



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 1987/भाद्र 7, 1909
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1987/BHADRA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रका मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि और स्याम मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987
सूचना

का. प्रा. 2210—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुभाष चन्द्र चौधरी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदाह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(45)/87-स्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th August, 1987

NOTICE

S.O. 2210—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under

787 GI/87—1

rule 4 of the said Rules, by Shri Subhash Chander Chaudhary Advocate for appointment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(45)/87-Judl.]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

सूचना

का. प्रा. 2211—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुरेश पाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे कैंपबे व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाये।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदाह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(46)/87-स्या.]

आर. एम. मोहम्मद, सक्षम प्राधिकारी

(2833)

New Delhi the 13th August, 1987

NOTICE

S.O. 2211.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule of the said Rules, by Shri Surinder Pal Sharma, Advocate or appointment as a Notary to practise in Kaithal.

2 Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(46)/87-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987

क्र. भा 2212.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हमें द्वारा गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्वास प्रभाग के अधीन बंदोबस्त बिग सहायक बंदोबस्त अधिकारी सर्व श्री साहिब राम और छबील दाम को उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रबंध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए उनके अपने कार्य भार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रबंध अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (6)/विशेष सैन/एम. एस.-II]

एम. असलम, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 15th July, 1987

S.O. 2212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Central Government hereby appoint S/Shri Sahib Ram and Chabil Dass, Assistant Settlement Officers in the Settlement Wing under the Rehabilitation Division of Ministry of Home Affairs, as Managing Officers in addition to their own duties, for the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(6)/Spl. Cell/87-SS.II]

M. ASLAM, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1987

घायकर

क्र. भा 2213.—इस कार्यालय की दिनांक 2-1-86 की अधिसूचना सं. 6554 (फा.सं. 203/30/85-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिाइन प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और शोधोपयोगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित सस्था को घायकर नियम 1962 के नियम 6 के तहत पंक्ति प्रारंभ अधिनियम 1961 की धारा 35 की

उपधारा (1) के तहत (II) (वेतन/एफ/डी) के प्रयोजन के लिए संगम प्रयोग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन किया है -

- (i) यह कि बाला मंदिर रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पुथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रस्प में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाधिक किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वस्तुओं द्वारा अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परि-संपत्तियों, देदारियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त की भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संख्या

"बाला मंदिर रिसर्च फाउन्डेशन, 126, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर मद्रास-600017"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7267/फा. सं. 203/60/87 आ.क.नि.-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st May, 1987

S.O. 2213.—In continuation of this Office Notification No. 6554 (F. No. 203/230/85-ITA. II) dated 2-1-1986 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five) One]Two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Bala Mandir Research Foundation, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Bala Mandir Research Foundation, 126, G. N. Chetty Road, T. Nagar, Madras-600017.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7267 (F. No. 203/60/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 2 जून, 1987

का. अ. 2214.—इस कार्यालय की दिनांक 4-4-84 की अधिसूचना सं. 5744 (फा. सं. 203/12/84-आ. क. नि. II) के तिलमिसे में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए 'संगम' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि महाराष्ट्र एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिशिष्ट वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र खर्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"महाराष्ट्र एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, मा. कालिज रोड, पुणे, 411004."

यह अधिसूचना 6-3-87 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[संख्या 7322 (फा. सं. 203/288/86-आ.क. नि-II)]

New Delhi, the 2nd June, 1987

S.O. 2214.—In continuation of this Office Notification No. 5744 (F. No. 203/12/84-ITA. II) dated 4-4-84 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority

for the purpose; of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Law College Road, Pune-411004.

This Notification is effective for a period from 6-3-87 to 31-3-90.

[No. 7322 (F. No. 203/288/86-ITA-II)]

का. अ. 2215.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि लेडी अनुसुयया मिहानिया मेडिकल रिसर्च सोसायटी, कोटा अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाये और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिशिष्ट वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राप्तिना पत्र रद्द कर दिया जाएगा :

संस्था

लैडी अनुसूया सिंघानिया मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, जे. के. नगर, कोटा 324003 राजस्थान”

यह अधिसूचना 5-5-87 से 31-3-89 तक प्रभावी है।

[सं. 7323/फा. सं. 203/57/87-भा. का. नि. -II]

S.O. 2215.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (thirty five/one/two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) That the Lady Anusuya Singhania Medical Research Society, Kota will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

ASSOCIATION

Lady Anusuya Singhania Medical Research Society, Jaykay Nagar, Kota-324003, Rajasthan.

This Notification is effective for a period from 5-5-87 to 31-3-89.

[No. 7323 (F. No. 203/57/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 8 जून, 1987

आयकर

का. भा. 2216—इसी कार्यालय की दिनांक 10-7-85 की अधिसूचना सं. 6306 (फा. सं. 203/205/85 भा. का. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ, पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए “संस्था” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि विवेकानन्द निधि, कलकत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरण बिहित प्राधिकारी को प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 मई तक ऐसे प्रत्येक में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय वसति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों वसति हुए तुल्य पत्र की एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक बिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा

- v) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और प्रविधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राप्तिना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“विवेकानन्द निधि, कलकत्ता”

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की प्रविधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7337 (फा. सं. 203/95/87-भा. का. नि.-II)]

New Delhi, the 8th June, 1987

S.O. 2216.—In continuation of this Office Notification No. 6306 (F. No. 203/205/85-ITA-II) dated 10-7-85 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Institution” subject to the following conditions:—

- (i) That the Vivekananda Nidhi, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Vivekananda Nidhi, Calcutta.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7337 (F. No. 203/95/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 11 जून, 1987

का.आ. 2217.—यह कार्यालय की दिनांक 29-5-86 की अधिसूचना सं. 6736 (फा. सं. 203/20/86 अ. का. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (i) यह कि एस.पी. रिसर्च इंस्टीट्यूट, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वंशति हुए अपने संपरिचित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देयदारियां वंशति हुए तुलन-पत्र का एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"एस.पी. रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, प्लॉट नं. 1 फास रोड नं. 2 मालाबा (वैस्ट) बम्बई-400064।

यह अधिसूचना 1-1-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7339 (फा. सं. 203/275/86-आ. का. नि.-II)]

New Delhi, the 11th June, 1987

S.O. 2217.—In continuation of this Office Notification No. 6736 (F. No. 203/220/86-ITA-II) dated 29-5-86 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax, Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax, Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Aspe Research Institute, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total

income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Aspe Research Institute, Adarsh Housing Society, Plot No. 1, Cross Road No. 2, Malad (West) Bombay-400064.

This Notification is effective for a period from 1-1-87 to 31-3-88

[No. 7339 (F. N. 203/275/86-ITA-II)]

का.आ. 2218.—यह कार्यालय की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:

- (i) यह कि आ. जी.एन. चक्रवर्ती होम्योपैथिक रिसर्च एण्ड फाउण्डेशन, हावड़ा अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वंशति हुए अपने संपरिचित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देयदारियां वंशति हुए तुलन-पत्र का एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"आ. जी.एन. चक्रवर्ती होम्योपैथिक रिसर्च सोसायटी एण्ड फाउण्डेशन 5, सुबल कनि लेन, हावड़ा-711 101।"

यह अधिसूचना 5-5-1981 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7340 (फा. सं. 203/23/86-आ. का. नि.-II)]

S.O. 2218.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax, Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax, Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Dr. B. N. Chakravorty, Homoeopathic Research Society and Foundation, Howrah will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Dr. B. N. Chakravorty Homoeopathic Research Society and Foundation 5, Subal Koley Lane, Howrah-711101.

This Notification is effective for a period from 5-5-87 to 31-3-88.

[No. 7340 (F. No. 203/23/86-ITA-II)]

का.आ. 2219—इस कार्यालय की दिनांक 26-9-85 की अधिसूचना सं. 6431 (फा.सं. 203/173/84-आ.क.नि.-II) के तलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (वैज्ञानिक/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए 'संगम' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि इण्डियन कैंसर सोसायटी, सोलापुर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वसति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमपत्तियां देनदारियां वसति हुए तुल्य-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली (राजस्व विभाग) नई दिल्ली की अनुमोदित संपत्ति से तीन माह पूर्व नई दिल्ली के लिए आवेदन करेगा।

करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"इण्डियन कैंसर सोसायटी, सोलापुर ब्रांच, 560/48 एस. सदार बाजार, सोलापुर 413003।"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 21-3-1988 तक की अधिधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7341 (फा.सं. 203/282/86-आ.क.नि.-II)]

S.O. 2219.—In continuation of this Office Notification No. 6431 (F. No. 203/173/84-ITA-II) dated 20-9-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Indian Cancer Society, Solapur will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That, the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Indian Cancer Society, Solapur Branch. 560/48, S. Sadar Bazar, Solapur-413 003.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7341 (F. No. 203/282/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 12 जून, 1987

का.आ. 2220—इस कार्यालय की दिनांक 19-11-85 की अधिसूचना की संख्या 6478 (फा.सं. 203/67/85-आ.क.नि.-II) के तलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (वैज्ञानिक/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए 'संगम' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :

- (i) यह कि न्यूट्रीशन्ट सोसायटी आफ इंडिया, हैदराबाद अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(i) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी विषय कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियां दर्शाने हुए तुलनपत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था,

"न्यूट्रिशन सोसायटी ऑफ इण्डिया [मार्फत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ—
न्यूट्रिशन, जामाए उस्मानिया हैदराबाद-500007]"।

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7344 (का. सं. 203/166/86-आ.क.नि.-II)]

New Delhi, the 12th June, 1987

S.O. 2220.—In continuation of this Office Notification No. 6478 (F. No. 203/67/85-ITA-II) dated 19-11-1985 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) That the Nutrition Society of India, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for its extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Nutrition Society of India, C/o National Institute of Nutrition, Jamai Osmania, Hyderabad-500 007.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990

[No. 7344 (F. No. 203/166/86-ITA-II)]

का. सं. 2221.—इस कार्यालय की दिनांक 21-7-86 की अधिसूचना सं. 6820 (का. सं. 203/89/86 आ. क. नि.-II) के निम्नलिखित में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन किया है:—

(i) यह कि सोसायटी फॉर रिसर्च आन हीमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजियन, कलकत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियां दर्शाने हुए तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सोसायटी फॉर रिसर्च आन हीमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजियन, 75-मी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता; 700016"।

यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7342 (का. सं. 203/21/87 आ.क. नि.-II)]

S.O. 2221.—In continuation of this Office Notification No. 6820 (F. No. 203/89/86-ITA-II) dated 21-7-86. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

(i) That the Society for Research on Haematology and Blood Transfusion, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of

their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets and liabilities, with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Society for Research on Haematology and Blood Transfusion, 75-C, Parkstreet, Calcutta-700016.

This Notification is effective for a period from 1-4-87 to 31-3-90.

[No. 7342 (F. No. 203/21/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 18 जून, 1987

आयकर

का. प्रा. 2222—इस कार्यालय की दिनांक 11-3-86 की अधिसूचना सं. 6616 (का. सं. 203/47/86 आ. क. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (वैसीस (एक)/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दस्तवेजों में अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देवदारियों दस्तवेजों द्वारा तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथमिकता खारिज कर दिया जाएगा।

संस्था

"नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च पारिसिला भवन, 11, इन्द्रप्रस्था एस्टेट नई दिल्ली 110002"।

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7351 (का. सं. 203/8/87 आ. क. नि.-II)]

New Delhi, the 18th June, 1987

S.O. 2222.—In continuation of this Office Notification No. 6616 (F. No. 203/47/86-ITA-II) date 11-3-86, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions—

- (i) That the National Council of Applied Economic Research, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

National Council of Applied Economic Research, Parisila Bhavan, 11, Indraprastha Estate, New Delhi-110002.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7351 (F. No. 203/8/87-ITA-II)]

का. प्रा. 2223—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (वैसीस (एक)/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि महाराष्ट्र ग्रंथोत्प्रेषक संस्था, पुणे, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मार्च तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दस्तवेजों में अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देवदारियों दस्तवेजों द्वारा तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन

प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थान 1133, सदाशिव पेथ पुणे-411030।

यह अधिसूचना 17-2-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7350 (फा. सं. 203/140/85-प्रा. फा. नि. II)]

S.O. 223.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Maharashtra Granthotejak Santha, Pune, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Mahaarashtra Granthotejak Sanstha, 1133, Sadashiv Peth, Pune-411030.

This Notification is effective for a period from 17-2-1987 to 31-3-1988.

[No. 7350 (F. No. 203/140/85-ITA-II)]

फा. प्रा. 2224—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनड्वारा अधिसूचित किया जाना है कि बिल्डि प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पेतीस एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि कर्नाटक स्टेट सेरीकल्चर डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, बंगलूर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, बिल्डि प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

787 GI/87—2.

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संयोजित वार्षिक लेखों का तथा अपनी परिवर्तित, देनदारियों दर्शाते हुए न्यूनतम-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक बिल्डि प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त "संगम" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

कर्नाटक स्टेट सेरीकल्चर डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, थालावट्टापुरा, बंगलूर-560062।

यह अधिसूचना 27-4-87 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7353 (फा. सं. 203/140/86-प्रा. फा. नि.-II)]

S.O. 2224.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Karnataka State Sericulture Development Institute, Bangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Karnataka State Sericulture Development Institute, Thalaghattapura, Bangalore-560062.

This Notification is effective for a period from 27-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7353 (F. No. 203/140/86-ITA-II)]

का.सं. 2225—इस कार्यालय की दिनांक 16-4-1986 की अधिसूचना सं. 6665 (फा.सं. 203/72/86-आ.क.नि.-II) के निम्नलिखित में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इण्डिया, मद्रास अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियां का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देवदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इण्डिया, वसंत विहार, 64-65 ग्रीनवेज रोड, मद्रास-600028.

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7349 (फा.सं. 203/93/87-आ.क.नि. II)]

S.O. 2225.—In continuation of this Office Notification No. 6665 (F. No. 203/72/86-ITA. II) dated 16-4-1986, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) That the Krishnamurti Foundation India, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its

assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Krishnamurti Foundation India, Vasant Vihar, 64-65, Greenways Road, Madras-600 028.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7349 (F. No. 203/93/87-ITA-II)]

का.सं. 2226—इस कार्यालय की दिनांक 6-6-1985 की अधिसूचना सं. 6244 (फा.सं. 203/20/85-आ.क.नि.-II) के निम्नलिखित में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "कालिज" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि राम निरंजन जून्जुनवाला कालिज, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त कालिज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त कालिज अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देवदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त कालिज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

राम निरंजन जून्जुनवाला कालिज, रेल्वे स्टेशन के सामने, घाटकोपर (वैस्ट), बम्बई 400086।

यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7352 (फा.सं. 203/94/87-आ.क.नि. II)]

S.O. 2226.—In continuation of this Office Notification No. 6244 (F. No. 203/20/85-ITA. II) dated 6-6-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "College" subject to the following conditions:—

- (i) That the Ramniranjan Jhunjhunwala College, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

- (ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st may each year
- (iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said College will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Ramniranjan Thunhunwala College, App. Railway Station, Ghatkopar (West), Bombay-400 086.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7352 (F. No. 203/94/87-ITA-II)]

का.भा. 2227.—इस कार्यालय की दिनांक 19-9-85 की अधिसूचना सं. 6427 (फा.सं. 203/41/85-आ.क.नि.-II) के मिलसिले से, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रबंध के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है --

- (i) यह कि द बांद्रा होली फेमिली मेडिकल रिसर्च सोसायटी, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो हत प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

द बांद्रा होली फेमिली मेडिकल रिसर्च सोसायटी सेट एण्ड्रू रोड, बांद्रा, बम्बई-400050.

यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7354 (फा.सं. 203/5/87-आ.क.नि. II)]

S.O. 2227.—In continuation of this Office Notification No. 6427 (F. No. 203/41/85-ITA-II) dated 19-9-85. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Bandra Holy Family Medical Research Society, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st may each year
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

The Bandra Holy Family Medical Research Society, St. Andrew Road, Bandra, Bombay-400 050.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7354 (F. No. 203/5/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 22 जून, 1987

का.भा. 2228.—इस कार्यालय की दिनांक 7-5-85 की अधिसूचना सं. 6212 (फा.सं. 203/72/85-आ.क.नि. II) के मिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रबंध के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् --

- (i) यह कि मालम्बा हान्स रिचर्व सेंटर, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"नालन्दा डांस रिसर्च सेंटर, प्लॉट नं. ए-7/1, एन.एस. रोड नं. 10, जे.वी.पी.ओ. स्कीम, विले पार्ले (वैस्ट), बम्बई-400049"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अधि-सि लिए प्रभावी है।

[सं. 7361 (फा.सं. 203/74/87-आ.क.नि. II)]

New Delhi, the 22nd June, 1987

S.O. 2228.—In continuation of the Office Notification No. 12 (F. No. 203/72/85-ITA. II) dated 7-5-85, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Nalanda Dance Research Centre, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Nalanda Dance Research Centre, Plot No. A-7/1, N.S. Road, No. 10, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West) Bombay-400 049.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7361 (F. No. 203/74/87-ITA-II)]

का.आ. 2229.—इस कार्यालय की दिनांक 3-9-85 की अधिसूचना सं. 6402 (फा.सं. 203/2/85-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा

- (1) के खंड (iii) पेटिस (ए) तीन के प्रयोजनों के "संस्था" प्रभाव के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (i) यह कि इण्टरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इण्डिया, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रस्व में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिव्यवस्थित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने वार्षिक वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुल्य-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

इण्टरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इण्डिया, 9-ए, फेल्ल्स बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001.

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अधि-सि लिए प्रभावी है।

[सं. 7362 (फा.सं. 203/55/87-आ.क.नि. II)]

S.O. 2229.—In continuation of this Office Notification No. 6402 (F. No. 203/2/85-ITA. II) dated 3-9-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the International Management Institute India, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

International Management Institute India, 9-A, Phelps Building, Connaught Circus, New Delhi-110001.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7362 (F. No. 203/55/87-ITA-JF)]

का. भा. 2230.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि फाउण्डेशन फॉर कॉइल वाइंडिंग टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त 'संगम' अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुल्य-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त 'संगम' केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"फाउण्डेशन फॉर कॉइल वाइंडिंग टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, प्लॉट, नं. सी-5-12(19) भोसरी इण्डस्ट्रीज एरिया, पोस्ट ऑफिस के पीछे, पुणे"

यह अधिसूचना 8-6-87 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7359 (फा. सं. 203/91/87-अ. क. नि. II)]

S.O. 2230.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five) One/two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Foundation for Coil Winding Technology and Research, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) hat the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Foundation for Coil Winding Technology and Research (Plot No. C-5-12(19) Bhosari Industrial Area, Behind Post Office Pune-411026.

This Notification is effective for a period from 8-6-87 to 31-3-89.

[No. 7359 (F. No. 203/91/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 22 जून 1987

आयकर

का. भा. 2231.—इस कार्यालय की दिनांक 31-3-84 की अधिसूचना सं. 5735 (फा. सं. 203/70/84 भा. क. नि.-II) के मिलसिमे में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुल्य-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, जे. एन. यू. कैम्पस, गहोब जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110067."

यह अधिसूचना 14-9-1986 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7357 (फा. सं. 203/49/87-भा. क. नि.-II)]

S.O. 2231.—In continuation of this Office Notification No. 5735 (F. No. 203/70/84-ITA II) dated 31-3-84, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) That the National Institute of Immunology, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will furnish annual returns Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

National Institute of Immunology, INU Campus, Shahid Jeeb Singh Marg, New Delhi-110067.

This Notification is effective for a period from 14-9-1986 to 31-3-1989.

[No. 7357 (F. No. 203/49/87-ITA-II)]

का. प्रा. 2232.—इस कार्यालय की दिनांक 19-11-1985 की अधिसूचना सं. 6499 (फा. सं. 203/153/85—प्रा. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) (पैमीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :-

- (1) यह कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राजियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो हम प्रयोजनों के लिए अधिकतम किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेतनशर्तियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून, तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्त

से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देर होने पर आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, 1008, नई दिल्ली हाउस, 27, बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली—110001"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7356 (फा. सं. 203/297/86-प्रा. क. नि.-II)]

S.O. 2232.—In continuation of this Office Notification No. 6499 (F. No. 203/153/85-ITA II) dated 19-11-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category

"Institution" subject to the following conditions :-

- (i) That the Petroleum Conservation Research Association, New Delhi, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Petroleum Conservation Research Association, 1008, New Delhi House, 27, Bara Khamba Road, New Delhi-110001.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7356 (F. No. 203/297/86-ITA-II)]

का. प्रा. 2233.—इस कार्यालय की दिनांक 15-11-84 की अधिसूचना सं. 6036 (फा. सं. 203/21/84—प्रा. क. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) (पैमीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :-

- (1) यह कि एन्थ्रोपेटिड एप्रोक्लरेशन डिवेलपमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राजियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिस्थित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिस्थितियों, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(1) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रायतना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"एग्रीकल्चरल एंटीकल्चरल डेवेलपमेंट फाउंडेशन, 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065,"

यह अधिपूचना 1-1-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7358 (फा. सं. 203/31/87-आ. क. नि. --II)]

S.O. 2233.—In continuation of this Office Notification No. 6036 (F. No. 203/2/84-ITA II) dated 15-11-84, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) That the Associated Agricultural Development Foundation, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Associated Agricultural Development Foundation, 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7358 (F. No. 203/31/87-ITA-II)]

नोट. आ. 2234 --इस कार्यालय की दिनांक 13-12-85 की अधिपूचना सं. 6530 (फा. सं. 203/115/85-आ. क. नि.--II) के निम्नलिखित में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-

कर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित भाषाकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैकिंग/एक/दो) के प्रयोजन के लिए "संस्था" पद का उपयोग करने के लिए अनुमोदित किया है --

(1) यह कि द. कर्नाटक कैंसर थेरापी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाटक अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरण, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से प्रति वर्ष 30 मई तक ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिस्थित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिस्थितियों, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की ममाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रायतना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"द कर्नाटक कैंसर थेरापी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाशानगर, हुबली, कर्नाटक-580025"

यह अधिपूचना 1-1-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7360 (फा. सं. 203/75/87-आ. क. नि.--II)]

S.O. 2234.—In continuation of this Office Notification No. 6530 (F. No. 203/115/85-ITA II) dated 13-12-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

(i) That the Karnataka Cancer Therapy And Research Institute, Karnataka, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

The Karnataka Cancer Therapy And Research Institute,
Navanagai, Hubli, Karnataka-580025.

This Notification is effective for a period from 1-1-1987
to 31-3-1989.

[No. 7360 (F. No. 203/75/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 26 जून, 1987

का.आ. 2235—इस कार्यालय की दिनांक की अधिसूचना सं 6411 का सं 203/105/85-आ.क.नि.-II के सिलसिले में, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतीम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :

- (1) यह कि विज्ञान रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाएगा।
- (3) यह कि उक्त "संगम" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संरक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों वगैरहें हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली, को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"विज्ञान रिसर्च फाउण्डेशन, 18 कालिदास रोड, मद्रास"।

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7370 (फा. सं. 203/12/87-आ.क.नि.-II)]

New Delhi, the 26th June, 1987

S.O. 2235.—In continuation of this Office Notification No. 6411 (F. No. 203/105/85-ITA. II) dated It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Vision Research Foundation, Madras, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said "Association" will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) That the said "Association" will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said "Association" will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Vision Research Foundation, 18 College Road, Madras.

This Notification is effective for a period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988.

[No. 7370 (F. No. 203/12/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

का.आ. 2236—इस कार्यालय की दिनांक की अधिसूचना सं. 6758 (फा. सं. 203/84/86-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) (i) के खंड (2) (पैतीम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज त्रिवेन्द्रम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संरक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों वगैरहें हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, प्रककुलम, पल्लिकल पो. ओ. त्रिवेन्द्रम-595031"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7372 (फा. सं. 203/301/86-आ.क.नि.-II)]

New Delhi, the 29th June, 1987

S.O. 2236.—In continuation of this Office Notification No. 6758 (F. No. 203/84/86-ITA, II) dated 17-6-86, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Centre for Earth Science Studies, Trivandrum will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Centre for Earth Science Studies, Akkulam, Thiruvikkal P O., Trivandrum-695031.

This Notification is effective for a period from 1st April, 1987 to 31st March, 1989.

[No. 7372 (F. No. 203/301/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

का. भा. 2237—इस कार्यालय की दिनांक 14-7-86 की अधिसूचना सं 6797 (फा. सं. 203/156/85—आ. क. नि.—II) के मिलाने में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैस/एक/वो) के प्रयोजनों के लिए "संगम प्रवाह" के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि बकुल फाइनकेम रिसर्च सेंटर, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियाँ का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणों विहित, प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्जो हुए प्रपत्र परीक्षित वार्षिक लेखा का तथा प्राप्त पर्याप्तता, संतुष्टता दर्शाते हुए, मुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो तथा इन दस्तावेजों से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा सर्वोच्च आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय पत्रिका कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन को सहायिता से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने से किसी प्रकार का देर होना पर प्रावधान-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"बकुल फाइनकेम रिसर्च सेंटर, स्टर्लिंग सेंटर, 4th फ्लोर 4th, डॉ. एनी बेसन्ट रोड, बम्बई-400018"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की प्राप्ति के लिए प्रभावी है।

[सं. 7371 (फा. सं. 203/302/86-ITA-II)]

New Delhi, the 29th June, 1987

S.O. 2237.—In continuation of this Office Notification No. 6797 (F. No. 203/156/85-ITA II) dated 14-7-86, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Bakul Finechem Research Centre, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Bakul Finechem Research Centre, Sterling Centre, 4th Floor, Dr. Annie Besant Road, W-18, Bombay-400018.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1989.

[No. 7371 (F. No. 203/302/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

का. भा. 2238—इस कार्यालय की दिनांक 4-7-86 की अधिसूचना सं 6814 (203/109/86—आ. क. नि.—II) के मिलाने में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैस/एक/वो) के प्रयोजनों के लिए "संगम प्रवाह" के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्स रिसर्च आक अडिया, वैदगावद अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियाँ का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकांकित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने मंगरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमपत्तियां, देनदागियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की मभापति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, बेला विस्ता, हैदराबाद 500049,"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक का अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7390 (फा सं 203/111/86--आ क. नि.--II)]

New Delhi, the 30th June, 1987

S.O. 2238—In continuation of this Office Notification No. 6144 (F. No. 203/109/84-ITA II) dated 4-2-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- That the Administrative Staff College of India, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Administrative Staff College of India, Bella Vista Hyderabad-500049.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990

[No. 7390 (F No 203/111/86-ITA-II)]

का. आ. 2239:—इस कार्यालय की दिनांक 24-3-1986 को अधिसूचना सं 6630 (फा. सं. 203/246/84--आ. क. नि. II) के मिलान में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैतीस/एक/तीन) के प्रयोजन के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

(1) यह कि श्री अरविन्दो इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तमिलनाडु अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकांकित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने मंगरीक्षित वार्षिक लेखों का तथा अपनी परिमपत्तियां, देनदागियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की मभापति से तीन माह पूर्व और अधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"श्री अरविन्दो इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अरविल्ले, कोट्टाक्पम, तमिलनाडु-605104"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7389 (फा सं 203/105/86--आ क. नि.--II)]

S.O. 2239.—In continuation of this Office Notification No. 6630 (F. No. 203/246/84-ITA II) dated 24-3-86, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- That the Sri Aurobindo International Institute of Educational Research, Tamil Nadu will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Sri Aurobindo International Institute of Educational Research, Auroville, Kottakuppam, Tamil Nadu-605104

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7389 (F. No. 203/305/86-ITA-II)]

का. प्र. 2240.—इस कार्यालय की दिनांक 16-10-86 की अधिसूचना सं. 6970 (फा. ग. 203/209/86—आ. क. नि. - II) के निम्नलिखित में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) (वैज्ञानिक/एन/सी) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रयोग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है —

- (1) यह कि डायबेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाएगा और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिमपत्तियां, दस्तावेजों दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समिति में तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"डायबेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, माणिक जोवाडिया बिल्डिंग, प्रथम तल, 127, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई—400016"

यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-88 तक क. प्रवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7379 (फा. स. 203/88/87—आ. क. नि. - II)]

S.O. 2240.—In continuation of this Office Notification No. 6970 (F. No. 203/209/86-ITA II) dated 16-10-86, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) That the Diabetic Association of India, Bombay will maintain a separate account of the sum, received by it for scientific research.

- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

- (i) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax

- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Diabetic Association of India, Maneckji Wadia Building, 1st Floor, 127, Mahatma Gandhi Road, Fort, Bombay-400016.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7379 (F. No. 203/88/87 ITA II)]

का. प्र. 2241.—इस कार्यालय की दिनांक 7-6-1986 की अधिसूचना सं. 6251 (फा. सं. 203/214/84—आ. क. नि. - II) के निम्नलिखित में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) (वैज्ञानिक/एन/सी) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रयोग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

- (i) यह कि श्रीमती लक्ष्मी गोविन्दभाई मिश्रा मेडिकल रिसर्च भंडाल (गुजरात) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

- (ii) यह कि उक्त संस्था परा वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (ii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिमपत्तियां, दस्तावेजों दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (v) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली का अनुमोदन की समिति में तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"श्रीमती लामुबेन गोविन्दभाई मिस्ट्री मेडिकल रिसर्च सोसायटी,
श्री फलश्रुति नगर, (एम टी डिपो के पीछे), भड़ोच,
गुजरात-392001"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 7380 (फा.स. 203/17/86-आ.क.नि.-II)]
ई. के. बत्रा, अवर सचिव

S.O. 2241.—In continuation of this Office Notification No. 6254 (F. No. 203/244/84-ITA. II) dated 7-6-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Smt. Labhuben Govindbhai Mistry Medical Research Society, Bharuch (Gujarat) will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Smt. Labhuben Govindbhai Mistry Medical Research Society, Shree Falshruiti Nagar, Opp. S. T. Depot, Bharuch, Gujarat-392001.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-89.

[No. 7380 (F. No. 203/17/86-ITA-II)]

Y. K. BATRA, Under Secy.

का. आ. 2242.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 13-1-1975 की अधिसूचना सं. 816 (फा. सं. 203/65/74-आ. क. नि.-II) द्वारा गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, मद्रुरै (जिसे पहले गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली प्लानिंग, मद्रुरै डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के नाम से जाना जाता था) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(i) (ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31-3-1990 तक सीमित किया जाता है :—

- (1) यह कि गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, मद्रुरै अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय वसति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां, वेनदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व भागे अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

[स. 7381 (फा. सं. 203/110/87-आ. क. नि.-II)]

S.O. 2242.—It is hereby notified for general information that the approval granted under section 35 (i)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to the Gandhi Gram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust, Madurai (formerly known as The Gandhigram Institute of Rural Health and Family Planning, Madurai District, Tamil Nadu) vide Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 816 (F. No. 203/65/74-ITA. II) dated 13th January, 1975, is hereby restricted upto 31st March, 1990 subject to the following conditions :—

- (i) That the Gandhi Gram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust, Madurai will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

[No. 7381 (F. No. 203/110/87-ITA. II)]

का. आ. 2243.—इस कार्यालय की दिनांक 4-9-85 की अधिसूचना सं. 6404 (फा. सं. 203/104/85-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित "संस्था" को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) पैरिस / एक / तीन के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (1) यह कि गांधी लेबर इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के गबध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिक्थित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संरोक्षित वार्षिक लेखा की तथा अपनी परिमपतियां, वेनवारियां दशति हुए मुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"गान्धी लेबर इंस्टीट्यूट थलतेज राड, अहमदाबाद-380062"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 7377 (फा. सं. 203/2/87-आ. का. नि.-I)]

New Delhi, the 30th June, 1987

S.O. 2243.—In continuation of this Office Notification No. 6404 (F. No. 203/104/85-ITA. II) dated 4-9-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Gandhi Labour Institute, Ahmedabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Gandhi Labour Institute, Thaltej Road, Ahmedabad-380062

This Notification is effective for a period from 1st April, 1987 to 31st March, 1988.

[No. 7377 (F. No. 203/2/87-ITA-II)]

का. आ. 2244—इस कार्यालय की दिनांक 26-6-85 की अधिसूचना सं. 6290 फा. सं. 303/38/85-का. आ. नि. II के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है

कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजन के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि सेंटर फॉर रीजनल इकोलॉजिकल एण्ड साइंस स्टडीज इन डिवेलपमेंट आल्टरनेटिव्स, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त "संस्थान" अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजनाधी अधिक्थित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संरोक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमपतियां, वेनवारियां दशति हुए मुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त "संस्थान" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सेटर फॉर रीजनल इकोलॉजिकल एण्ड साइंस स्टडीज इन डिवेलपमेंट आल्टरनेटिव्स, चतुर्थ फ्लेट नं. 3, 32, गोबिन्दा ब्राह्मी रोड, कलकत्ता-700027"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7378 (फा. सं. 203/111/87-आ. का. नि.-II)]

S.O. 2244.—In continuation of this Office Notification No. 6290 (F. No. 203/88/85-ITA-II) dated 26-6-85, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Centre for Regional Ecological and Science Studies in Development Alternatives, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department

of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Centre for Regional Ecological and Science Studies in Development Alternatives Calcutta, Chaturanga, Flat No. 3, 32, Gohinda Auddy Road, Calcutta-700027.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7378 (F. No. 203/111/87-ITA-I)]

का० आ० 2245—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैलीम/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :-

- (i) यह कि एफ.आई.ए.एम.सी. बायो-मेडिकल एथिक्स सेंटर, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां, देनदारियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"एफ.आई.ए.एम.सी. बायो-मेडिकल एथिक्स सेंटर, सेट पायसएसएम कॉलेज, आरे रोड, गॉर्गाँव ईस्ट बम्बई-400 063"।

यह अधिसूचना 8-6-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 7375 (फा. सं. 203/42/87-प्रा.क.नि.-II)]

S.O. 2245.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the F.I.A.M.C. Bio-Medical Ethics Centre, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

F.I.A.M.C. Bio-Medical Ethics Centre, St. Pius X College, Aarey Road, Goregaon East, Bombay 400063.

This Notification is effective for a period from 8-6-1987 to 31-3-1989.

[No. 7375 (F. No. 203/42/87-ITA-II)]

का० आ० 2246—इस कार्यालय की दिनांक 8-1-85 की अधिसूचना सं० 6099 (फा० सं० 203/126/84-प्रा.क.नि.-II) के मिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैलीम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

- (i) यह कि इन्वैस्टिगल रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट एसोसिएशन, बड़ोदरा अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां, देनदारियां दर्शाने हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"इन्वैस्टिगल रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट एसोसिएशन, पी.बी.नं. 760, मकड़पुरा इण्डस्ट्रियल स्टेट पी ओ एच.बी.बी. गैस्ट हाऊस के पास, एन.एच.नं. 8, बड़ोदरा-390010."

यह अधिसूचना 1-1-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7379 (फा. सं. 203/112/87-प्रा.क.नि.-II)]

S.O. 2246.—In continuation of this Office Notification No. 6099 (F. No. 203/126/84-ITA-II) dated 8-1-85. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Electrical Research and Development Association, Vadodara will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Electrical Research and Development Association, P.B. No. 760, Maharashtra Industrial Estate, P.O. Near P.E.E. Guest House N.H. No. B, Vadodara-390010.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No 7379 (F. No 203/112/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1987

का.आ. 2247—इस कार्यालय की दिनांक 23-1-86 की अधिसूचना सं. 6579 (फा. सं. 203/225/86-आ.क.नि. II) के मितसिरे में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रकार के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि पूर्ण मेडिकल रिसर्च सोसायटी, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक उसे प्रेषण में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वार्षिक रूप से अपने संवरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिस्पत्तियां देनदारियों दर्शाते हुए तदनंतर की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रतिलिपि प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा आयकर अधिकार शासन को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नई दिल्ली को अनुमोदन की गमाप्ति में तीन माह पूर्व और अधिक वरदान के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का देरी होने पर प्राप्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"पूर्ण मेडिकल रिसर्च सोसायटी, 21, सदाशिव पथ, पुणे-411030"
यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-87 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[नं. 7391 (फा. सं. 203/48/87-आ.क.नि. II)]

New Delhi, the 1st July, 1987

S.O. 2247.—In continuation of this Office Notification No. 6579 (F. No. 203/225/85-ITA-II) dated 23-1-86. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five /One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Pune Medical Research Society, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Pune Medical Research Society, 27, Sadashiv Peth, Pune-411030

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988

[No 7391 (F. No 203/48/87-ITA-II)]

का.आ. 2247—इस कार्यालय की दिनांक 1-7-87 अधिसूचना सं. 6799 (फा. सं. 203/30/87-आ.क.नि. II) के मितसिरे में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रकार के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि उक्त विज्ञान मेडल सोसायटी हेल्थ फाउण्डेशन, इन्फरमिटी में मेडिकल शोधार्थियों के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय

वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (iii) यह कि उक्त "संगम" अपनी कुल आय तथा व्यय वशति हुए अपने गपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां, वशति हुए तुलन-पत्र को एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति में तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"डॉ० जिवराज मेहता स्मारक हेल्थ फाउण्डेशन आरोग्यधाम, आयोजनगर के पास अहमदाबाद-880007.

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7396 (फा. सं. 203/51/87-आ.क.नि.-II)]

S.O. 2248.—In continuation of this Office Notification No. 6799 (F. No. 203/30/86-ITA-II) dated 14-7-86. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- That the Dr. Jivraj Mehta Smarak Health Foundation, Ahmedabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Dr. Jivraj Mehta Smarak Health Foundations, Arogyadham, Near Avojanagar, Ahmedabad 380007.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7396 (F. No. 203/51/87-ITA-II)]

का० आ० 2219—इस कार्यालय की दिनांक 20-3-86 की अधिसूचना सं० 6626 (फा० सं० 203/193/85-आ०क०नि०-II) के सिद्धांतों में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी यशवि वैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम

1962 के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (1) (पैराम/एक/दो) के प्रयोजन के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- यह कि महाराष्ट्र राज्य द्राक्षा बगायनदार संघ, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों को वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- यह कि उक्त "संस्थान" अपनी कुल आय तथा व्यय वशति हुए अपने गपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपना परिसंपत्तियां, देनदारियां वशति हुए तुलन-पत्र को एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारों को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति में तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"महाराष्ट्र राज्य द्राक्षा बगायनदार संघ, द्राक्षा भवन, ई/4, मॉडिटर याई, मुल्तेकड़ी, पुणे-411037"।

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 7394 (फा० सं० 203/237/86-आ०क०नि०-II)]

वाई० के० बल्ला, प्रवर सचिव

S.O. 2249.—In continuation of this Office Notification No. 6626, (F. No. 203/193/85-ITA-II) dated 20-3-86. It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- That the Maharashtra Rajya Draksha Bagaitdar Sangha, Pune, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

before the expiry of the approval for further extension. Application is received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Maharashtra Rajya Draksha Bagatdar Sangha, Draksha Bhavan, E/4, Market Yard, Gulikadi, Pune-411037.

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1988.

[No. 7394 (F. No. 203/237/86-ITA-II)]
Y. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मई, 1987

आयकर

क्रा. प्रा. 2250—इस कार्यालय की दिनांक 31-7-84 की अधिसूचना सं. 5917 (फा. सं. 203/25/84-मा. क. नि. II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैतिस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि युनिवर्सिटी डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों को वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष, 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संवर्धित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन पत्र को एक एक प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"यूनिवर्सिटी डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 46-ए, फेज-1 (एम.आई.जी.) सेक्युलर, मा. बंधु नगर, नई दिल्ली-110077"

यह अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7308 (फा. सं. 203/3/87-मा. क. नि. II)]

Department of Revenue

New Delhi, the 20th May, 1987

INCOME-TAX

S.O. 2250.—In continuation of this Office Notification No. 5917 (F. No. 203/25/84-ITA-II) dated 31-7-84 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read 787 GI/87—4

rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the Universal Digital Communication Research Institute, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Universal Digital Communication Research Institute, 46-A, Phase-I (MIG) Seikhsarai, Malviya Nagar, New Delhi-110077."

This Notification is effective for a period from 1-4-87 to 31-3-89.

[No. 7308 (F. No. 203/3/87-ITA II)]

क्रा. प्रा. 2251—इस कार्यालय की दिनांक 23-1-84 की अधिसूचना सं. 5599 (फा. सं. 203/114/82-मा. क. नि. II) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैतिस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि सेंट्रल फार एंडीज इन डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों को वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संवर्धित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“सेंटर फॉर स्टडीज इन डिसेंट्रलाइज्ड इण्डस्ट्रीज बम्बई”

यह अधिसूचना 16-7-86 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7306 (फा. सं. 203/9/86-भा. क. नि.-II)]

S.O. 2251.—In continuation of this Office Notification No. 5599 (F. No. 203/114/82-ITA.II) dated 23-1-84 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the income-tax Rules, 1962 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) That the Centre for Studies in Decentralised Industries, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

“Centre for Studies in Decentralised Industries, Bombay.”

This Notification is effective for a period from 16-7-86 to 31-3-88.

[No. 7306 (F. No. 203/9/86-ITA.II)]

का. घा. 2252.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अर्थात् निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि सेंटर फॉर स्टडीज आफ मैन एण्ड एन्वायरन्मेंट, कलकत्ता, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हफ्ते अपने संवरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी पति-संपत्तियां, देनदारियां दशति हफ्ते तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय

प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त सहायक (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समिति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथना पत्र खूब कर बिना जाएगा।

संस्था

“सेंटर फॉर स्टडीज आफ मैन एण्ड एन्वायरन्मेंट, डिपार्टमेंट आफ जिग्रानाजि, प्रेजिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता-700073”

यह अधिसूचना 28-2-87 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7307 (फा. सं. 203/200/85-भा. क. नि.-II)]

S.O. 2252.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) That the Centre for Study of Man and Environment, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

“Centre for Study of Man and Environment Department of Geology, Presidency College, Calcutta-700073.”

This Notification is effective for a period from 28-2-87 to 31-3-89.

[No. 7307 (F. No. 203/200/85-ITA-II)]

नई दिल्ली, 21 मई 1987

का. घा. 2253.—इस कार्यालय की दिनांक 15-11-84 की अधिसूचना सं. 6430 (फा. सं. 203/192/84-भा. क. नि II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैरोस/एक/तीन) के प्रयोजनों के

लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

नई दिल्ली, 22 मई, 1987

- (i) यह कि सेंटर फार वूमैन्स डिवेलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई, तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां, दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून, तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथमता-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सेंटर फार वूमैन्स डिवेलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-90 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7309 (फा. सं. 203/112/86-आ. क. नि.-II)]

S.O. 2253.—In continuation of this Office Notification No. 6034 (F. No. 203/192/84-ITA.II) dated 15-11-84 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Centre for Women's Development Studies, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Centre for Women's Development Studies, New Delhi."

This Notification is effective for a period from 1-4-87 to 31-3-90.

[No. 7309 (F. No. 203/112/86-ITA-II)]

या. आ. 2254.—इस कार्यालय की तिनांक 6-6-85 की अधिसूचना सं. 6243 (फा. सं. 203/14/85-आ.क.नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित जाकर प्रविनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (तीस/एक/तीन) के प्रभावों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

- (i) यह कि जन.न. प्रबोधिनी संशोधन संस्था, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई, तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां, दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व-विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राथमता-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"जन.न. प्रबोधिनी संशोधन संस्था, पुणे"

यह अधिसूचना 1-4-1987 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7310 (फा. सं. 203/257/86-आ.क.नि.-II)]

New Delhi, the 22nd May, 1987

S.O. 2254.—In continuation of this Office Notification No. 6243 (F. No. 203/14/85-ITA.II) dated 6-6-85 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Jnana Prabodhini Samshodhan Sanstha, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Jnana Prabodhini Samshodhan Sanstha, Pune."

This Notification is effective for a period from 1-4-1987 to 31-3-1990.

[No. 7310 (F. No. 203/257/86-ITA.II)]

नई दिल्ली, 2 जून, 1987

का. धा. 2255:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) (पैरोस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- यह कि वि एसोसिएशन फार द वेल्फेयर ऑफ परसन्स विथ ए मेंटल हैंडिकैप इन महाराष्ट्र, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणों विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेनदारियां दर्शाते हुए तुलनात्मक की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"द एसोसिएशन फार द वेल्फेयर ऑफ परसन्स विथ ए मेंटल हैंडिकैप इन महाराष्ट्र, टर्नर मोरिसन हाउस (बेसमेंट) 16 बैंक स्ट्रीट, बम्बई-400023"

यह अधिसूचना 28-2-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7321 (फा. सं. 203/13/87-आ. व. नि.-II)]

New Delhi, the 2nd June, 1987

S.O. 2255.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five) One three of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- That The Association for the Welfare of Persons with a Mental Handicap in Maharashtra, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

- That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.

- That the said institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"The Association for the Welfare of Persons with a Mental Handicap in Maharashtra, Turner Morrison House (Basement), 16, Bank Street, Bombay-400023."

This Notification is effective for a period from 28-2-87 to 31-3-88.

[No. 7321 (F. No. 203/13/87-ITA.II)]

का. धा. 2256:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- यह कि श्री अरविन्द इस्टीम्यूट ऑफ एप्पाइड साइंटिफिक रिसर्च, पाण्डिचेरी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेनदारियां दर्शाते हुए तुलनात्मक की एक-एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"श्री अरविन्द इस्टीम्यूट ऑफ एप्पाइड साइंटिफिक रिसर्च प्रकाशनी हाऊस, 12, मारवाडी स्ट्रीट, पम्पिनो नगर, पाण्डिचेरी-605012"

यह अधिसूचना 27-2-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7320 (फा. सं. 203/33/86-आ. व. नि.-II)]

धार. एन. बर्मा, उपसचिव

S.O. 2256.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Sri Aurobindo Institute of Applied Scientific Research, Pondicherry will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Sri Aurobindo Institute of Applied Scientific Research Academy House, 12, Marvadi Street, Padmini Nagar, Pondicherry-605012."

This Notification is effect for a period from 27-4-87 to 31-3-88.

[No. 7320/F. No. 203/33/86-ITA-II]
R. N. VERMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 1987

आयकर

का.आ. 2257—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार राजस्व विभाग की दिनांक 1-11-1985 की अधिसूचना सं. [6485 का.सं. 398/29/84-आ.क.(ब.)] का अधिलेखन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री के.एम.एन. शरण को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री के.एम.एन. शरण द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7331/का.सं. 398/18/87-आ.क.(ब.)]

New Delhi, the 5th June, 1987

INCOME-TAX

S.O. 2257.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6485 [F. No. 398/29/84-IT(B)] dated the 1-11-1985, the Central Government hereby authorises Shri K. S. N. Sharan, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the power of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K. S. N. Sharan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7331/F. No. 398/18/87-IT(B)]

का.आ. 2258—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री एल. कुजूर को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री कुजूर द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7333/का.सं. 398/18/87-आ.क.(ब.)]

बी. ई. एलेक्जेंडर, अवर सचिव

S.O. 2258.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri L. Kujur being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Kujur takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7333/F. No. 398/18/87-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जून, 1987

आयकर

का.आ. 2259—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 25-4-1986 की अधिसूचना सं. 6686 (का.सं. 398/8/86-आ.क.व.) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री टी. सी. रंगनाथन को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री टी. सी. रंगनाथन द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7363/का.सं. 398/3/87-आ.क.(ब.)]

New Delhi, the 25th June, 1987

INCOME-TAX

S.O. 2259.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6686 [F. No. 398/18/86-IT(B)] dated the 25-4-1986, the Central Government hereby authorises Sh. T. C. Ranganathan being Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri T. C. Ranganathan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7363/F. No. 398/87-IT(B)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

आयकर

का.आ. 2260—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार एतद्वारा नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना (अधिसूचनाओं) का अधिवेशन करके नीचे स्तम्भ (2) के उल्लिखित व्यक्तियों को, केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर बटुली अधिकारियों के स्थान पर, उक्त अधिनियम के अन्वये कर बटुली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :-

1	2	3	4
क. उन व्यक्तियों के नाम	उन कर बटुली अधि-	पुरानी अधिसूचना सं.	
सं. जिन्हें कर बटुली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है।	कारियों के नाम जिनके स्थान पर स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है।	श्रीर. तरील-जितना अधिवेशन किया गया/जाना है।	
1 श्री डी सुरेश बाबू	श्री के. के. मथई	6263 दिनांक 5-8-85 [फा सं 398/16/85-आ.क. (ब.)]	
2 श्री कुरुविला एम जार्ज	श्री एम. एन राघवन	6261 दिनांक 5-8-85 (फा. सं. 398/16/85-आ.क.ब.)	

2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी तथा जहाँ तक स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है, कर बटुली अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 7383/फा सं. 398/16/87-आ.क. (ब.)]

New Delhi, the 30th June, 1987

INCOME-TAX

S.O.2260—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the persons mentioned below in column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer (s) under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notification(s) mentioned below in column 4 :—

(1)	(2)	(3)	(4)
S. No.	Name of the persons to be authorised to exercise the powers of Tax Recovery Officer (s).	Name of Tax Recovery Officer (s) in place of whom the persons mentioned in column 2 to be authorised.	Old Notification No. and date to be superseded.

1.	Shri D. Suresh Babu	Shri K. K. Mathai	6263 dt. 5-8-85 [F.No. 398/16/85-IT (B)]
2.	Shri Kuruville M. George	Shri M.N. Raghavan	6261 dt. 5-8-1985 [F.No. 393/16/85-IT (B)]

2. This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the date(s) they take over charge(s) as Tax Recovery Officers.

[No. 7383 (F No. 393/16/87-IT (a))]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1987

आयकर

का० आ० 2261—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ संलग्न सारणी में उल्लिखित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए बन्ध-पत्रों को विनिविष्ट करती है।

यसमें कि दृष्टान्त अथवा वितरण द्वारा इस प्रकार के बन्ध-पत्रों के अन्वय के माप में उक्त परन्तुक के अन्वये लाभ स्वकार्य होगा यदि अन्वय 60 दिन के अन्वय के अन्वय रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस प्रकार के अन्वय से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सूचित करे।

सारणी

बन्ध-पत्रों का विवरण

- 1 6% बन्ध पत्र, 1987 (द्वितीय शृंखला)
- 2 6.25% बन्ध पत्र, 1988
- 3 6.25% बन्ध पत्र 1988 (द्वितीय शृंखला)
- 4 6.50% बन्ध पत्र, 1989
- 5 6.50% बन्ध पत्र, 1989 (द्वितीय शृंखला)
- 6 6.75% बन्ध पत्र, 1992
- 7 6.75% बन्ध पत्र, 1992 (द्वितीय शृंखला)
- 8 7.25% बन्ध पत्र, 1996
- 9 7.25% बन्ध पत्र (1996) द्वितीय शृंखला
- 10 7.25% बन्ध पत्र, 1997
- 11 7.50% बन्ध पत्र, 1997
- 12 7.50% बन्ध पत्र, 1997 (द्वितीय शृंखला)
- 13 8.25% बन्ध पत्र, 1995
- 14 8.75% बन्ध पत्र, 2000
- 15 8.75% बन्ध पत्र, 2001
- 16 9% बन्ध पत्र, 1999
- 17 9% बन्ध पत्र, 1999 (द्वितीय शृंखला)
- 18 9.25% बन्ध पत्र, 1998 (41वीं शृंखला)
- 19 9.75% बन्ध पत्र, 1998 (42वीं शृंखला)
- 20 9.75% बन्ध पत्र, 1999 (43वीं शृंखला)
- 21 11% बन्ध पत्र, 2001 (44वीं शृंखला)
- 22 11% बन्ध पत्र, 2001 (45वीं शृंखला)
- 23 11% बन्ध पत्र, 2002 (46वीं शृंखला)
- 24 11% बन्ध पत्र, 2002 (47वीं शृंखला)

[सं० 7457/का० सं० 275/63/87आ०-क० (ब०)]

का० नागराजन, निदेशक

New Delhi, the 31st. July, 1987

INCOME TAX

S.O. 2261— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the bonds issued by the Industrial Finance Corporation of India, New Delhi, as specified in the Table hereto annexed for the purposes of the said clause.

Provided that the benefit under the said proviso shall be admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement or delivery, if the transferee informs the Industrial Financial Corporation of India by registered post within a period of sixty days of such transfer.

TABLE
Description of Bonds

1. 6 % bonds 1987 (IO Series)
2. 6.25% bonds 1988
3. 6.25% bonds 1988 (II Series)
4. 6.50% bonds 1989
5. 6.50% bonds 1989 (II Series)
6. 6.75% bonds 1992
7. 6.75% bonds 1992 (II Series)
8. 7.25% bonds 1996
9. 7.25% bonds 1996 (II Series)
10. 7.25% bonds 1997
11. 7.50% bonds 1997
12. 7.50% bonds 1997 (II Series)
13. 8.25% bonds 1995
14. 8.75% bonds 2000
15. 8.75% bonds 2001
16. 9% bonds 1999
17. 9% bonds 1999 (II Series)
18. 9.75 % bonds 1998 (41st Series)
19. 9.75% bonds 1998 (42nd Series)
20. 9.75% bonds 1999 (43rd Series)
21. 11% bonds 2001 (44th Series)
22. 11% bonds 2001 (45th Series)
23. 11% bonds 2002 (46th Series)
24. 11% bonds 2002 (47th Series)

[No. 7457/F. No. 275/63/87-IT(B)]
B. NAGARAJAN, Director

न. दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

आदेश

स्टाम्प

का.भा. 2262.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो हरियाणा वित्तीय निगम, चंडीगढ़ द्वारा केवल तीन सौ बीस लाख रुपये के मूल्य के बन्धनों (27वीं श्रृंखला) के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 32/87-स्टाम्प-फा.सं. 33/30/87-वि.क.]

New Delhi, the 12th August, 1987

ORDER

STAMPS

S.O. 2262.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes (27th Series) of the value of rupees Three hundred and Thirty lakhs only to be issued by the Haryana Financial Corporation, Chandigarh are chargeable under the said Act.

[No. 32/87-Stamp-F. No. 33/30/87-ST]

का.भा. 2263.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उस शुल्क को माफ करती है जो प्रावास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए

जायेंगे तथा तीस करोड़ रुपये के मूल्य के 11 प्रतिशत श्रृंखला-2002 28वीं श्रृंखला के रूप में विनिर्दिष्ट श्रृंखलाओं के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 33/87-स्टाम्प-फा.सं. 33/34/87-वि.क.]

S.O. 2263.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures described as 11 per cent Debentures-2002 XXVIII Series of the value of rupees thirty crores only to be issued by Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 33/87-Stamp-F. No. 33/34/87-ST]

का.भा. 2264.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स एच.ए.ई. (इंडिया) लिमिटेड को मात्र एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपये के उस संयोजित स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जायेंगे वाले मात्र एक करोड़ पचास लाख रुपये के अधिक मूल्य के क.सं. 1 से 150000 तक के सौ-सौ रुपये 150000 श्रृंखलाओं पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभावी है।

[सं. 34/87-स्टाम्प-फा.सं. 33/27/87-विक्रीकर]

बी.आर. मेहमी, अवर सचिव

S.O. 2264.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. S.A.B. (India) Limited to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh twelve thousand and five hundred only, chargeable on account of the stamp duty on 150000 debentures of Rs. 100 each bearing serial No. 1 to 150000 of the face value of rupees one crore and fifty lakhs only to be issued by the said company.

[No. 34/87-Stamp-F. No. 33/27/87-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(अवर सचिव)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का.भा. 2265.—सर्वोच्च निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपखण्ड प्लेजरा अनुमोदित संस्थान, भट, गांधीनगर के कर्मचारियों के लाभों के लिए संस्थापित सर्वोच्च निधि पर लागू होंगे।

[सं. 4(2)-संस्था. की/83]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 12th August, 1987

S.O. 2265.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provision of the said Act shall apply to the provident fund established for the benefit of the employees of the Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar.

[O.M.No. 4(2)-EV/83]

का. प्रा. 2268 :—मविन विधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित सरकारी संस्थान का नाम जोड़ती है, अर्थात् "प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, भट, गंधीनगर"।

[सं. 4(2)/संस्था.वी./83]

के. रतन, निदेशक

S.O. 2266.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the name of the following public institution namely :—

"Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar."

[No. 4(2)-EV/83]

K. RATAN, Director

(अर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1987

का. प्रा. 2267 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व राज्य और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग विंग) की दिनांक 5 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या का. आ. 460(ई) [सं. एक 4-79/75-ए. सी. (1)] में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में "गोयपाड़ा, कामरूप और दारंग जिलों" शब्दों के स्थान पर "कामरूप, बड़पेटा, दारंग, सोनितपुर, गोयपाड़ा, कोकराझर, बुबन, नावबड़ी और बेनटोला तथा प्रागज्योतिषपुर जिले के पंचवटी मौजे" शब्द आएंगे।

[सं. एक. 1-12/86-ग्राम्यारबी]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 3rd August 1987

S.O. 2267.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Department of Revenue and Banking (Banking Wing) No. S.O. 460(E) [No. F-4-79/75-AC(I)], dated the 5th July, 1976, namely :—

In the said notification, for the words "districts of Goalpara, Kamrup and Darrang", the words "districts of Kamrup, Barpeta, Darrang, Sonitpur, Goalpara, Kokrajhar, Dhubri, Nalbari, and Beltola and Penbari mouzas of Pragjyotishpur district" shall be substituted.

[No. F. 1-12/86-RRB]

का. प्रा. 2268 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 23 सितम्बर, 1980 का का. प्रा. सं. 809 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "24 परगना जिले" के शब्द और अंकों के स्थान पर "नार्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना के जिले" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं. एक. 1-13/86-ग्राम्यारबी]

S.O. 2268.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. S.O. 809(E) dated the 23rd September, 1980, namely :—

In the said notification, for the words and figures "district of 24 Parganas", the words and figures "districts of North 24 Parganas and South 24 Parganas" shall be substituted.

[No. F. 1-13/86-RRB]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1987

का. प्रा. 2269 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री जी. करंदीकर को बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 12-6-1987 से प्रारम्भ होकर 30-6-1990 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री करंदीकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-1/87-ग्राम्यारबी]

New Delhi, the 11th August, 1987

S.O. 2269.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Y. G. Karandikar as the Chairman of the Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh and specifies the period commencing on the 12-6-87 and ending with the 30-6-90 as the period for which the said Shri Karandikar shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-1/87-RRB]

का. प्रा. 2270 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री जी. एस. पण्डे को, जिसकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की सेवा अवधि की पहली अवधि 31-12-1986 को समाप्त हो गई है, 1-1-1987 से प्रारम्भ होकर 11-6-1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक. 2/1/87-ग्राम्यारबी]

S.O. 2270.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri G. S. Pande whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31-12-86 as the Chairman of Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh for a further period commencing from 1-1-87 and ending with 11-6-87.

[No. F. 2/1/87-RRB]

का. प्रा. 2271 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री बी. बी. दास को कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जीपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21-6-87 से प्रारम्भ होकर 30-6-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री दास अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-37/86-ग्राम्यारबी]

S.O. 2271.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. B. Das as the Chairman of the Koraput Panchabati

Gramya Bank, Jeypore and specifies the period commencing on the 21-6-87 and ending with the 30-6-90 as the period for which the said Shri Das shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-37/86-RRB]

का. आ. 2272.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एस के पाव को, जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत कोरापुट पंचावटी ग्राम्य बैंक, जैपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 31-7-86 को समाप्त हो गई है, 1-8-86 से प्रारम्भ होकर 20-6-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक 2-37/86-ग्राम्यारक्ष.]

S.O. 2272.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri S. K. Ghosh whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31-7-86 as the Chairman of Koraput Panchabati Gramya Bank, Jeypore for a further period commencing from 1-8-86 and ending with 20-6-87.

[No. F. 2-37/86-RRB]

का. आ. 2273.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री इरुपु गम कुलकर्णी को, जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत रत्नागिरी सिधुदुर्ग ग्राम्य बैंक, रत्नागिरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-11-86 को समाप्त हो गई है, 1-12-86 से प्रारम्भ होकर 22-4-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक 2-42/86-ग्राम्यारक्ष.]

S.O. 2273.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri W.M. Kulkarni whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 30-11-86 as the Chairman of Ratnagiri Sindudurg Gramin Bank, Ratnagiri for a further period commencing from 1-12-86 and ending with 22-4-1987.

[No. F. 2-42/86-RRB]

का. आ. 2274.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अनिल कुमार माधव वाकडे को रत्नागिरी सिधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23-4-87 से प्रारम्भ होकर 30-4-90 का समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वाकडे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-42/86-ग्राम्यारक्ष.]

S.O. 2274.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Anil Kumar Madhav Wakade as the Chairman of the Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank, Ratnagiri and specified the period commencing on the 23-4-87 and ending with the 30-4-90 as the period for which the said Shri Wakade shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-42/86 RRB]

का. आ. 2275.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अरुण कुमार बानेर्जी को सगर ग्राम्य बैंक, अमताला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 25-5-87 से प्रारम्भ होकर 21-5-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करता है कि जिसके दौरान श्री बानेर्जी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-2/87-ग्राम्यारक्ष.]

S.O. 2275.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Arun Kumar Banerjee as the Chairman of the Sagar Gramin Bank, Amtala and specifies the period commencing on the 25-5-1987 and ending with the 31-5-1990 as the period for which the said Shri Banerjee shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-2/87-RRB]

का. आ. 2276.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री अजय चन्द्र जेना को, जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बैतरानी ग्राम्य बैंक, बरौपाड़ा, मयूरभंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-11-86 को समाप्त हो गई है, 1-12-86 से प्रारम्भ होकर 15-5-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक 2-73/82-ग्राम्यारक्ष.]

S.O. 2276.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri Ajay Chandra Jena whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 30-11-86 as the Chairman of Baitarani Gramya Bank, Baripada, Mayurbhanj for a further period commencing from 1-12-1986 and ending with 15-5-87.

[No. F. 2-73/82-RRB]

का. आ. 2277.—प्रदेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सुब्रह्मण्यन रामनाथन को बैतरानी ग्राम्य बैंक बरौपाड़ा, मयूरभंज का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 16-5-87 से प्रारम्भ होकर 31-5-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान श्री रामनाथन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-73/82-ग्राम्यारक्ष.]

प्रवीण कुमार सेजवान, अवर सचिव

S.O. 2277.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Subramanian Ramnathan as the Chairman of the Baitarani Gramya Bank, Baripada, Mayurbhanj and specifies the period commencing on the 16-5-87 and ending with the 31-5-90 as the period for which the said Shri Ramnathan shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-73/82-RRB]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

कां. आ. 2278---निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) का धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री एम० कृष्णमूर्ति, प्रबंध निदेशक, भारतीय माधारण बीमा निगम को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 अक्टूबर, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए श्री सं० एन० एम० शास्त्री के स्थान पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ० 7/7/87-ब० प्रो० I]

एम० एम० सं तागमन, अवर सचिव

New Delhi, the 10th August, 1987

S.O. 2278.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri S. Krishnamurthy, Managing Director, General Insurance Corporation of India as a Director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period beginning with the date of issue of the notification and ending with October 31, 1988 vice Shri C. N. S. Shastri.

[No. F. 7/7/87-BO, II]

M. S. SETHIARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

का. आ. 2279---केन्द्रीय सरकार, राजधानी (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) विधेयक, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय माधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यभाषा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है---

1 भारतीय माधारण बीमा निगम

कानों का नाम युनाइटेड इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड

- (1) मंडल कार्यालय, देहरादून
- (2) मंडल कार्यालय, कानपुर
- (3) मंडल कार्यालय, लखनऊ
- (4) मंडल कार्यालय, हनुमानगढ़
- (5) मंडल कार्यालय, लखनऊ
- (6) मंडल कार्यालय, मुरादाबाद
- (7) मंडल कार्यालय, बुध्द लुधियाना
- (8) मंडल कार्यालय, दिल्ली
- (9) मंडल कार्यालय, दिल्ली लुधियाना
- (10) मंडल कार्यालय, प्रथम लुधियाना
- (11) शाखा कार्यालय, देहरादून
- (12) शाखा कार्यालय, सहरनपुर
- (13) शाखा कार्यालय, लखनऊ-2
- (14) शाखा कार्यालय, लखनऊ
- (15) शाखा कार्यालय, गोंडा
- (16) शाखा कार्यालय, मेरठ
- (17) शाखा कार्यालय, मेरठ

- (18) शाखा कार्यालय, गुना
- (19) शाखा कार्यालय, साहौर
- (20) शाखा कार्यालय, कानपुर-1
- (21) शाखा कार्यालय, फतेहपुर
- (22) शाखा कार्यालय, पीलीभीत
- (23) शाखा कार्यालय, सीतापुर
- (24) शाखा कार्यालय, विदिशा
- (25) शाखा कार्यालय, मेरठ
- (26) शाखा कार्यालय, फिरोजाबाद
- (27) शाखा कार्यालय, पिथौरागढ़
- (28) शाखा कार्यालय, अमरापुर
- (29) मंडल कार्यालय, जालंधर

[सं 11011/51/85-हि का क]

पी. वी. भिडे, निदेशक

New Delhi, the 13th August, 1987

S.O. 2279.—In pursuance of Sub-Rules (4) of Rule 10 of the Official Language (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India (under the Administrative Control of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) the staff where of have acquired working knowledge of Hindi—

1 General Insurance Corporation of India

Name of the Company United Insurance Co Ltd.

- (1) Divisional Office, Dehradun;
- (2) Divisional Office, Kanpur;
- (3) Divisional Office, Gwalior;
- (4) Divisional Office, Maladwani;
- (5) Divisional Office, Lucknow;
- (6) Divisional Office, Moradabad;
- (7) Divisional Office, 4th Ludhiana;
- (8) Divisional Office, Hissar;
- (9) Divisional Office, 2nd Ludhiana;
- (10) Divisional Office, Jalandhar;
- (11) Divisional Office, 1st Ludhiana;
- (12) Branch Office, Dehradun;
- (13) Branch Office, Saharanpur;
- (14) Branch Office, Lucknow-2;
- (15) Branch Office, Jakhimpur;
- (16) Branch Office, Gonda;
- (17) Branch Office, Mainpuri;
- (18) Branch Office, Renukut;
- (19) Branch Office, Guna;
- (20) Branch Office, Sihore
- (21) Branch Office, Kanpur-1;
- (22) Branch Office, Pilibhit;
- (23) Branch Office, Sitapur;
- (24) Branch Office, Vidisha;
- (25) Branch Office, Meerut;
- (26) Branch Office, Firozabad;
- (27) Branch Office, Pithoragarh;
- (28) Branch Office, Almora;
- (29) Branch Office, Fatehpur.

[No. F. 11011/51/85-HIC]

P. V. BHIDE, Director.

(बीमा खंड)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1987

(बीमा)

का. आ. 2280---केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम बर्ग 3 और बर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के नवप्रवर्तों और शर्तों का पुनरीक्षण)

नियम, 1985 के नियम 13 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित करता है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल, 1986 को भारस्म होने वाली और 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, बोनस के बदले में संदाय, उक्त उपनियम में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके संबलम के 15 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा।

[फा. सं. 2(25)/बोमा-3/87]

एन. जार, नाटिया, प्रवर सचिव

(Insurance Division)

New Delhi, the 18th August, 1987

INSURANCE

S.O. 2280.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, the Central Government hereby determine that, subject to the other provisions of the said sub-rule, the payment in lieu of bonus for the period commencing on the 1st day of April, 1986 and ending with the 31st day of March, 1987 to every Class III and Class IV employee shall be at the rate of 15 per cent of his salary.

[F. No. 2(25)/Ins.III/87]

S. R. BHATTIA, Under Secy.

वार्णिज्य संचालय

(मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1987

आदेश

का.आ. 2281.—मैसर्स यूनिवर्सल रिसोर्सिस (प्रा०) लि०, पों.या० बॉक्स 4903, बी 2/56, सहायराज एम्प्लेय, दिल्ली को आयात तथा निर्यात नीति (खण्ड-1) 1985-88 के पैरा 114(i) के अन्तर्गत स्टॉक तथा वियर के लिये अनिश्चित पुर्तों के आयात के लिये 3,13,082 रु० (तीन लाख तेत्तानीस हजार तथा ब्यासी रु० मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एफ 1477416 दिनांक 18-3-87 जारी किया गया था।

2. पार्टी ने उक्त लाइसेंस की अनुतिनि प्रति जारा किये जाने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अपने तर्क के समर्थन में मै० यूनिवर्सल रिसोर्सिस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ने 85-88 के लिये आयात तथा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-2 के पैरा 86 द्वारा यथाप्रवेशित शपथपत्र दाखिल किया है। शपथपत्र में उन्होंने बताया है कि मूल लाइसेंस उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसे किसी भी पक्षन पर पत्रोक्त नहीं करवाया गया है। अनुतिनि लाइसेंस, मूल लाइसेंस की पूरी राशि अर्थात् 3,43,082 रु० मात्र के लिये अर्पणित है। मैसर्स यूनिवर्सल रिसोर्सिस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली इस बात से सहमत है और यह बताने देते हैं कि यदि उक्त लाइसेंस बाद में प्राप्त हो जाता है तो उसे रिकार्ड के लिये इस कार्यालय को लौटा दिया जायेगा।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस सं० पी/एफ 1477416 दिनांक 18-3-87 पारगमन में आ गया है। यथासंगोचित आयात निर्यात आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9(घ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आयात लाइसेंस सं० पी/एफ 1477416 दिनांक 18-3-87 को एन.ए. द्वारा रद्द करता हूँ। पार्टी को एन.ए. द्वारा रद्द किये गये मूल लाइसेंस के बदले में अनुतिनि लाइसेंस जारी किया जा रहा है।

[फा.सं० 3-यू/लोमस/ए एम-87-जी एल एम/ए एन एम/307]

एन. एन. कृष्णामूर्ती,

उप मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

का. मुख्य निर्यातक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 6th August, 1987

ORDER

S.O. 2281.—M/s. Universal Resources (P) Ltd., P.O. Box 4903, B2/56, Saldarjung Enclave, Delhi were granted an import licence No. P/F/1477416 dt. 18-3-87 for Rs. 3,43,082/- (Rupees Three Lakh forty three thousand & eighty two only) for import of spares for stock & sale under para 114(i) of Import and Export Policy (Vol. I) 1985-88.

2. The party has applied for issue of duplicate copy of the above mentioned licence on the ground that the original licence has not been received by them. In support of their contention, M/s. Universal Resources (P) Ltd., New Delhi have filed an affidavit as required in para 86 of Chapter II of hand Book of Import & Export Procedures 1985-88. In the affidavit, they have stated that they have not received the original licence and the same has not been registered in any of the ports. The duplicate licence is required for the entire amount of the original licence i.e. for 3,43,082 only. M/s. Universal Resources (P) Ltd., New Delhi agrees and undertakes to return the said licence to this office for record, if traced later on.

3. I am satisfied that the Original licence No. P/F/1477416 dt. 18-3-87 has been lost in transit. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(d) of Import Control Order, 1955 dated 7-12-55 as amended, I hereby cancel the Import Licence No. P/F/1477416 dt. 18-3-87. A duplicate Import Licence is being issued to the party in lieu of the original licence cancelled hereby.

[F. No. 3-U/Spares/AM-87-GLS/ALS/307]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller

of Imports & Exports

for Chief Controller of Imports & Exports

(उप-मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

जयपुर, 3 अक्टूबर, 1986

आदेश

का. आ. 2282.—मै० बीजे नोत्रम मार्केट इंटरस्ट्रीज प्रा. लि०, गांव पो. श्री. भुवना एन एच. 8, उदयपुर (राजस्थान) को अप्रैल-मार्च, 1984 अवधि के लिए आयात नीति के परिशिष्ट-5 के अनुसार अनुमेय मर्चों के आयात के लिए 3,28,000/- रु० का मूल्य का आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2214069, दिनांक 4-2-84 दिया गया था।

2. फर्म ने उक्त लाइसेंस की अनुतिनि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी किए जाने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए तथा बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना खो गई है। फर्म ने मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति यदि बाद में मिल जाती है तो, उस को रिकार्ड के लिए इस कार्यालय का लौटाने का वचन दिया है।

3. अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1984-85 के अध्याय-15 के पैरा-353 के अनुसार एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2214069 दिनांक 4-2-84 का मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है तथा आवेदक को लाइसेंस की अनुतिनि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारा करने का निर्देश देता है। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द किया जाता है।

4. लाइसेंस का अनुतिनि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को अक्सर से जारी किया जा रहा है।

[फा. सं. फार्म एन/डी नो टो/डी/एस यू पी पी एल. 5/ए एम. 84/एस डेसी 1/

एयु/डी सी सी आई एंड ई/राज/22374]

भार. के. राहा,

उप-मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

Jaipur, the 3rd October, 1986

ORDER

S.O. 2282.—M/s. DeeJay Neelam Marble Industries Pvt. Ltd., Vil. P.O. Bhuwana, NH. 8, Udaipur (Rajasthan) were granted import licence No. P/D/2244069 dated 4-2-84 for Rs. 3,28,000 for import of permissible items as per Annexure-5 of Import Policy for AM-84 period.

2. The firm requested for the issue of duplicate copy of Customs Purposes copy of the above licence on the ground that the original customs purposes copy has been lost without having been registered with any Customs Authority and utilised at all. The firm agreed and understood to return the original Customs Purposes Copy of the licence if traced later, to this office for record.

3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para-353 of Chapter-XV of Hand Book of Import Export Procedure—1984-85. The undersigned is satisfied that the original customs purpose copy of Import Licence No. P/D/2244069 dated 4-2-84 has been lost and directs that duplicate copy of Customs Purposes copy of the licence may be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy of licence has been cancelled.

4. The duplicate copy of Customs Purpose copy of the Import licence has been issued separately.

[F. No. INF/DGTD/SUPPL.5/AM.84/SEC/IAU/DCCI&E/
22374]

R. K. RAHA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1987

का.भा. 2283.—व्यापार और पण्य वस्तु विज्ञान नियम, 1959 के नियम 157 के उपनियम (2) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 157 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नीचे वर्णित गए परिवर्तन कर दिए हैं :—

क्र.सं. व्यापार चिह्न अभिकर्ता का नाम	निवास स्थान का पता	कारोबार के मुख्य स्थान का पता
1. ए.एस. शिवा	शिवा ट्रेड एंड मार्केट 15 चक्रपानी स्ट्रीट (एक्स्टेंशन) वेस्ट माम्बलाम, मद्रास-600033	ए.एस. शिवा सिवाज ट्रेड एंड मार्केट 15, चक्रपानी स्ट्रीट (एक्स- टेन्शन) वेस्ट माम्बलाम मद्रास-600033
2. एस.सी. मल्होत्रा	फ्लैट नं. 701 (7 वा तल) 6 डी, दामोदर पार्क, एस.बी.एस. मार्ग घाटकोपर (वेस्ट) मुम्बई-400086	अंतरमहाडीपीय व्यापार चिह्न ब्यूरो घीया निवास, (सीसरा तल), 73/75 सुतार चाल, जावेरी वा. मुम्बई-400002
3. श्रीमती एस.एस. मल्होत्रा	फ्लैट नं. 701 (7 वा तल) 6-डी, दामोदर पार्क, एस.बी.एस. मार्ग घाटकोपर (वेस्ट) मुम्बई-400086	मैसर्स मल्होत्रा एंड मल्होत्रा घीया निवास (सीसरा तल) 73/75 सुतार चाल, जावेरी बाजार, मुम्बई-400002

[का.सं. 29/1/84-पी.पी.एच.सी]
सी.आर. गायत्री, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 17th August, 1987

S.O. 2283.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 157 of the Trade & Merchandise Marks Rules, 1959, it is hereby notified in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the said rule 157, the Central Govt. has caused the following alterations to be made in the Registrar of Trade Marks Agents, as shown below :

Sl. No	Name of the Trade Marks Agent	Address of the place of residence	Address of the principal place of business
1.	A.S Siva	SIVAS TRADE & MARKS 15, Chakrapani Street (Extn). West Mambalam, Madras 600033	A.S.Siva Sivas Trades & Marks 15, Chakrapani Street (Extn). West Mambalam, Madras-600033
2.	S C.Malhotra	Flat No. 701 (7th Floor) 6-D, Damodar Park L.B.S. Marg, Ghatkopar (West) Bombay-400086	INTER-CONTINENTAL TRADE MARKS BUREAU GHIA NIWAS (3RD FL) 73/75 SUTAR CHAWL, ZAVERI BAZAR BOMBAY-400002
3.	Smt. S.S. Malhotra	Flat No. 701 (7th Floor) 6-D, Damodar Park L.B.S. Marg, Ghatkopar (West) Bombay-400086	M/s. MALHOTRA & MALHOTRA GHIA NIWAS (3RD FLOOR) 73/75 SURAR CHAWL, ZAVERI BAZAR BOMBAY 400002.

[F. No. 29/1/84-PP&C
C. R. GAYATHARE, Director]

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1987

का.भा. 2284.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मै. इंडियन केबल कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, हैयर स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 में है, के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 1307/76) के निरस्तीकरण का अधिसूचित करती है।

[सं. 16/12/86-एम.-III]

एल.सी. गोयल, अवसर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 19th August, 1987

S.O. 2284.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Indian Cable Company Limited having its registered office at 9, Hare Street, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1307/76).

[No 16/12/86-M. III]
L. C. GOYAL, Under Secy

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का. भा. 2285—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस. बालाचन्द्रन, वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का 12 अगस्त, 1987 से 2 वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त करत है।

[संख्या 7-9/85-वित्त-II]

एम. कुमारस्वामी, निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 12th August, 1987

S.O. 2285.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby re-appoints Shri S. Balachandran, Financial Adviser, Ministry of Petroleum & Natural Gas, as a member of the Oil Industry Development Board to represent the Ministry of Finance, with effect from the 12th August, 1987 and for a period not exceeding two years.

[No. 7/9/85-Fin II]

M. KUMARASWAMI, Director(Finance)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का. भा. 2286—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. जी. एक्स से एस. एन. जी. एम. से एस. एन. सी. टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रस्ताव आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में किसी भी व्यक्ति, उक्त भूमि के लिये पाइपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बजौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुतबाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. जी. एक्स से एस. एन. जी. एम. से एस. एन. सी. टी. एफ. तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात		जिला व तालुका		मेहसाणा	
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5	
बनोस	1238	0	03	96	
	1237	0	08	28	
	1304	0	06	60	
	1305	0	06	60	

1	2	3	4	5
	1323	0	07	56
	1322	0	17	40
	1419	0	00	84

[सं. ओ.-12016/61/87 ऑ.एन जी.जी.-4]

New Delhi, the 12th August, 1987.

S.O. 2286.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.N.D.X. to S.N.D.M. to N. SANTHAL L.T.F. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNDX to SNDM to N. Santal CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balol	1238	0	03	96
	1237	0	08	28
	1304	0	06	60
	1305	0	06	60
	1323	0	07	56
	1322	0	17	40
	1419	0	00	84

[No. O-12016/61/87-ONG/D-4]

का. भा. 2287—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. जी. जी. से एस. एन. जी. एम. से एस. एन. सी. टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रस्ताव आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बसने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिवृद्ध: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. डी. डी. से एस. एन. के. से एस. एस. सी. टी. एक. तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला	व तालुका : मेहसाणा		
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टार
मृदाणा	1316	0	05	16
	1367	0	04	32
	1368	0	01	68
	1366	0	08	64

[स. ओ-12016/52/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2287.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNDD to SNK to SSC/TP in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the Pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNDD to SNK to SS CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Jotana	1316	0	05	16
	1367	0	04	32
	1368	0	01	68
	1366	0	08	64

[No. O-12016/52/87-ONG-D4]

का. धा --2288 यन: केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. जी. जी. एस-II से एन. के. सी. टी. एक. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यन: यह प्रतीत होता है कि ऐसी बातों को बिछाने के परीक्षण के लिए एन. के. जी. जी. एस-II से एन. के. सी. टी. एक. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

अतः इस पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उन्में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित किया है।

बसने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिवृद्ध: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. के. जी. जी. एस. II से एन. के. सी. टी. एक. तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला मेहसाणा	तालुका	कहा	
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
बालासन	114/2	0	09	12
	114/3	0	08	52
	86/1	0	01	20
	86/2	0	11	40
	86/3	0	05	64
	88	0	14	40
	87	0	03	60
काटेद्रेक		0	00	84
	92	0	09	84
	95	0	04	20

[स. ओ-12016/53/87-ओएनजी-डी-4]

S.O. 2288.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK GGS II to NK CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. 39009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner

SCHEDULE

Pipeline from NK GGS II to NK CTF.

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chalasan	114/2	0	09	12
	114/3	0	08	52
	86/1	0	01	20
	86/2	0	11	40
	86/3	0	05	64
	88	0	14	40
	87	0	03	60
	Cart track	0	00	84
	92	0	09	84
	95	0	04	20

[No. O-12016/53/87-ONG-D4]

का.प्र. 2289.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं.-24 से कूप नं. 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्डोपायड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्डोपायड घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षय प्राधिकारी नल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकता है।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ॥

अनुसूची

कूप नं. 24 से कूप नं. 5 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला - बड़ौदा तालुका :- पादरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
चित्राल	115	0	18	75
	125	0	27	60
	146	0	20	40
	147	0	09	15
	151	0	10	95
	152	0	07	80
	150	0	03	60
	153	0	23	70
	155	0	12	45
	कार्टट्रेक	0	00	75
	199	0	08	55

1	2	3	4	5
	198	0	17	85
	196	0	02	00
	197	0	21	30
	195/पी	0	02	00
	कार्टट्रेक	0	01	50
	194/पी	0	07	05
	238	0	25	05
	237	0	01	35
	357	0	19	80
	कार्टट्रेक	0	00	60
	273	0	00	75
	274	0	22	95
	307	0	05	70
	312	0	03	00
	310	0	15	15
	311	0	01	50
	309	0	08	75
	314	0	09	10
	315	0	09	30
	316	0	03	45
	325	0	09	15
	324	0	09	75

[सं. ओ-12016/54/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2289.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from W. No. 24 to W. No. 5 in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from WELL No. 24 to WELL No. 5.

State : Gujarat District : BARODA Taluka: Padara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chitral	115	0	18	75
	125	0	27	60
	146	0	20	40
	147	0	09	45
	151	0	10	95
	152	0	07	80
	150	0	03	60
	153	0	23	70

1	2	3	4	5
Cb'tral	155	0	12	45
	Cart track	0	00	75
	199	0	08	55
	198	0	17	85
	196	0	02	00
	197	0	21	30
	195/P	0	02	00
	Cart track	0	01	50
	194/P	0	07	05
	38	0	25	05
	37	0	01	35
	57	0	19	80
	Cart track	0	00	60
	73	0	00	75
	74	0	22	95
	07	0	05	70
	12	0	03	00
	10	0	15	15
	11	0	01	50
	09	0	06	75
	14	0	09	10
	15	0	09	30
	16	0	03	45
	25	0	09	15
	24	0	09	75

[No. O-12016/54/87-ONG-D4]

का. भा. 2290--यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में असजोल-5 से ऐम. के जी. जी. एस III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवटाइड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एनवटाइड घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकारपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

असजोल-5 से नं. के. जी. जी. एस. III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :- गुजरात जिला :- व. तालुका :- मेहसाणा

गांव	सर्वेक्षण	हेक्टेयर आर. सेन्टीयर	1	2	3	4	5
धनपुरा	723/1 } 723/2 }	0	07	44			
	731	0	02	04			

1	2	3	4	5
धनपुरा	721	0	09	96
	725	0	10	32
	716	0	11	28
	703	0	13	68
	704	0	06	48
	698	0	01	32
	697	0	04	56
	693	0	06	72
	684/1 } 694/2 }	0	09	72
	678	0	16	20
	675	0	03	96
	674/1	0	05	64
	674/2	0	17	04
	447	0	04	44
	448	0	03	16
	468	0	15	36
	467	0	09	60
	473	0	00	60
	474/2 } 474/4 }	0	10	20
	463	0	14	76
	475	0	08	52
	476	0	03	60
	477	0	03	00
	492	0	00	60
	491	0	04	08

[नं. ओ-12016/55/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2290.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Asjal-5 to NK GGS III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Asjal-5 to NK. GGS III.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhanpura	723/1 } 723/2 }	0	07	44
	731	0	02	04
	724	0	09	96
	725	0	10	32
	716	0	11	28

1	2	3	4	5
703		0	13	68
704		0	06	48
698		0	01	32
697		0	04	56
693		0	06	72
694/1	}	0	09	72
694/2				
679		0	16	20
675		0	03	96
674/1		0	05	64
674/2		0	17	04
447		0	04	44
448		0	03	16
468		0	15	36
467		0	09	60
473		0	00	60
474/2	}	0	10	20
474/4				
463			14	76
475		0	08	52
476		0	03	60
477		0	03	00
492		0	00	60
491		0	04	08

[No. O-12016/55/87-ONG-D4]

का.भा. 2291.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एम. डी. क्यू (111) से ब्लोक-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः भव्य पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीवा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कबन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एम. डी. क्यू. (111) से ब्लोक-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात

जिला व तालुक :—मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घर.	सेन्टोयर
1	2	3	4	5
बलो	1679/2	0	01	92
	1679/1	0	01	08
	1676	0	18	72
	1677			
	1680			

1	2	3	4	5
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	1646	0	10	80
	1649	0	06	48
	1650	0	06	48
	1651	0	06	72
	1772/2	0	06	00
	1763	0	01	08
	1770	0	02	40

[सं. ओ-12016/56/87-ओएनजीडी 4]

S.O. 2291.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNDQ (111) to Balol (M) in Guja'at State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNDQ(111) To Balol-4

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balol	1679/2	0	01	92
	1679/1	0	01	08
	1676	0	18	72
	1677			
	1680			
	Cart track	0	01	20
	1646	0	10	80
	1649	0	06	48
	1650	0	06	48
	1651	0	06	72
	1772/2	0	06	00
	1763	0	01	08
	1770	0	02	40

[No. O-12016/56/87-ONG-D4]

का.भा. 2292.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.डी.क्यू. से ब्लोक-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूचित में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उससे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.एन.सी.एम. से बलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य :- गुजरात जिला :- व.तालुका :- मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार.	सेन्टीयर
संथाल	332	0	16	80
	312	0	06	96
	310	0	06	84

[सं. ओ-12016/57/87-ओएनजी-4]

S.O. 2292.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SKCM to Balol-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCM to Balol-4.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Santhal	332	0	16	80
	312	0	6	96
	310	0	06	84

[No. O-12016/57/87-ONG-D4]

का.प्र. 2293.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.सी.एम. से एस.एन.सी. बल्लू (82) से बलोल-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जागे चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उससे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.एन.सी.एम. से एस. ए. एन.सी. बल्लू (82) से बलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :- गुजरात

जिला व तालुका :- मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार.	सेन्टीयर
बलोल	1645/1 } 1645/2 }	0	10	32
	1644	0	03	24
	1678	0	11	40
	1394	0	06	72
	1395	0	07	80
	1399	0	16	68
	1417	0	04	44

[सं. ओ-12016/58/87-ओएनजी-4]

S.O. 2293.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCM to SNCW (82) to Balol-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNDM to SANCW(82) to Balol-4.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Balol	1645/1 }	0	10	32
	1645/2 }			
	1644	0	03	24
	1678	0	11	40
	1394	0	06	72
	1395	0	07	80
	1399	0	16	68
	1417	0	04	44

[No. O-12016/58/87-ONG-D4]

का. भा. 2294--यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पाखाजन-1 से डब्ल्यू. एच.आई. वहेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत।

अनुसूची

पाखाजन-1 से डब्ल्यू.एच.आई. वहेज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य :- गुजरात	तालुका : बागरा	जिला : भरुच		
गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
खोजबल	247	0	11	05
	246	0	06	50
	242	0	02	60
	241	0	13	00
	263	0	13	65
	262	0	15	60
	264	0	26	00
	282	0	15	60
	271	0	14	95
	281/ए	0	02	60
	272	0	22	75
	275	0	05	20
	275/बी	0	11	
	274	0	15	
	326	0	05	20

[सं. ओ-12016/60/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2294.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Pakhajan-1 to WHI at Dahej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan-1 to WHI at Dahej.
State : Gujarat Taluka : Vagara District : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Khajbal	247	0	11	05
	246	0	06	50
	242	0	02	60
	241	0	13	00
	263	0	13	65
	262	0	15	60
	264	0	26	00
	282	0	15	60
	271	0	14	95
	281/A	?	02	60
	272	0	22	75
	275	0	05	20
	275/B	0	11	05
	274	0	15	60
	326	0	05	20

[No. O-12016/60/37-ONG-D4]

का. भा. 2295 --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी.एल.एच. सी. से बलोस ओजीएस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों का बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा धाम्य करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कबन करेगा क: क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

धनुसूची

बी. एल. एच. सो. से बलोल जी. एम. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात	जिला	तालुका :— मेहसाणा			
गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर धार.	सेंटीयर		
मीठा	452	0	11	64	
	453	0	02	28	
	454	0	06	00	
	455	0	02	76	
	456	0	03	12	
	458	0	06	00	

ह.

सक्षम प्राधिकारी

कुसे गुजरात राज्य रिया बडोदरा

[सं. ओ-12016/59/87-ओएनजी-डी 4]

पा. के. राज गीपासन, डेस्क अधिकारी

S.O. 2295.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from BLHC to Balol GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from BLHC to Balol GGS.

State :Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Mitha	452	0	11	64
	453	0	02	28
	454	0	06	00
	455	0	02	76
	456	0	03	12
	458	0	06	00

Sd/-

Competent Authority,

For Gujarat State Area, Vadodra

[No. O-12016/59/87-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

का.धा. 2296.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिकारियों का बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 30 द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नॉथि भी सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राज-पत्रित अधिकारी का पक्ष के समतुल्य निगमित प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोगों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिविष्ट सरकारी परिसरों की बावत, अपना अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगा।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी परिसरों के प्रबर्न और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
कनिष्ठ/सहायक/उप प्रबन्धक (भूमि/सम्पदा/प्रशासन) खनन इंजीनियर धार. आई एम एल बिशाखापतनम (खान) मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बिशाखापतनम इस्पात परियोजना	बिशाखापतनम में स्थित मैसर्स बिशाखापतनम इस्पात परियोजना जो उसके प्रशाननिक नियंत्रणाधीन है के परिसर और बुबावडा, कोयावरी, अग्रहम मक्तेश्वरम, मामरम, पोचरम, सेरीपुरम और करेपल्ली ग्राम जो सभी आन्ध्र प्रदेश में हैं।

[सं. 13(6)/87-बीएसपी]

आई एन नागपास, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 13th August, 1987

S.O. 2296.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (1) of the Table below being officers of the Corporate Authority equivalent in rank to a gazetted officer of the Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction and in respect of public premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of Officers	Categories of Public Premises and local limits of Jurisdiction.
(1)	(2)
Junior/Assistant/Deputy Manager(Land)/Estate/Administration)	Premises belonging to and under the administrative control of M/s. RINL, Visakhap-

1	2
Mining Engineer (Mines) M/s. Rashtriya Ispat Nigam Ltd. Visakhapatnam Steel Project.	atnam Steel Project, situated at Visakhapatnam and village Budawada. Kowthavari Agra- haram, Mukteswarapuram, Madharam, Pecharam, Seri- puram and Katepalli, all in Andhra Pradesh.

[No. 13(6)/87-VSP]
I.L. NAGPAL, Director

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

का.पा. 2297.—इस विभाग की दिनांक 21 अगस्त, 1986 की समसंयुक्त अधिसूचना के अनुक्रम और वार्षिक सभाजन में और पशुधन मायात (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 1 द्वारा यथा संशोधित पशुधन मायात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खंड 2 और उपखंड 3 की धारा (ब) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा, स्पेन, बेलजियम, पुर्तगाल, मॉन्टर्नीय और इटली से सूअर, सूअर का गोस्त, सूअर का सुखाया मांस और सूअर के उर्वी प्रकार के अन्य उत्पादों के इन देशों में प्रकीर्ण सूअर प्वर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 19-7-87 से छः महीने की अवधि के लिये भारत में आयात करने पर निषेध लगाती है।

[सं. 50-43/85-एल.ओ.टी. (ए. व्.ए.)]
एस. पी. वर्मा, प्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 14th August, 1987

S.O. 2297.—In continuation and in partial modification of this Department's notification of even number dated 19th December, 1986 and in exercise of the powers conferred by clause (b) of the section 2 and sub-section 3 of the Livestock Importation Act 1898 (9 of 1898) as amended by the Livestock Importation (Amendment) Act, 1953 (Act 1 of 1953) the Government of India hereby prohibits the import into India of swine, pork, ham and such other Porcing products from Spain, Belgium, Portugal, Netherlands and Italy for a period of six months from 19th June, 1987 (the issue of this notification) in view of the incidence of African Swine Fever in those countries.

[No. 50-43/85-LDT(AQ)]
S. P. VERMA, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

का.पा. 2298.—केन्द्रीय सरकार, नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पठित नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इंडियन नेशनल शिपमैनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाविक भविष्य निधि के व्यासियों के मंडल के सदस्य के रूप में श्री एस. वी. परण्डे, प्रबंधक (फ्लोटिंग स्टाफ प्रकाउण्ट), भारतीय नौवहन निगम लि. को श्री टी. एस. नारायण के स्थान पर नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय जल-भूतल परिवहन विभाग (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. 5757 दिनांक 23-12-1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में कृप. भाग 6 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाए, अर्थात् :—

"6 श्री एस वी परण्डे,
इंडियन नेशनल शिपमैनर्स
एसोसिएशन के प्रतिनिधि"

जहाज मालिकों
का प्रतिनिधित्व"

[का.सं.एल. उल्लु/एम उल्लु एस (30)/82-एमटी]
जे. सी. पंत, प्रवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 13th August, 1987

S.O. 2298.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with sub-paragraph (i) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby appoints Shri S.V. Parande, Manager (Floating Staff Accounts), Shipping Corporation of India Ltd. to represent Indian National Shipowners' Association as a Member of the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of Shri T. S. Narayan and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport, Deptt. of Surface Transport (Shipping Wing), No. S.O. 5757 dated 28-12-1985, namely :—

In the said notification, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"6. Shri S. V. Parande, Shipowners
Representing Indian National Represent-
Shipowners' Association. tive".

[File No. SW/MWS(30)/82-MT]
J. C. PANT, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1987

का.पा. 2299.—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में और भारतीय सर्वेक्षण के सरकारी निवासों का प्रावर्तन नियम, 1974 को प्रतिष्ठित करने हुए, ऐसे प्रतिष्ठित किये जाने के पूर्व की गई और किये जाने से यह गर् बातों को छोड़कर, निम्नलिखित नियम ब्रतते हैं, अर्थात् :—

अनुपूरक नियमों के भाग 8 में, खण्ड 26-कछ, के पश्चात् निम्न-लिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"खण्ड 26-कज"

अ० नि० 317-कज-1 संक्षिप्त नाम, लागू होता और प्रारंभः—

(1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण संघा के सरकारी निवासों का प्रावर्तन नियम, 1987 है।

(2) ये नियम उन निवासों के प्रावर्तन को लागू होंगे, जो भारतीय सर्वेक्षण और ऐसे केन्द्रीय/प्रादेशिक केतन और सेवा कार्यालयों में, जो भारतीय सर्वेक्षण के साथ सेवा अधिकारिता रखते हैं, नियोजित सरकारी सेवकों के उपयोग के लिये प्राथमिक रूप से प्राणयित हैं।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
अ० नि० 317-कज-2 परिभाषाएं :—

इन नियमों में जब तक कि विषय या पदार्थ के बिना कोई बात न हो :

(क) "प्रावर्तन" से अभिप्रेत है इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सरकारी सेवकों को उसके द्वारा निवास के रूप में प्रयोग के लिये निवास का अधिभोग करने हेतु अनुमति का अनुदान;

- (ख) "आर्बंटन बर्थ" से अभिप्रेत है वह वर्ष जो पहली जनवरी को प्रारंभ होता है या ऐसी अवधि जो संबंधित निदेशक द्वारा अधिसूचित की जाये;
- (ग) "संबंधित निदेशक" से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण संपदा का प्रशासन करने के लिये उत्तरदायी भारतीय सर्वेक्षण का निदेशक;
- (घ) "पात्र-कार्यालय" से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय और केन्द्रीय/प्रादेशिक बेतन और लेखा कार्यालय, जो भारतीय सर्वेक्षण के साथ लेखा अधिकारिता रखते हैं, जिनके कर्म-चारिकुन्द इन नियमों के अधीन निवास के लिये पात्र घोषित किये गये हैं ;
- (ङ) "मूल बेतन" से अभिप्रेत है वह बेतन जो वैयक्तिक बेतन, विशेष बेतन, प्रतिनिधित्व (ड्यूटी) भत्ता आदि को छोड़कर, मूल नियम 9(21)(क)(i) में परिभाषित है।

स्पष्टीकरण—ऐसे अधिकारी की दशा में जो निर्धारित है, उस आर्बंटन वर्ष के, जिसमें वह निर्वाचन के अधीन किया गया है प्रथम दिन को उसके द्वारा लिए गए मूल बेतन को या यदि वह आर्बंटन वर्ष के प्रथम दिन को निर्वाचन के अधीन किया गया है तो उस तारीख के ठीक पूर्व उसके द्वारा लिये गये मूल बेतन को मूल बेतन समझा जायेगा;

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, पत्नी या पत्नी और बच्चे, सीसेले बच्चे, विधिक रूप से वक्त लिये गये बच्चे, माता-पिता, भाई या बहिन, जो सामान्यतः अधिकारी के साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हैं।

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो।

(ज) "अनुश्रुति फीस" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन आर्बंटित निवास की बाबत मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक संवेय धन की राशि;

(झ) किसी टाईप के निवास की बाबत जिसका कि वह नियम प्रॉ. 3 के उपबन्धों के अधीन पात्र हैं, अधिकारी की "पूषिकता तारीख" से अभिप्रेत है वह पूर्वतम तारीख जिससे कि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या धिवेशी सेवा के अधीन पद पर, निवास छुट्टियों की अवधि के, ऐसा मूल बेतन लगातार ले रहा है, जो किसी विशिष्ट टाईप या उच्चतर टाईप से सुसंगत है।

परन्तु टाईप ख, टाईप ग या टाईप घ निवास की बाबत वह तारीख जिससे कि अधिकारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में, जिसमें कि विदेशी सेवा की अवधि भी सम्मिलित है, निरन्तर रहा है, उस टाईप के लिये उसकी पूषिकता तारीख होगी।

परन्तु ऐसे पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक की दशा में, जिसने रक्षा सेवा सीमान्त प्रमुखिदाओं को भारतीय सर्वेक्षण में पुनर्नियोजन पर अभ्यर्षित कर दिया है और जिसके सेवा में भंगों की, यदि कोई हों सक्षम प्राधिकारी द्वारा भाग कर दिया गया है, भूतपूर्व सेवाओं को उसकी पूषिकता तारीख का आधार बनाने में गणना में लिया जायेगा। यदि किसी अधिकारी की सेवा में एक भंग से अधिक हैं तो ऊपर वर्णित प्रमुखिदा अंतिम भंग से पूर्व की गई निरन्तर सेवा के संबंध में ही अनुव्यय होगी।

परन्तु यह और कि जहाँ दो या अधिक अधिकारियों की पूषिकता तारीख एक ही, वहाँ उनमें से ज्येष्ठता मूल बेतन की रकम उच्चतर मूल बेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी को निरन्तर मूल बेतन पाने वाले अधिकारी से प्राथमिकता देते हुए अवधारित की जायेगी।

परन्तु यह भी कि जहाँ दो या अधिक अधिकारियों का मूल बेतन समान है वहाँ ज्येष्ठता का अवधारण उनके जन्म की तारीख के प्रति

निर्णय से उस अधिकारी को, जो आयु में अधिक है, आयु में छोटे अधिकारी से प्राथमिकता देते हुए अवधारित किया जाएगा।

(म) ग्रहक "नियुक्ति" से अभिप्रेत है ऐसी नियुक्ति जिसके धारक से भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय / प्रादेशिक बेतन और लेखा कार्यालय की सेवा के लिए विकास करने की अपेक्षा की जाती है।

(ट) "निवास" से अभिप्रेत है ऐसा कोई निवास जो तत्समय संबंधित निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हो।

(ठ) "उस पट्टे पर देना" के अन्तर्गत आर्बंटिनी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा किराये के संवाय सहित या उसके बिना, निवास में रहना है।

स्पष्टीकरण : आर्बंटिनी द्वारा अपने निकट संबंधियों को निवास में रहने उप पट्टे पर देना नहीं सम्मत्ता जाएगा। इस प्रश्न का विनिश्चय कि कोई व्यक्ति निकट संबंधी है या नहीं संबंधित निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ड) "अस्थायी स्थानांतरण" से अभिप्रेत है ऐसा स्थानांतरण जिसमें चार मास से अनधिक अवधि की अनुपस्थिति हो ;

(ड़) "स्थानांतरण" से अभिप्रेत है वर्तमान आस्थान से किसी अन्य आस्थान को या पात्र कार्यालय से किसी अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा का स्थानांतरण या प्रतिनिधित्व और किसी संगठन के अपात्र कार्यालय में किसी पद पर प्रतिनिधित्व भी आती है।

(ण) अधिकारी के संबंध में "टाईप" से अभिप्रेत है निवास का ऐसा टाईप जिसका वह नियम प्र. नि. 317-कज-3 के उपबन्धों के अधीन पात्र है।

प्र. नि. 317-कज-3 निवासों का वर्गीकरण

(1) आर्बंटन के प्रयोजन के लिए निवास निम्न रूप में वर्गीकृत किए गए हैं तथा इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के विवाय, अधिकारी निम्न सारणी में दलित टाईप के निवासों के आर्बंटन के लिए पात्र होगा :-

आवास का टाईप जिसका हकदार है।	हकदारी के प्रस्थापित मामलों में अधिकारियों की मूल बेतन रेज जो उस आर्बंटन वर्ष के जिसमें आर्बंटन किया गया है, प्रथम दिन की हो।
------------------------------	---

टाईप क	₹ 750.00 से 949.00 तक-
टाईप ख	₹ 950.00 से 1499.00 तक
टाईप ग	₹ 1500.00 से 2799.00 तक
टाईप घ	₹ 2800.00 से 3599.00 तक
टाईप ङ	₹ 3600.00 और उससे अधिक

(2) टाईप ङ. का पात्र कोई अधिकारी उससे पिछले नीचे के निवास के टाईप के लिए भी पात्र होगा।

प्र. नि. 317-कज-4 आर्बंटन के लिए आवेदन

(1) "निवास के सभी टाईपों के आर्बंटन" के लिए आवेदन उचित माध्यम द्वारा संबंधित निदेशक को ऐसे प्रकृप और रीति में तथा ऐसी तारीख तक किए जाएंगे जो इस नियमित संबंधित निदेशक विनिश्चित करे निदेशक नियम प्र. नि. 317-क-3 के रूप में प्रत्येक टाईप के निवास के लिए प्रतीक्षा सूची रखेगा। प्रतीक्षा सूची में आर्बंटन पात्रता की तारीख स्पष्टतः दलित होगी। आर्बंटन हक की तारीखों के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार किए जाएंगे।

(2) ऐसा अधिकारी जो भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय बेतन और लेखा कार्यालय/प्रादेशिक बेतन और लेखा कार्यालय में प्रयत्न नियुक्ति या स्थानांतरण पर सेवा आरम्भ करता है वह ऐसी सेवा आरम्भ के एक मास के भीतर संबंधित निदेशक को विधि प्रोकराम में अपना आर्बंटन प्रस्तुत कर सकेगा।

अ. नि. -317 कज -5 निवासों का आर्बंटन

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के निवास, निवास खाली होने पर संबंधित निदेशक द्वारा अधिमान रूप में ऐसे आर्बंटन को, जो अ. नि. 317-कज-14 के उपबंधों के अधीन उस टाईप के आवास का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए प्रेषित हो तो ऐसे आर्बंटन को जो उस टाईप में बिना निवास का है और जिसकी उस टाईप के निवास के लिए सबसे पूर्व की पूर्विकता नारीक रखना है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए आर्बंटित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) संबंधित निदेशक ऐसे आर्बंटन को जिसके लिए वह पात्र है, उससे उच्चतर टाईप का निवास आर्बंटित नहीं करेगा।

(ii) संबंधित निदेशक किसी आर्बंटन को, जिसके लिए वह अ. नि. 317-कज-5 के अधीन पात्र है, उससे नीचे के टाईप के निवास को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करेगा।

(iii) संबंधित निदेशक किसी आर्बंटन द्वारा नीचे के निवास के आर्बंटन के लिए प्रार्थना करने पर ऐसा निवास आर्बंटित कर सकेगा जो उस टाईप से नीचे है जिसका कि आर्बंटन उनके लिए अपनी पूर्विकता के आधार पर पात्र है।

(2) संबंधित निदेशक, अधिकारी का वर्तमान आर्बंटन रह कर सकेगा और उसको उसी टाईप के वैकल्पिक निवास या आयाती परिस्थितियों में ऐसे टाईप के निवास के नीचे के टाईप का आनुकूलिक निवास, जिसमें कि अधिकारी का अधिभोग है, और यदि अधिकारी के अधिभोग का निवास खाली किए जाने के लिए प्रेषित है, आर्बंटित कर सकेगा।

अ. नि. 317-कज-6 पूर्विकता आर्बंटन

(1) निदेशकों और उसके ऊपर की श्रेणियों के अधिकारियों के लिए समुचित निवास आर्बंटित किए जा सकेंगे। यदि इनमें से कोई उस पर अधिभोग नहीं कर रहा है तो वे प्रतीक्षा सूची पर के प्राधिकृत व्यक्ति को इस शर्त पर आर्बंटित किए जा सकेंगे कि वह यदि उक्त अधिकारियों में से किसी के द्वारा अधिभोग के लिए प्रेषित होगा तो 30 दिन की पूर्व सूचना पर उसे खाली कर देगा।

(2) इन नियमों में अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी आर्बंटित समुचित निवासों के साथ निम्नलिखित पूल को संबंधित निदेशक द्वारा पृथक् रूप में रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) पूर्विकता पूल जिसमें निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट होंगे—

सहायक महा सर्वेक्षक, वी. चिकित्सक अधिकारी जिनके अन्तर्गत एक महिला चिकित्सक अधिकारी है, सुरक्षा पर्यवेक्षक, सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक, अभिनयन अधिकारी, ज्येष्ठतम लीडिंग हैंड फायररमैन या अधीक्षक ओ. सी. संपदा अधिकारी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी, देहरादून में वार हाईवर एम. टी. और अन्य स्थानों पर दो हाईवर एम. टी. एक हाईवर फायर इंजन, अभिनयन कर्मचारियों में से पचास प्रतिशत, भारतीय प्रतिशत रक्षक, भारतीय प्रतिशत सफाईवाले।

(ii) संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेगा की उपर्युक्त प्रत्येक प्रजा के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के लिए आवास का उपबंध

किया गया है यदि संख्या में और उस टाईप के निवास संपूर्ण पून के लिए पर्याप्त नहीं है;

(iii) इस पूल में रखे जाने वाले निवासों की टाईपों का संख्या का अवधारण सरकार द्वारा समय समय पर किया जाएगा;

(iv) अधिकारी उक्त पूल में आवास के आर्बंटन के लिए हकदार उस टाईप से अगले निम्न टाईप में होंगे जिसके वे अ. नि. 317-कज-3 के उपबंधों के अधीन हकदार है। तथापि यह उपबंध उन अधिकारियों को लागू नहीं होगा जो पहले से ही टाईप 2 के निवास के हकदार हैं।

(v) यदि किसी समय कोई निवास इस कारण अनावर्तित रह जाता है कि इस पूल का कोई पात्र अधिकारी अधिभोग के लिए उपलब्ध नहीं है तो संबंधित निदेशक उसे प्रतीक्षा सूची में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को इस शर्त पर आर्बंटित कर सकेगा कि वह यदि ऐसे उक्त अधिकारियों में से किसी से अधिभोग के लिए प्रेषित हो तो निवास को तौस दिन की सूचना पर रिक्त कर देगा।

(3) संबंधित निदेशक ऐसे अन्य सरकारी विभागों के कामियों को, जिनकी उपस्थिति सपरा की देखभाल के लिए आवश्यक और अनिवार्य समझी जाती है, उपयुक्त निवासों को आर्बंटित कर सकेगा:

परन्तु यह आर्बंटन ऐसे रक्षकों के अधीन होगा जो भारतीय सर्वेक्षण के हितों में उस समय आवश्यक समझे जाएं और संबंधित निदेशक, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे आर्बंटन को रद्द कर सकेगा जवाबों के लिए बावों की पूर्विकता का क्रम निम्नलिखित होगा:

(क) भारतीय सर्वेक्षण / केन्द्रीय बेतन और लेखा कार्यालय/ प्रादेशिक बेतन और लेखा कार्यालय के कामिक;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कामिक;

(ग) अन्य सरकारी विभागों के कामिक, जिनके बारे में संबंधित निदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाए।

अ. नि. 317-कज-7 सरकारी सेवक का स्वयं रहना और रिक्त निवासों के लिए उपबंध

(1) जब पर्याप्त समुचित निवास उपलब्ध न हो तो उच्चतर या निम्नतर टाईप का निवास अर्थात् ऐसा आर्बंटन लोक निर्माण के हित में फायदेमंद समझा जाए, इस विनिश्चित समझदारी पर आर्बंटित किया जा सकेगा कि उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों को, जैसे और जब समुचित निवास उपलब्ध होता है, उसमें जाना पड़ेगा। अनुज्ञाति फोन प्रवृत्त नियमों के अनुसार बयान की जाएगी।

(2) सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाएगी कि वह निवास में स्वयं रहे, वह छूटो पर या किसी अन्य कारण से बाहर अधिक से अधिक छह माह लिए संबंधित निदेशक को पूर्व के अनुज्ञा से रह सकना है, संबंधित निदेशक से यदि ऐसी अनुज्ञा नहीं ली जाती है तो आर्बंटन रद्द कर सकेगा और उसे बैरखन करने की व्यवस्था कर सकेगा।

परन्तु आर्बंटन सरकारी सेवक को प्रस्थापित कार्यवाही के बिना कारण वगैरह करने का व्यक्तिगत अवसर दिए जाने के पक्षपात ही रह किया जाएगा।

(3) यदि कोई निवास इस कारण अनावर्तित रह जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण का कोई अधिकारी अधिभोग के लिए उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित निदेशक उसे ऐसे सरकारी सेवक को जो भारतीय सर्वेक्षण के भिन्न विभाग में कार्य कर रहा है और जिसे वह उचित समझता है, आर्बंटित करेगा, परन्तु यह तब जब कि आर्बंटित लिखित रूप में यह परिचय देना है कि वह व्यक्ति अनुज्ञाति फोन का संदाय करेगा और उसे ऐसी सूचना मिलने पर कि निवास भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारी के

प्रयोग के लिए अपेक्षित है, उस सूचना प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर उसे खाली कर देगा।

(4) जब प्रतीक्षा सूची में कोई सही बेटन क्रम वाला अधिकारी नहीं है तो रिक्त निवास निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा—

(क) पहले ऐसे अधिकारी को जो अपने उच्चतर वर्ग के लिए प्रतीक्षा सूची में उच्चतर मूल बेटन ले रहा है परन्तु यह तब जब कि वह उसे उस समय खाली करने का करार करे जब कि ऐसा समुचित टाईप का निवास, जिसके लिए प्रतीक्षा सूची में उसका स्थान उसे हकबार बनाता है, खाली होता है, तत्पश्चात्

(ख) ऐसे अधिकारी को जो भ्रमले नौबत के वर्ग के लिए प्रतीक्षा सूची में उच्चतर मूल बेटन ले रहे हैं। यदि वे उनके लिए स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और जब कभी संबंधित निदेशक द्वारा अपेक्षित हो और उसे निवास बदलने के लिए समुचित निवास पुनः आवंटित किया जाए, उसे वह खाली करने के लिए सहमत है।

उच्चतर टाईप के निवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस आवंटित के मूल बेटन के उस प्रतिशत तक उसे सीमित किए बिना मूल नियम 45 क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस होगी।

घ. नि. 317—क पति और पत्नी को आवंटन पालता ऐसे अधिकाधिकारियों की दशाओं में जो एक दूसरे से विवाहित हैं।

(1) किसी अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास आवंटित नहीं किया जाएगा यदि अधिकारी को पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, को पहले से ही निवास आवंटित किया जा चुका है जबकि कि ऐसा निवास अभ्यर्षित न किया जाए।

परन्तु यह कि यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथकरण के आदेश के अनुसरण में भ्रमले भ्रमले निवास कर रहे हैं।

(2) जहाँ इन नियमों के अधीन आवंटित पृथक निवासों में अधिभोग करने वाले अधिकारी एक दूसरे से विवाह करते हैं वे विवाह के एक मास के भीतर निवासों में से एक को अभ्यर्षित कर देंगे।

(3) यदि उप नियम (2) द्वारा यथापेक्षित निवास अभ्यर्षित नहीं किया जाता तो निम्नतर टाईप के निवास का आवंटन ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ समझा जाएगा और यदि निवास उसी के हैं तो उनमें से ऐसे एक का आवंटन जैसा कि निदेशक विनिश्चय करे, ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ समझा जाएगा।

(4) जहाँ पत्नी और पति दोनों केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजित हैं वहाँ इन नियमों के अधीन उनमें से प्रत्येक के निवास के आवंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) में (4) तक में किसी बान के होते हुए भी— यदि यथास्थिति उस पत्नी या पति को जो इन नियमों के अधीन निवास का आवंटित है, ऐसे पूल से, जिसे वह नियम लागू नहीं होते उसी स्थान पर निवासीय आवास पश्चात्कर्त्ती रूप में आवंटित किया जाता है, तो वह पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, निवासों में से किसी को आवंटन के एक मास के भीतर अभ्यर्षित कर देगा।

परन्तु यह कि यह उपनियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पति या पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथकरण के आदेश के अनुसरण में भ्रमले भ्रमले निवास कर रहे हैं।

(6) जहाँ दो अधिकारी उसी स्थान पर पृथक निवासों के अधिभोग में हैं और एक को इन नियमों के अधीन दूसरे और को उस पूल से जिसे वे नियम लागू नहीं होते, निवास आवंटित किया गया है, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, तो उनमें से कोई उन निवासों में से किसी एक को ऐसे विवाह के एक मास के भीतर अभ्यर्षित कर देगा।

(7) यदि निवास उपनियम (5) या (6) के अधीन अभ्यर्षित अभ्यर्षित नहीं किया जाता है तो भारतीय संपदा सर्वेक्षण में निवास का आवंटन ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् रद्द किया गया समझा जाएगा।

घ. नि. 317—क-9 बिना पारी के आवंटन

(1) निदेशक द्वारा सरकारी निवास के अधिभोग वाले सरकारी सेवक के, जो सरकारी सेवा से अधिवर्धिता प्राप्त करता है या सरकारी सेवा के दौरान मर जाता है, पुत्र या पुत्री अथवा पत्नी या पति अथवा पिता या माता को निवास का आवंटन किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि उक्त संबंधी स्वयं भारतीय सर्वेक्षण और केन्द्रीय बेटन और लेखा कार्यालय/प्रादेशिक बेटन और लेखा कार्यालय में नियोजित हो या सरकारी सेवक के बचले में उसकी मृत्यु के बारह मास के भीतर उनमें नियुक्ति प्राप्त कर ली हो और उस सरकारी सेवक के जो अधिवर्धिता प्राप्त करता है या सेवा के दौरान मर जाता है, ऐसी अधिवर्धिता या मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक रहता रहा है। उसे वहाँ निवास आवंटित किया जा सकेगा जिसका आवंटित अधिभोग कर रहा था यदि वह उसी टाईप या उच्चतर टाईप के निवास के लिए पात्र है, अन्य दशाओं में उसे ऐसे टाईप का निवास आवंटित किया जा सकेगा जिसका वह वास्तविक रूप में पात्र है परन्तु यह तब जब कि ऐसा निवास खाली हो और निवास खाली न होने की दशा में उसे ठीक अपने सीने वाला टाईप आवंटित किया जा सकेगा।

(2) संबंधित निदेशक बिकिसीय आघातों पर जहाँ सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य क्षय रोग, कैंसर से पीड़ित हो और जिला चिकित्सा अधिकारी/मिजिल सर्जन ऐसे अन्य विशेषज्ञ को जो नियत किया जाए कि राय में उसके लिए यथोचित आवास की आवश्यकता आवश्यक हो गृह आवंटन समिति की सिफारिश के आधार पर अपनी बिना पारी के आवंटन कर सकेगा। बेहतरावून में ऐसे बिना पारी के आवंटन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे।

- | | |
|--|----------|
| (i) निदेशक (प्रशासन और वित्त) | —अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक नक्शा प्रकाशन | —सदस्य |
| (iii) उप निदेशक, जो संपदा मामलों के संबंध में कार्रवाई करता हो | —सदस्य |

इसी प्रकार हेतुवाव समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

- | | |
|---|----------|
| (i) वरिष्ठ निदेशक, सर्वेक्षण, प्राशिक्षण केन्द्र और नक्शा प्रकाशन | —अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान | —सदस्य |
| (iii) उप निदेशक जो संपदा मामलों के संबंध में कार्रवाई करता हो | —सदस्य |
- अन्य स्थानों में आवंटन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे—
- | | |
|--|----------|
| (i) संबंधित निदेशक | —अध्यक्ष |
| (ii) उप निदेशक, जो संपदा मामलों के संबंध में कार्रवाई करता हो | —सदस्य |
| (iii) उप स्थान पर किसी अन्य निदेशालय में उप-निदेशक उस स्टेशन का प्राधिकार बंधा | —सदस्य |

संबंधित बिकिसीय प्राधिकारियों का सकारितों पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। इस बारे में कोई भी आवेदनात्मक निवेश नहीं हो सकता कि उनकी राय और विचार स्वीकार किए जाने चाहिए।

(i) गृह आवंटन समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी और बिना पारी के आवंटन के लिए आवेदनों पर विनिश्चय करेगी। ऐसे आवेदकों को उनके आवेदन गृह आवंटन समिति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं,

- महान् कर्म में और व्यक्तिगत रूप से विनिश्चय की सूचना दी जानी चाहिए। उन आवेदकों की, जिनको बिना पारी आर्बंटन के लिए मंजूरी दी जाती है, सूची उनके आवेदनों की प्राप्ति की तारीख के अनुसार व्यवस्थित की जानी चाहिए और सूचना पट्ट पर लगाई जानी चाहिए।
- (ii) अपील—गृह आर्बंटन समिति के विनिश्चय के शिरोधार्य विषयों की विनिश्चय महा-सर्वेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और ऐसे मामले में उसका विनिश्चय अंतिम माना जाएगा।
- (iii) यदि किसी परीय की अपील महा-सर्वेक्षक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उनका नाम गृह आर्बंटन समिति द्वारा उक्त ब्रेडक में जिसमें अपीलार्थी का मामला नामजूर किया गया था, अनुमोदित अंतिम नाम के नीचे सूची में गोट किया जाएगा।
- (iv) जब परीयों की आर्बंटन के लिए बिना पारी के आधार पर क्वार्टर उपलब्ध हो तो उनका आर्बंटन उक्त (i) में निर्दिष्ट प्रतीक्षा सूची के क्रम से आर्बंटन किया जाएगा।
- (v) बिना पारी के आधार पर किए गए किसी आर्बंटन के अस्वीकार किए जाने पर संबंधित अधिकारी का नाम बिना पारी के क्वार्टरों के आर्बंटन के लिए प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ प्रतीक्षा परीय से प्राप्त सम्भावित पर, गृह आर्बंटन समिति मंजूरी को पुनर्जीवित करने का विनिश्चय करती है वहीं उस परीय का बिना पारी के आधार पर क्वार्टर पुनः आर्बंटन किया जाना चाहिए।
- (vi) ऐसे मामलों में जहाँ बिना पारी आर्बंटन गृह आर्बंटन समिति द्वारा मंजूर किया गया है किन्तु वास्तविक आर्बंटन मंजूरी की तारीख से छह माह के भीतर नहीं किया गया है, वहीं आर्बंटन समिति द्वारा 6 मास की समाप्ति पर उसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और उन परीयों के नामों की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाना चाहिए जिनके मामलों में बिना पारी आर्बंटन के लिए अपेक्षा करने वाली परिस्थितियाँ हो सकती हैं परिवर्तित हो गई हों और परिवर्तित परिस्थितियों में बिना पारी आर्बंटन व्यायसंगत न हो।
- (vii) रिक्त होने वाला प्रत्येक निवास क्वार्टर निम्नलिखित के कारण बिना पारी के आधार पर आर्बंटन के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए (क) आर्बंटन ऐसे सरकारी सेवक के निकट संबंधों को किया जाए जो उपनियम (i) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार सरकारी सेवा में अधिवापिला प्राप्त कर लेता है या सेवा के दौरान मर जाता है और (ख) विकिस्तीय आधारे पर जहाँ सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार अयरोज/कैंसर से पीड़ित है यह आरक्षण इस बात के अधीन होगा कि इस प्रकार आरक्षित क्वार्टरों की संख्या बिना पारी के आर्बंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में परीयों की संख्या से अधिक नहीं होगा चाहिए। यदि कोई बिना पारी आर्बंटन लंबित नहीं है तो वह आरक्षित क्वार्टर साधारण प्रयोग के अधीन आर्बंटन के लिए चला जाएगा।
- (viii) आर्बंटन किए जाने वाले क्वार्टरों के टाईप का अधिधारण करने के लिए बिना पारी के आर्बंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय परीय द्वारा लिए जाने वाले बेतन को ध्यान में रखा जाएगा सभी संबंधित बिना पारी मंजूरीयों के लिए जिनके लिए एक वर्ष के भीतर आर्बंटन नहीं किया गया है, ऐसे बेतन पुनरीक्षण का, यदि कोई हो, तो उस अवधि के दौरान किया गया हो, आर्बंटन किए जाने वाले क्वार्टर के टाईप का अधिधारण करने के लिए लेखा रिया जाएगा।

(ix) ऐसे परीयों को, जिनको बिना पारी आर्बंटन की मंजूरी दी गई है, उनके हक से एक वर्ष नीचे का क्वार्टर दिया जाना चाहिए। संघी भारतीय किए गए व्यक्तियों को जो सिपिकीय और सहस्रद काठरों में विभाग में सेवा आरम्भ करते हैं और जो टाईप 2 के क्वार्टरों के लिए हकदार हैं, बिना पारी के आधार पर टाईप 2 क्वार्टर दिया जाना चाहिए किन्तु टाईप 2 क्वार्टरों के हकदार परीयों को जो एक बार टाईप 1 क्वार्टर के लिए पात्र थे बिना पारी के आधार पर टाईप 1 क्वार्टर दिया जाना चाहिए।

अ. नि. 317--कज--40 आर्बंटन या प्रस्थापना की अस्वीकृति या स्वीकृति के पश्चात् आर्बंटन निवास पर अधिभोग करते की असफलता।

(1) यदि अधिकारी पांच दिन के भीतर निवास आर्बंटन को स्वीकार नहीं करता है या स्वीकृति के पश्चात् आर्बंटन के पक्ष की प्राप्ति के आठ दिन के भीतर उस निवास का कब्जा नहीं ले लेता है, तो वह दूसरे आर्बंटन के लिए आर्बंटन के पक्ष की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि कोई अधिकारी जो निम्नतर टाईप के निवास का अधिभोग कर रहा है उसे उक्त टाईप का निवास, जिनके लिए वह नियम 317-कज-3 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने इन नियमों के अधीन आवेदन किया है, आर्बंटन किया जाना है या प्रस्थापित किया जाना है उसे उक्त आर्बंटन या आर्बंटन को प्रस्थापना के इंकार पर अनुशा दी जा सकेगा कि वह निम्न लिखित बातों पर पूर्वत आर्बंटन निवास में बना रहे अर्थात्--

(i) ऐसा अधिकारी उल्लखत टाईप के निवास के आर्बंटन के लिए आर्बंटन पक्ष की तारीख से 6 मास की अवधि के लिए दूसरे आर्बंटन का पात्र नहीं होगा।

(ii) वर्तमान निवास को प्रतिधारित करने हुए उससे वही अनुज्ञप्ति फीस प्रसारित की जाएगी जिसका उसे मूल नियम 45-क के अधीन उस प्रकार आर्बंटन या प्रस्थापित निवास की बात नदार्थ करता पड़ता था जो उसके पहले के अधिभोग के निवास के संबंध में मरिय अनुज्ञप्ति फीस है, इनमें से जो भी उच्च हो।

अ. नि. 317-कज-11--अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित उपबन्ध

(1) (क) जहाँ निवास का या आनुकम्पिक निवास का आर्बंटन स्वीकृत किया जा चुका है, अनुज्ञप्ति फीस का वास्तविक अधिभोग की तारीख से या आर्बंटन पक्ष की प्राप्ति तारीख के आठवें दिन से जो भी पूर्वतर हो, आरम्भ होगा।

(ख) ऐसा अधिकारी जो स्वीकृति के पश्चात् आर्बंटन-पक्ष की प्राप्ति की तारीख से आठवें दिन के भीतर उस निवास का कब्जा नहीं लेता है उससे अनुज्ञप्ति फीस उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक लिए ली जाएगी। परन्तु इसमें की कोई बात उस वशा में लागू नहीं होगी जब कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित करे कि निवास उस समय तक अधिभोग के लिए तैयार नहीं था और उसके परिणाम-स्वरूप अधिभोग ने पूर्वत अवधि के भीतर निवास का कब्जा नहीं लिया।

(2) जहाँ अधिकारी को, जो निवास के अधिभोग में है, एक दूसरा निवास आर्बंटन किया जाता है और वह नए निवास का अधिभोग कर लेता है तो पूर्व निवास का आर्बंटन नए निवास के अधिभोग की तारीख से यह हुआ मसमा जाएगा। तथापि वह निवास को बचाने और उसके पश्चात् के दिन के लिए बिना किसी अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के पूर्ववर्ती निवास प्रतिधारित कर सकेगा।

अ. नि. 317-वज-10 निवास के खाली होने पर अन्तर्गत फीस के सदाय व विण अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व और अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभति का दिया जाना।

(1) अधिकारी जिसे निवास आवंटित किया गया है उस अवधि के दौरान जिसके लिए निवास उसको आवंटित किया गया है और उसके आवंटित रहना है या जहां आवंटन इन नियमों के उपबन्धों में से निर्धारित नहीं किया जा चुका है तो उस अवधि तक के लिए जब तक कि निवास उससे लगे हुए उपभोक्ता के साथ खाली न किया गया हो और उसका पूरा खाली कच्चा सरकार को पुनः वापस न किया गया हो, उसकी अनुमानित फीस के लिए तथा सरकार द्वारा दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग या सेवाओं में, उचित टूट-फूट के प्रतिभति की गई नुकसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(2) जहां अधिकारी जिस निवास आवंटित किया गया है, न स्थायी न स्थायित्व सरकारी सेवक है वह ऐसे निवास, सेवाओं और उसके बदले दिए गए दूसरे किसी निवास की बाबत उसको शोध अनुमानित फीस और अन्य प्रभावों से सम्बन्धित सदाय के लिए ऐसे प्रतिभूति सहित, या केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी सरकारी सेवक होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रकृति में प्रतिभति बंधपत्र निष्पादित करेगा।

(3) यदि प्रतिभूति सरकारी सेवा में नहीं रह जाता है या दिया-लिया हो जाता है या किसी अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाता है या अपनी गारण्टी वापस ले लेता है तो अधिकारी ऐसी घटना या तथ्य की अपनी जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर दूसरे प्रतिभूति द्वारा निष्पादित नवीन बंधपत्र देगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसको दिए गए निवास का आवंटन जब तक कि संबंधित निदेशक के द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

(4) अनुमानित फीस भारतीय सर्वेक्षण के आहरण और संविमरण अधिकारी द्वारा संबंधित निदेशक द्वारा दिए गए भाग विवरण के प्राधिकार पर संबंधित अधिकार के बतन बिना से बतन की जाएगी। संबंधित निदेशक द्वारा भाग विवरण में विनिर्दिष्ट रकमे संबंधित सरकारी सेवक का पूर्व-निर्दिष्ट किए बिना पूरी बतन की जाएगी।

अ. नि. 317-वज-13-वह अवधि जिसके लिए आवंटित अस्तित्व में रहता है और आगे प्रतिधारण के लिए गिरायती अवधि

(1) आवंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसमें वह अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है और जब तक प्रभावी रहेगा जब तक —

(1) अधिकारी पात्र-कार्यालय में कतब पर नहीं रह जाता है, उसके पश्चात् उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय गिरायती अवधि समाप्ति नहीं हो जाती,

(II) वह संबंधित निदेशक द्वारा वह रद्द नहीं किया जाता है या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया हुआ नष्टा गमना जाता है

(III) अधिकारी द्वारा वह अध्यापित नहीं किया जाता है, या

(IV) अधिकारी निवास को अधिभोग में नहीं रखता है।

(2) उप नियम (3) के अधीन रहते हुए अधिकारी का आवंटित निवास निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उसके स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखा जा सकेगा। परन्तु यह तब जब कि निवास अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के सम्भावित प्रयोग के लिए निवास अपेक्षित है।

सारणी

घटनाएं निवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञेय अवधि

1	2
(I) पदत्याग, पदच्युति या सेवा में हटाया जाना, सेवा की समाप्ति या अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति।	चार मास
(II) सेवा निवृत्ति या सेवान्तरण छुट्टी	चार मास
(III) आर्थिकी की मृत्यु	छह मास
(IV) वर्तमान स्थान में बारह स्थान को स्थानांतरण	दो मास
(V) आस्थान में किसी अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण	दो मास
(VI) भारत में विदेश सेवा के लिए प्रस्थान पर	दो मास
(VII) भारत में सम्भावी स्थानांतरण या भारत के बारह स्थान को स्थानांतरण	चार मास
(VIII) छुट्टी (पूर्व सेवा निवृत्ति छुट्टी इकार की गई छुट्टी, सेवान्तरण छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययन छुट्टी से निश्चय)	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु चार मास से अधिक नहीं
(IX) मूलनियम 86 के अधीन दी गई पूर्व सेवा निवृत्ति छुट्टी या इकार की गई छुट्टी	अधिकतम चार मास के अधीन रहने हुए जिसमें सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि सम्मिलित है पूर्ण अधीन वेतन पर छुट्टी की पूरी अवधि के लिए।
(X) भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी या प्रतिनियुक्ति	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु 6 मास से अधिक नहीं।
(XI) भारत में अध्ययन छुट्टी	छुट्टी की अवधि के लिए किन्तु 6 मास से अधिक नहीं होगी।
(XII) चिकित्सीय आधारों पर छुट्टी	छुट्टी की पूरी अवधि।
(XIII) प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान पर	प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए।

स्पष्टीकरण 1 जहां भारत में स्थानांतरण या विदेश सेवा में किसी अधिकारी का छुट्टी मजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में सेवा आरम्भ करने के पूर्व उसका उपसंग करना है उसे सब (IV), (V), (VI) और (VII) में उल्लिखित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए जा भी अधिक हो निवास को रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण 2 जहां भारत में विदेश क्षेत्र पर स्थानांतरण का आदेश किसी ऐसे अधिकारी को दिया जाता है जो कि पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण 1 के अधीन अनुज्ञेय अवधि की गणना ऐसे आदेश के जारी करने की तारीख से की जाएगी।

(3) जहां निवास उपनियम (2) के अधीन प्रतिधारित किया जाता है तो आवंटन अनुज्ञेय गिरायती अवधियों की समाप्ति के पूर्व तब तक रद्द हुआ समझा जाएगा जब तक कि उसकी समाप्ति पर तुरन्त अधिकारी पात्र कार्यालय में सेवा-पुनः आरम्भ न करे।

(4) जहां अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के वित्तीय छुट्टी पर है, वह उपनियम (2) के नीचे की सारणी में मद (Xii) के अधीन रियायत के आधार पर प्रपत्ता निवास प्रतिधारित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे निवास की अनुमति फीम तब तक रूप में प्रति मास भेजता रहे और जहाँ वह दो महीने में अधिक के लिए ऐसी अनुमति फीम भेजने में असफल रहता है, आवंटन रद्द हो जाएगा।

(5) ऐसा अधिकारी जिसने उपनियम (2) के नीचे की सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास को प्रतिधारित किया है किसी पात्र कार्यालय में पुनर्नियोजन पर उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस निवास को प्रतिधारित करने का हकदार होगा और वह इन नियमों के अधीन निवास के किसी और आवंटन के लिए भी पात्र होगा।

परन्तु यह कि जब ऐसे पुनर्नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां उसके द्वारा अधिभोग किए गए टाईम के निवास का उसे हकदार नहीं बताती है, उसे निम्नतर टाईम का निवास आवंटित किया जाएगा।

(6) उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई अधिकारी पदस्थित किया जाता है या सेवा में हटाया जाता है या जब उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और उस कार्यालय में जिसमें कि ऐसा अधिकारी ऐसी पदस्थिति या हटाए जाने या सेवा समाप्त किए जाने के ठीक पूर्व नियोजित था, की बाबत विभाग के प्रधान का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और समीचीन है, वह संबंधित निदेशक से ऐसे अधिकारी की किए गए निवास का आवंटन तुरन्त या उपनियम (2) के नीचे सारणी की मद (i) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व की तारीख से जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, रद्द करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और संबंधित निदेशक तबनुसार कार्य करेगा।

अ० नि० 317-कज-14-आवंटन का अभ्यर्पण और अवधि।

(1) अधिकारी किसी समय आवंटन का अभ्यर्पण ऐसी सूचना देते हुए कर सकेगा जो निवास के खाली करने की तारीख से पूर्व कम से कम दस दिन के भीतर संबंधित निदेशक को पहुँच जाए। निवास का आवंटन उस दिन के पश्चात् तयारहने वाले दिन से जिस दिन पत्र संबंधित निदेशक को प्राप्त होता है या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से जो भी बाद की हो, रद्द हुआ समझा जाएगा। यदि वह ऐसी समय सूचना देने में असफल रहता है तो वह दस दिन के लिए या ऐसे दिनों के लिए जो उसके द्वारा दी गई सूचना में दस दिनों से दस दिनों के कम पड़ते हैं, अनुज्ञति फीम के मसाले के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु यह कि संबंधित निदेशक कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि विहित सूचना आवंटन के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण नहीं दी जा सकती थी।

(2) अधिकारी जो उपनियम (1) के अधीन निवास अभ्यर्पित करता है उस पर पुनः उसी आस्थान पर सख्तरी आवास के आवंटन के लिए ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अ० नि० 317-कज-15-निवास का परिवर्तन

(1) अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन निवास आवंटित किया जा चुका है, वह उसी टाईम के दूसरे निवास के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा। अधिकारी को आवंटित किए गए एक टाईम के निवास की वापस एक से अधिक परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) परिवर्तनों की प्रस्थापना संबंधित निदेशक के कार्यालय में प्राप्त उनके आवेदनों के कम में की जाएगी।

(3) यदि अधिकारी उसको दम्पती निवास के परिवर्तन को ऐसी प्रस्थापना या आवंटन के द्वारा करने के पात्र दिन के भीतर स्वीकार

करने में असफल रहता है तो उस पर उस टाईम के निवास के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे अधिकारी पर, जो निवास के परिवर्तन को स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा लेने में असफल रहता है, पहले से उसके कब्जे के निवास के लिए, जिसका आवंटन अस्तित्व में बना रहेगा, मूल नियम 15 क के अधीन प्रामाण्य अनुज्ञति फीम के अनिवार्य अ० नि० 317, कज-10 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार उस पर ऐसे निवास के लिए अनुज्ञति फीम प्रधारित की जाएगी।

अ० नि० 317 कज-16 निवासों का परस्पर विनियम

अधिकारी, जिन्हें इन नियमों के अधीन उसी आस्थान पर उसी टाईम के निवास आवंटित किए गए हैं अपने निवास के परस्पर विनियम की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा। परस्पर विनियम के लिए अनुज्ञा अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि दोनों अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य पर होने और ऐसे विनियम के अनुमोदन की तारीख से कम से कम 6 मास के लिए परस्पर विनियम किए गए निवास में निवास करने की आशा की जाए।

अ० नि० 317 कज-17 निवासों का उप पट्टे पर देना और उसमें साथ रहने देना।

(1) कोई अधिकारी उसको आवंटित निवास या किसी उपगृह और गैराज में सिवाय केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के, जो इन नियमों के अधीन निवास के आवंटन के लिए पात्र हैं, साथ नहीं रहेगा। सेवकों के स्वार्टर, उपगृह, गैराज और अस्तबल सद्व्यवस्था प्रयोजनों के लिए ही जिनमें प्रासंगिकता के सेवक का निवास है और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो संबंधित निदेशक द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, प्रयोग किए जा सकेंगे।

(2) कोई अधिकारी अपने संपूर्ण निवास को उप पट्टे पर नहीं देगा:

परन्तु छुट्टी पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी ऐसे किसी अधिकारी को, जो सख्तरी निवास में साथ रहने के लिए पात्र हो, सहायक के रूप में अ० नि० 317 कज-12 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किन्तु जो 6 मास से अनधिक होगी, आवास सुविधा प्रदान कर सकेगा।

(3) अधिकारी जो अपने निवास में साथ रहने देता है या उसको उप-पट्टे पर देता है वह अपने स्वयं की जाक्षिम और उत्तरदायित्व पर ऐसा करेगा और निवास की बाबत मदत किसी अनुज्ञति फीम, निवास या इसकी प्रतीमाओं या धौल, सरकार द्वारा उसमें दी गई सेवाओं में उचित टूट-फूट के परे कारित किसी नुकसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बना रहेगा।

(4) निवास में साथ रहने देना केवल संबंधित निदेशक की पूर्व अनुज्ञा द्वारा ही किया जा सकेगा।

अ. नि. 317-कज-19-कुटुंब न रखे जा सकने वाले आस्थान पर स्थानान्तरण

यदि अधिकारी का स्थानान्तरण ऐसे स्थान पर हो जाता है जहाँ उसे सरकार द्वारा अपने साथ अपना कुटुंब रखने को अनुज्ञा नहीं दी जाती है या सलाह नहीं दी जाती है और इन नियमों के अधीन उसको आवंटित निवास बच्चों की सम्भावना शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए कुटुंब द्वारा अपेक्षित है, वह प्रार्थना किए जाने पर मूल नियम 45-क के अधीन अनुज्ञति फीम के पंदाय पर अपने बच्चों के शाला शिक्षा मल के अत तक निवास प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

अ. नि. 317-कज-19-निवासों के अनुरक्षण के लिए दायित्व

(1) अधिकारी जिसे निवास आवंटित किया गया है निवास और परिसरों को संबंधित निदेशक के समाधानप्रद रूप में स्वच्छ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुज्ञाओं के विपरीत कोई नुकसान आदि या नोडा नहीं उत्पन्न या वांछित निदेशक की विहित पूर्व प्रज्ञा के विरुद्ध निवास के मसाले बाँट

सहन या प्रशासित में विद्यमान किसी वृक्ष या झाड़ी को नहीं काटेगा या उसको काट-छाट नहीं करेगा। इस नियम के उल्लंघन में उपाए गए वृक्ष, बागान या वनस्पति संबंधित निदेशक द्वारा संबंधित अधिकारों को जोखिम और खर्च पर कटवाए जा सकेंगे।

(2) अधिकारी से, जिसे निवास प्रावर्तित किया गया है जब वह निवास के अधिभोग में प्रवेश करता है और जब वह उसे खाली करता है यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फर्नीचर (निवास में यदि दिया गया हो) और फिटिंग्स को प्रस्तु सूची पर हस्ताक्षर करे।

(3) अधिकारी जिसको निवास प्रावर्तित किया गया है वह किसी प्रकार के जानवर को उसके अन्दर या उसके समीप नहीं रखेगा।

प्र. नि. 317-कज-20-नियमों और शर्तों के भंग के परिणाम

(1) यदि अधिकारी जिसे निवास प्रावर्तित किया गया है अप्राधिकृत रूप से निवास को उप पट्टे पर देता है या हिस्सेदार से ऐसी वर पर कियाया प्रभारित करता है, जिसे संबंधित निदेशक अत्यधिक समझता है या निवास के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत संरचना का परिनिर्माण करता है या निवास या उसके किसी भाग को किसी ऐसे प्रयोजन से जिसके लिए वह बना है, भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है या बिजली या अन्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है या नियमों या प्रावर्तन के निबंधों और शर्तों को भंग करता है या निवासों या परिसरों को ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे संबंधित निदेशक अनुचित समझता है, प्रयोग करता है या प्रयोग करने के लिए अनुज्ञा देता है या ऐसी रीति में व्यवहार करता है जो उसकी राय में उसके पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या जानबूझकर प्रावर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखत कथन में गलत सूचना देता है, तो संबंधित निदेशक किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जो उसके विवेक की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निवास के प्रावर्तन को रद्द कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में "अधिकारी" पद से जब तक कि सर्वम से अन्यथा अपेक्षित न हो उसके कुटुंब का सदस्य और अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, भीते हैं।

(2) यदि अधिकारी उसको प्रावर्तित निवास या उसके किसी भाग या उससे अनुलग्न किसी उपगृह या अस्तबल को इन नियमों के उल्लंघन में उपपट्टे पर देता है तो उससे ऐसी किसी कार्रवाई पर, जो उसके विवेक की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से चार गुना से अधिक बढ़ी हुई अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी। बसूल की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस का भाला और वह भवधि जिसके लिए वह बसूल की जाएगी, संबंधित निदेशक द्वारा गुणगुण पर विनिश्चित की जाएगी। इसके प्रतिरिक्त अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिश्चित भवधि के लिए जो संबंधित निदेशक द्वारा विनिश्चित की जाए, निवास में हिस्सेदार बनाने के लिए विवक्षित कर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रावर्तित द्वारा परिसरों को अप्राधिकृत रूप से उप पट्टे पर देने के कारण प्रावर्तन को रद्द करने की कार्रवाई की गई है, प्रावर्तित और किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके साथ निवास कर रहा हो, साठ दिन को भवधि परिसरों को खाली करने के लिए अनुज्ञा की जाएगी प्रावर्तन परिसर, परिसर को खाली करने की तारीख से या प्रावर्तन के रद्दकरण के लिए आवेदनों की तारीख से साठ दिन की भवधि की समाप्ति से, जो जो पूर्वतर हो, रद्द हो जाएगा।

(4) जहां निवास का प्रावर्तन पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कारण रद्द किया जाता है, अधिकारी को संबंधित निदेशक के विवेक पर किसी अन्य स्थान पर उसी वर्ग का दूसरा निवास प्रावर्तित किया जा सकेगा।

(5) संबंधित निदेशक उपनियम (1) से (4) के अधीन सभी या उनमें से कोई कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा और उन अधिकारों को

जो नियमों और उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अधिक भवधि के लिए निवासीय आवास के प्रावर्तन के लिए अपास भी घोषित करेगा।

(6) वे सरकारी सेवक, जो इन नियमों के उपबंधों का अतिव्रमण करते हैं, सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय आचरण के आधार पर, जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 के नियम 3(1) (iii) का अतिव्रमण अन्तर्बलित होगा, संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उपयुक्त शक्ति के अधिरोपण के लिए अनुशासनिक कार्यवाही का वाया होगा।

प्र.नि. 317-कज-21 प्रावर्तन के रद्दकरण के पश्चात् निवास में फिर भी निवास करते रहता

जहां इन नियमों में अन्तर्बिष्ट किसी उपबंध के अधीन प्रावर्तन रद्द किया जाता है या रद्द किया हुआ समझा जाता है और उसके पश्चात् निवास ऐसे अधिकारी, जिसे यह प्रावर्तित किया गया था या ऐसे किसी व्यक्ति, जो उसके माध्यम से दावा करता है के अधिभोग में रहता है या बना रहता है, ऐसा अधिकारी निवास, मेंवालों, फर्नीचर के प्रयोग और अधिभोग के लिए तथा बाग प्रभारों के लिए बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नुकसानी या सदाय करने के लिए वाया होगा।

परन्तु यह कि अधिकारी विशेष दशाओं में संबंधित निदेशक द्वारा मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने या मूल नियम 45-क के अधीन पूल को गई अनुज्ञप्ति फीस के दुगुने, जहां अनुज्ञप्ति फीस की पूर्णता की गई है, जो भी उच्चतर हो के संवाय पर, नियम प्र.नि. 317-कज-12 के अधीन अनुज्ञप्ति भवधि पर 6 मास से अधिक भवधि के लिए निवास प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

प्र.नि. 317-कज-22-इन नियमों को जारी करने के पूर्व किए गए प्रावर्तन बना रहता।

किसी निवास का विधिमान्य प्रावर्तन, जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व और तत्पश्चात् प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में रहता है इस बात के होते हुए भी कि वह अधिकारी, जिसे प्रावर्तन किया गया है, उस टाईप में निवास के लिए हकदार नहीं है इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से किया गया प्रावर्तन समझा जाएगा और इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबंध उस प्रावर्तन और उस अधिकारी को तदनुसार लागू होंगे।

प्र.नि. 317-कज-23-नियमों का निर्वन्धन

यदि इस खंड के नियमों के निर्वन्धन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

प्र.नि. 317-कज 24-नियमों का शिथिलीकरण

सरकार किसी अधिकारी या निवास या किसी वर्ग के अधिकारियों या टाईप के निवासों की दशा में ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे इन नियमों के सभी या किसी उपबंध को शिथिल कर सकेंगी।

प्र.नि. 317-कज-25-शक्तियों या कर्तव्यों का प्रत्यापोजन

सरकार इन नियमों द्वारा उसे प्रवृत्त कोई या सभी शक्तियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना उचित समझे अपने नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी को प्रत्यापोजित कर सकेंगी।

[का. स. 29-41/83-एस एम पी]
वीरेन्द्र कपूर, डेप्ट अधिकारी

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 17th August, 1987

S.O. 2299.—In pursuance of the provisions of Rule 45 of the Fundamental Rules and in supersession of the Allotment of Government Residences in the Survey of India Rules, 1974

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

In Part VIII of the Supplementary Rules, after division—XXVI AG, the following shall be inserted, namely :—

"DIVISION XXVI-AH"

S.R. 317-AH-1 Short Title, Application and Commencement :

- (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences in the Survey of India Estate Rules, 1987.
- (2) These rules shall apply to the allotment of the residences which are primarily intended for the use of Government servants employed in the Survey of India and the Central/Regional Pay and Accounts Offices having accountal jurisdiction with the Survey of India.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S.R. 317-AH-2 Definitions—In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context :

- (a) 'allotment' means the grant of a licence to a Government servant to occupy a residence for use by him as residence in accordance with the provisions of these rules;
- (b) 'allotment year' means the year beginning on the 1st January or such period as may be notified by the Director concerned;
- (c) 'Director concerned' means the Director of Survey of India responsible for administering the Survey of India Estate;
- (d) 'eligible office' means the Survey of India Office and the Central/Regional Pay and Account Offices having accounts jurisdiction with the Survey of India, the staff of which has been declared as eligible for residence under these rules;
- (e) 'Basic Pay' means pay as defined in F.R. 9(21)(a)(i) which excludes Personal Pay, Special Pay, Deputation (Duty) Allowance etc

Explanation—In the case of an officer who is under suspension, the Basic Pay drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the Basic Pay drawn by him immediately before that date, shall be taken as Basic Pay.

- (f) 'family' means the wife or husband, as the case may be and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the officer;
- (g) 'Government' means the Central Government unless the context otherwise requires;
- (h) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules;
- (i) 'priority date' of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible under the provisions of rule S.R. AH-3 means the earliest date from which he has been continuously drawing basic pay relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or a State Government or on foreign service, except for periods of leave :

Provided that in respect of a Type B, Type C or Type D residence, the date from which the officer has been continuously in service under the Central Government or State Government including the periods of foreign service shall be his priority date for that type :

Provided that the past services in the case of re-employed ex-servicemen who have surrendered the defence service terminal benefits on re-employment in Survey of India and whose breaks in service, if any, have been condoned by the Competent Authority, will be taken into account in determining their priority dates. If any officer had more than one break in his service, the above mentioned benefit will be admissible only in respect of the continuous service rendered prior to the last break:

Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of basic pay the officer in respect of higher basic pay taking precedence over the officer in respect of lower basic pay :

Provided also that where the basic pay to or more officers are equal, then the seniority shall be determined with reference to their date of birth, the officer who is older taking precedences over the younger officer;

- (j) 'qualifying appointment' means an appointment, the incumbent of which is required to reside on duty with the Survey of India and the Central/Regional Pay and Accounts Office;
- (k) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Director concerned;
- (l) 'subletting' includes sharing of residences by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person;

Explanation : Any sharing of residence by an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting. The question whether a person is a close relative or not shall be decided by the Director concerned.

- (m) 'temporary transfer' means a transfer which involve an absence for a period of not exceeding four months;
- (n) 'transfer' means a transfer from existing station to any other place or from an eligible office to an ineligible office and includes a transfer or reversion to service under a State Government and also deputation to a post in an ineligible office or organisation ;
- (o) 'Type' in relating to an officer means the Type of residence to which he is eligible under the provisions of rule S. R. 317-AH-3.

S.R. 317-AH-3 Classification of Residences : (1) For the purpose of allotment, the residences are classified as under and save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of a residence of the type shown in the table below :—

Type of accommodation to which entitled	Basic Pay range of officer in the proposed scale of entitlement as on the first day of the allotment year in which the allotment is made
Type A	From Rs. 750-949
Type B	From Rs. 950-1499
Type C	From Rs. 1500-2799
Type D	From Rs. 2800-3599
Type E	From Rs. 3600 and above

(2) An officer eligible to Type E shall also be eligible to the next below Type of residence.

S.R. 317-AH-4—Application for Allotment : (1) Application for allotment of all Types of residences shall be made to the Director concerned through proper channel in such Form and manner and by such date, as

may be specified by the Director concerned on this behalf. The Director shall maintain a waiting list for each type of residence as in rule S.R. 317-AH-3. The waiting list shall show clearly the dates of eligibility for allotment. Allotments shall be made according to the waiting list based on the dates of entitlement.

(2) An officer joining duty on first appointment or on transfer in the Survey of India and CPAO/RPAO may submit his application in the prescribed proforma to the Director concerned within a month of his joining duty.

S.R. 317-AH-5—Allotment of Residences. Save as otherwise provided in these rules, a residence, on falling vacant, will be allotted by the Director concerned preferably, to an applicant desiring a change of accommodation in that Type under the provisions of S.R. 317-AH-14 and if not required for that purpose, to an applicant without residence in that Type having the earliest priority date for that Type of residence subject to the following conditions, namely :—

- (i) The Director concerned shall not allot a residence of a Type higher than to what the applicant is eligible for.
- (ii) The Director concerned shall not compel any applicant to accept a residence of a lower Type than to what he is eligible for under S.R. 317-AH-5.
- (iii) The Director concerned on request from an applicant for allotment of lower Type of residence, might allot to him a residence next below the Type for which the applicant is eligible on the basis of his priority date for the same.

(2) The Director concerned may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same Type or in emergent circumstances an alternative residence of the Type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

S.R. 317-AH-6—Priority Allotment : (1) Appropriate residences may be reserved for the officers with the ranks of Directors and above. If any of these is not occupying it, the same may be allotted to an authorised person on the waiting list on the conditions that he shall vacate it on 30 (thirty) days notice if required for occupation by any of the said officers.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the following pool with appropriate residences reserved shall be maintained separately by the Director concerned namely :—

- (i) Priority Pool which shall comprise of the following officers:—

Assistant Surveyor General, two Medical Officers including one lady Medical Officer, Security Supervisors, Assistant Security Supervisors, Fire Officer, Senior Most Leading Hand Fireman, vehicle Superintendent, the officer deputed to carry out the duties of O.C. Estate/Estate Officer, four M.T. Drivers at Dehradun and two M.T. Drivers in other station, one driver Fire Engine and 50 per cent of Fire Staff, 40 per cent Guards, 40 per cent Safai-walas.

- (ii) The Director concerned will ensure that adequate number of staff from each of the above category have been provided accommodation in case the number and type of residences are not sufficient for the entire pool.
- (iii) The number of types of residences to be placed in this pool shall be determined by the Government from time to time.
- (iv) The officers shall be entitled to allotment of accommodation in the said pool in the type next below the type of which they are entitled under the provisions of S.R. 317-AH-3. However this provision would not apply to those officers who are already entitled to Type II residence.

- (v) If an officer is not eligible for any residence in the pool being available for occupation, the Director

concerned may allot it to an authorised person on the waiting list on the condition that he shall vacate it on 30 days notice if required for occupation by any of the said officers.

(3) The Director concerned may also allot suitable residences to the personnel of other Government Departments whose presence is considered necessary and essential and maintenance for the upkeep of the Estate.

Provided that this allocation will be subject to such safeguards as may be considered necessary at the time in the interest of the Survey of India and the Director concerned if he deems fit may cancel such allotment.

The order of priority of claims for residences shall be as follows :

- (a) Personnel of the Survey of India/CPAO/RPAO
- (b) Personnel of the Central Public Works Department
- (c) Personnel of other Government Departments as may be decided by the Director concerned.

S.R. 317-AH-7—Government Servant to Stay Himself and Provisions for Vacant Residences. (1) When sufficient appropriate residences are not available a higher or lower Type of residence may be allotted, when such allotment is considered advantageous in the interest of public work, on the specific understanding that the individual(s) shall have to move into appropriate residence as and when it become available. The licence fee shall be recovered according to rules in force.

(2) The Government will be required to stay at the residence himself. He may reside outside on leave or due to any other reasons for not more than six months only with the prior permission of the Director concerned who may cancel the allotment and arrange to evict him, if such permission is not taken :

Provided that the allotment shall not be cancelled except after giving to the Government servant a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(3) If any residence remains unallotted owing to no officer of the Survey of India being available for occupation, the Director concerned will allot it to a Government servant working in a Department other than the Survey of India whom he considers suitable, provided that the allottee gives an undertaking in writing that he shall pay the prescribed licence fee and vacate the residence within two months from the date of receipt of a notice that it is required for the use of an officer of the Survey of India.

(4) When no officer in the correct pay scale is on the waiting list a vacant residence shall be offered :—

- (a) First to an officer drawing higher basic pay on the waiting list for the next higher class provided he agrees to vacate it when a residence of the appropriate Type falls vacant to which his place on the waiting list entitles him, then,
- (b) to officers drawing highest basic pay in the waiting list for the next class below if they volunteer for it and are agreeable to vacate it whenever required by the Director concerned and are reallocated, appropriate residence to shift into.

The licence fee for higher Type of residence shall be standard licence fee under F.R. 45A, without limiting it to 10 per cent of the basic pay of the allottee.

S.R. 317-AH-8—Allotment to Husband and wife. Eligibility in Cases of officers who are married to each other : (1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall within one month of the marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period, and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Director concerned may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Central Government, the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to (4) :—

If a wife or husband, as the case may be who is, an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(6) Where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply, marry each other, any one of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

(7) If a residence is not surrendered as required under sub-rule (5) or (6), the allotment of the residence in the Survey of India Estate shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

S.R. 317-AH-9—Out of Turn Allotment : (1) The allotment of a residence may be made by the Director to the son or daughter or wife/husband or father or mother of a Government servant in occupation of Government residence, who superannuates from or dies while in Government service, provided that the said relative is himself/herself a Government servant employed in the Survey of India and CPAO/RPAO or secures an appointment therein within 12 months of the death, in harness of the Government servant and had stayed with the Government servant who superannuates or dies while in service, for a minimum period of 3 years immediately prior to the date of such superannuation or death. He/She may be allotted the same residence which the allottee was occupying if he/she is also eligible for the same type or higher type of residence. In other cases, he/she may be allotted the type of residence to which he/she is actually eligible provided that such a residence is vacant and that in case such a residence is not vacant he/ she may be allotted a residence immediately next below type if this is acceptable to him/her.

(2) The Director concerned may also make out of turn allotment on the basis of recommendation of a House Allotment Committee on medical grounds where the Government servant or member of his family is suffering from T.B./Cancer and in the opinion of District Medical Officer/Civil Surgeon/such other specialist as may be stipulated it is necessary to provide him a suitable accommodation. For the purpose of such out of turn allotment at Dehradun, the Committee will consist of the following officers :

- | | |
|---|-----------|
| (i) Director (Administration and Finance) | —Chairman |
| (ii) Director, Map Publication | —Member |
| (iii) Deputy Director dealing with the Estate matters | —Member |

Similarly at Hyderabad the Committee will consist of the following officers :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| (i) Senior Director, CST & MP | —Chairman |
| (ii) Director, STI | —Member |

(iii) Deputy Director dealing with the Estate matters —Member

At other places the Allotment Committee will consist of the following officers :

- | | |
|---|-----------|
| (i) Director concerned | —Chairman |
| (ii) Deputy Director dealing with Estate matters | —Member |
| (iii) Deputy Director from any other Directorate at the station/O.C. at the station | —Member |

The recommendations of the Medical Authorities concerned be considered on their merits. There can be no mandatory instructions that their opinion and views should be accepted.

(i) The House Allotment Committee should meet at least once a quarter and decide pending applications for out of turn allotment. The applicants whose applications are accepted or rejected by the House Allotment Committee should be duly informed of the decision individually. A list of applicants who have been sanctioned out of turn allotments should be arranged in accordance with the dates of receipt of their applications and placed on the notice board.

(ii) Appeals—Any appeal against the decision of the House Allotment Committee will be decided personally by the Surveyor General and his decision in such cases will be treated as final.

(iii) If any official's appeal has been accepted by the Surveyor General then his name will also be noted in the list below the last name approved by the House Allotment Committee at their meeting in which the case of the appellant was rejected.

(iv) When quarters become available for allotment to officials on out of turn basis, the same will be allotted in the order on the waiting list referred to in (i) above.

(v) On refusal of an allotment made on out of turn basis, the name of the official concerned should be removed from the waiting list for out of turn allotment of quarters. However, in cases where on a representation from the affected official, the House Allotment Committee decides to revive the sanction, the official should again be allotted a quarter on out of turn basis.

(vi) The cases in which out of turn allotment have been sanctioned by the House Allotment Committee but actual allotment have not been made within six months of the date of sanction, should be reviewed by the House Allotment Committee on the expiry of six months and names of those officials should be removed from the approved waiting list in whose cases the circumstances asking for out of turn allotments might have changed and in the changed circumstances out of turn allotment is not justified.

(vii) Every third quarter falling vacant should be reserved for allotment out of turn basis on account of (a) Allotment to be made to the close relative of a Government servant who superannuates from or dies while in Government service in accordance with the provisions contained in sub-rule (1); and (b) on Medical grounds where the Government servant or a member of his family is suffering from TB/Cancer as per the provisions of sub-rule (2). This reservation is subject to the condition that the number of quarters so reserved should not exceed the number of officials on the waiting list for out of turn allotment. In case no out of turn allotment is pending then that reserved quarter will go for allotment under the general category.

(viii) To determine the type of quarter to be allotted the pay of the official drawn by him at the time of submitting application for out of turn allotment should be taken into consideration. All pending out of turn sanction for which allotments have not been made within a year the pay revision, if any which might have taken place during that period should be accounted for to determine the type of quarter to be allotted.

(ix) The officials who have been sanctioned out of turn allotments should be provided quarters of the class next to that of their entitlement. The direct recruits who join the department in the clerical and allied cadres and who are entitled to type II quarters should, however, be given type II quarter on out of turn basis. But the officials entitled to type II quarters who were once eligible for type I

quarters, should be given type I quarters on out of turn basis.

S.R. 317-AH-10—Non Acceptance of Allotment of offer or Failure to occupy the Allotted Residence after acceptance.—(1) If an officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower Type of residence is allotted or offered, a residence of the Type for which he is eligible under rules 317-AH-3, or of which he has applied under these rules, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely:—

- (i) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher Type of residence;
- (ii) while retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under F.R. 45A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation whichever is higher.

S.R. 317-AH-11—Provision Relating to Licence Fee :

(1) (a) Where an allotment of residence or alternative residence has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment letter, whichever is earlier.

(b) An officer who after acceptance fails to take possession of that residence within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days, provided nothing contained herein shall apply where the Central Public Works Department certifies that the residence was not yet ready for occupation and as a result thereof the officer did not occupy the residence within the period aforesaid.

(2) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

S.R. 317-AH-12—Personal Liability of the Officer for Payment of Licence Fee till the Residence is Vacated and Furnishing of Survey by Temporary Officers : (1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residence alongwith the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacated possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu thereof.

(3) If the surety ceases to be in Government service or become insolvent or ceases to be available for any other

reasons or withdraws his guarantee, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall unless otherwise decided by the Director concerned, be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

(4) Licence fee shall be recovered monthly by the Drawing and Disbursing Officer in the Survey of India, from the pay bills of the officers concerned, on the authority of the demand statement furnished by the Director concerned. The amounts specified by the Director concerned in the demand statements shall be recovered in full without prior reference to the Government servant concerned.

S.R. 317-AH-13—Period for which Allotment Subsists and the Concessional Period for further Retention : (1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until

- (i) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office;
- (ii) it is cancelled by the Director concerned or is deemed to have been cancelled under any provisions in these rules ;
- (iii) it is surrendered by the officer; or
- (iv) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in the column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the bonafide use of the officer or members of his family.

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
1	2
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorised absence without permission.	1 month
(ii) Retirement or terminal leave	4 months
(iii) Death of the allottee	6 months
(iv) Transfer to a place outside existing place	2 months
(v) Transfer to an ineligible office on the station	2 months
(vi) On proceeding on foreign service in India	2 months
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside INDIA.	4 months
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave)	For the period of leave but not exceeding four months
(xi) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under F.R. 86	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of four months inclusive of the period permissible in the case of retirement.

1	2
(x) Study leave or deputation outside INDIA	For the period of leave but not exceeding six months.
(xi) Study leave in INDIA	For the period of leave but not exceeding six months.
(xii) Leave on medical grounds	Full period of leave.
(xiii) On proceeding on training	For full period of training

Explanation—I : Where an officer on transfer on foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) and (vii) or for the period of leave, whichever is more.

Explanation—II : Where an order of transfer on foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation I shall count from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office.

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowance, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office, within the period specified in the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules :

Provided that if the basic pay of the officer on such re-employment do not entitle him to the Type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower Type of residence.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (5), when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may require the Director concerned to cancel the allotment of residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the Director concerned shall act accordingly.

S.R. 317-AH-14-Surrender of an allotment and period of notice—(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director concerned at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director concerned or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days provided that the Director concerned may accept a notice for a shorter period if he is satisfied that the prescribed notice could not be given owing to circumstances beyond the control of the allottee.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

S.R. 317-AH-15-Change of residence.—(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same Type. Not more than one change shall be allowed in respect of one Type of residence allotted to the officer.

(2) Change shall be offered in the order of applications for the same received in the office of the Director concerned.

(3) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment he shall not be considered again for a change of residence of that Type.

(4) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (1) of S.R. 317-AH-11 in addition to the normal licence fee under F.R. 45-A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

S.R. 317-AH-16-Mutual exchange of residence—Officers to whom residence of the same Type have been allotted at the same station under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty and to reside in their mutual exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-AH-17—Subletting and sharing of residences.—(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses and garages appurtenant thereto except with the employees of the Central Government eligible for allotment of residence under these rules. The servants' quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director concerned.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate, in the residence any other officer eligible to share Government residence as a caretaker for the period specified in rule S.R. 317-AH-12, but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by the Government beyond fair wear and tear.

(4) The sharing of residence is allowed only with the prior permission of the Director concerned.

S.R. 317-AH-18-Transfer to non family station.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bonafide educational needs of his children, he may be allowed, on request to retain the residence on payment of licence fee under F.R. 45-A, till the end of the current academic session of his children.

S.R. 317-AH-19-Responsibilities for maintenance of residence.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Director concerned. Such officer shall not grow any tree, or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree in a garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Director concerned. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Director concerned at the risk and cost of the officer concerned.

(2) The officer to whom a residence has been allotted shall be required, when he enters into occupation of the residence and when he vacates it, to sign an inventory of the furniture (if provided in the residence) and fittings.

(3) The officer to whom a residence has been allotted shall not keep any cattle in or in the vicinity of the residence.

S.R. 317-AH-20-Consequences of breach of rules and conditions—(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Director concerned considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion

thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of the rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Director concerned considers to be improper or conducts, himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his religious or has knowingly furnished incorrect information in any application on written statement with a view to securing the allotment the Director concerned may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence :

Provided that the allotment of the residence shall not be cancelled except after giving to the officer a reasonable opportunity of being heard in person.

Explanation—In this sub-rule the expression 'officer' includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any other person claiming through the officer.

(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses and garages appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him, be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F.R. 45-A. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case shall be decided by the Director concerned on merits. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Director concerned.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee and any other person residing with him therein, to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders, for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Director concerned may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) The Director concerned shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) and also declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

(6) Those Government servants who violate any provision of these Rules, shall be liable for disciplinary action for imposition of a suitable penalty on grounds of unbecoming conduct of the Government employee involving violation of Rule 3(1)(iii) of the C.C.S. Conduct Rules, 1964 by the Disciplinary Authority of the Government servant concerned. S.R. 317-AH-21-Overstayal in residing after cancellation of allotment—Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by Government from time to time.

Provided that an officer, in special cases may be allowed by the Director concerned to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A or twice the pooled licence fee under F.R. 45-A where pooling of licence fees has been done, whichever is higher, for a period not exceeding six months beyond the period permitted under Rule S.R. 317 AH-13.

S.R. 317-AH-22-Continuance of allotments made prior to the issue of these rules—Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules and under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and the officer accordingly.

S.R. 317-AH-23-Interpretation of rules.—If any question arises as to the interpretation of these rules then it shall be decided by the Government.

S.R. 317-AH-24-Relaxation of rules.—The Government may for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

S.R. 317-AH-25-Delegation of powers or functions.—The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[F. No. 29—41/83-SMP]
VIRENDRA KAPOOR, Desk Officer

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का.आ. 2300:— 29 जून, 1987 को जारी की गई अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्वारा नागर विमानन मंत्रालय में विनीय सलाहकार को तत्काल से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के निदेशक मण्डलों से पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[का. सं. एवी 18013/2/86-एए]

शान्तनु कसल, उप वि

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th August, 1987

S.O. 2300.—In continuation of the Notification issued on 29th June, 1987, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953) hereby appoints the Financial Adviser in the Ministry of Civil Aviation as ex-officio Director on the Boards of Indian Airlines and Air-India, with immediate effect.

[F. No. AV. 18013/2/86-AA]
SHANTANU CONSUI, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

का.आ. 2301:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 431 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने पुस्तक टेलीफोन केन्द्र, आन्ध्रप्रदेश सचिवालय, में दिनांक 1-9-1987 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-8/87-पोएचबी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 13th August, 1987

S.O. 2301.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-9-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Puttur Telephone Exchange, Andhra Pradesh Telecom. Circle

[No. 5-8/87-PHB]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

का.आ. 2302:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने मेथिया टेलीफोन केन्द्र, वेस्ट बंगाल सचिवालय, में दिनांक 30-8-1987 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-17/87-पोएचबी]

पी. आर. फाउंडा, महा. महा-निदेशक (पोएचबी)

New Delhi, the 14th August, 1987

S.O. 2302.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 30-8-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sainthia Telephone Exchange under West Bengal Telecom. Circle.

[No. 5-17/87-PHB]

P. R. KARRA, Asstt. Director General (PHB)

अम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1987

का. आ. 2303.—धातुसादक खान विनियम, 1961 के विनियम 11 के उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के अम मंत्रालय की दिनांक 21 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2847 का अधि-क्रमण करने हुए, केन्द्रीय सरकार एक खनन परीक्षा बोर्ड गणित करती है, जिसका अध्यक्ष मुख्य खान निरीक्षक होगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- | | |
|---|---------|
| 1. मुख्य खान निरीक्षक (पदेन)
(जिन्हें अब खान सुरक्षा
महानिदेशक के रूप में
पुनर्पदनामित किया गया है) | अध्यक्ष |
| 2. श्री एम. के. बत्रा,
प्रबंध निदेशक,
यूरेनियम कारपोरेशन,
आफ इंडिया लिमिटेड,
डाकघर जादुगुडा खान,
जिला सिंहभूम—832102 | सदस्य |
| 3. श्री एम. ए. खान,
निदेशक, (सक्रियाएं)
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड,
इण्डस्ट्री हाउस,
10, कामाक स्ट्रीट, कलकत्ता—17 | सदस्य |
| 4. श्री के. एल. सुथरा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मैंगनीज और इरिया लिमिटेड,
3. माउण्ट रोड एक्सटेंशन,
पी. ओ. बाक्स नं. 34,
नागपुर—440001 | सदस्य |
| 5. श्री एन. बी. पालीवाल,
निदेशक (खनन सक्रियाएं)
हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड
6-नया फतेहपुरा, उदयपुर—313001 | सदस्य |
| 6. श्री जे. एल. चक्रवर्ती,
प्राचार्य खनन और अध्यक्ष,
खनन और भूविज्ञान विभाग,
बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, शिबपुर,
डाकघर बोटानिक गार्डन,
जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल | सदस्य |

[फा. सं. बो-23012/1/87-खान-1]

भार. टी. पाण्डेय, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th August, 1987

S.O. 2303.—In exercise of the powers conferred by Sub-Regulation (1), (2), (3) and (4) of regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2847 dated the 21st August 1984, the Central Government hereby constitutes the Board of Mining Examinations with the Chief Inspector of Mines as its Chair-

man and appoints the following persons as members of that Board for a period of three years amcy:—

- | | |
|--|----------|
| 1. Chief Inspector of Mines
(Ex-officio)
(Since re-designated as
Director-General of Mines
Safety).. | Chairman |
| 2. Shri M. K. Batra,
Managing Director,
Uranium Corporation of
India—Limited,
P.O. Jaduguda Mines,
Distt. Singhbhum-832102. | Member |
| 3. Shri M. A. Khan,
Director (Operations),
Hindustan Copper Limited,
Industry House, 10 Camac Street,
Calcutta-17. | Member |
| 4. Shri K. L. Luthra,
Chairman-cum-Managing Director,
Manganese Ore India Limited,
3-Mount Road Extension,
P.O. Box No. 34,
Nagpur-440001. | Member |
| 5. Shri H. V. Paliwal,
Director (Mining Operations),
Hindustan Zinc Limited,
6-New Fatehpura,
Udaipur-313001. | Member |
| 6. Shri J. L. Chakravarty,
Prof. of Mining and Head of
the Department of Mining and
Geology,
Bengal Engineering College,
Shibpur,
P.O. Botanic Garden,
Distt. Howrah—West Bengal. | Member |

[F. No. V-23012/1/87 M.I.]
R. T. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

का. आ. 2304.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3948 दिनांक 14-11-1986 के क्रम में, हिन्दुस्तान एन्टीबायोफिटका लिमिटेड, पिम्परी, पुणे को पहली जुलाई, 1986 से 30 जून, 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदाधिकारी—
 - (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए दो सई किसी विवरणी की विशिष्टियों को संस्थापित करने के लिए; या
 - (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या
 - (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधाओं को, जो ऐसी प्रमुविधाएँ हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

- (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसकी अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय वा अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस.-38014/21/86-एस. एस.-I]

ए. के. भट्टराई, अव्वर सचिव

स्पष्टीकरण गोपन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 10th August, 1987

S.O. 2304.—In exercise of the power conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3948, the Central Government hereby exempts the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Pune, from the operation of the said Act for a period of one year with effect from 1st July, 1986 upto and inclusive of the 30th June, 1987.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of:—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to:—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/21/86-SSI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1987

का.आ. 2305:—मैसर्स—तमिलनाडु हैण्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., नं. 2, हवीबुल्ला रोड, टी.एन. नगर, मद्रास (टी.एन./9055) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 15) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1115 तारीख 14-3-84 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 1-4-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-3-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रिय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (अ) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभागों का सन्दाय आवि भों है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कमो उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले हो गवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यावत् सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिस में कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उस दशा में सन्देश्य होता। जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्ति होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारिख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिराम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/7/84-पी. एफ. 2 (एन. एस-2)]

New Delhi the 19th August, 1987

S.O. 2305.—Whereas Messrs. Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited, No. 2, Habibullah Road, T.N. Nagar, Madras-17 (TN/9055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1115 dated the 14-3-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-4-1987 up to and inclusive of the 31-3-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns, to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/7/84-PF.II(SS.II)]

का० आ० 2306---मैसर्स नगर अरविन को-ऑपरेटिव बैंक लि०, ग्रहममदनगर, सैन्ट्रल बैंक रोड, पो० बा० नं० 7, ग्रहममदनगर-4149001 (एम.एच./7148) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 919 तारीख 5-3-1984 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 17-3-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 16-3-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के अन्तर्गत (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रचारों का सन्दाय प्राप्ति भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में राहतें होंगी जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में अग्रफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जायने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्कार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/10/84-पी.एफ. 2(एस. एस-2)]

S.O. 2306.—Whereas Messrs. Nagar Urban Co-operative Bank Limited, Ahmednagar, Central Bank Road, P.B. No. 7, Ahmednagar-41001 (MH/7148) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 919 dated the 5-3-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17-3-1987 upto and inclusive of the 16-3-1990

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/neminee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014/10/84-PF.IISS.II]

का० आ० 2307--मैगले पूना इन्डस्ट्रियल होटल लि०, 11, कोरे- गांव रोड, पुणे-411001 (एम. एन./8864) (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे-वेगले कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हममें हमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभोग्य है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिवृत्ति का ख्या का० आ० 1974 तारीख 19-5-1984 के अनुसूचन में और हमसे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की 16-6-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 15-6-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आप्रकृत महाराष्ट्रा को ऐसी नियंत्रण भेजेगा और ऐसी लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसी निरीक्षण पत्रों का पन्नेक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणालय में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण पत्रों का सन्दाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का बटन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब वभी उनसे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुपेक्षित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविशेष अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी सीमा में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तरीके की भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यर्थ प्रयत्न की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्पश्चात् और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/30/84-ती एफ. II एम. एम-2]

S.O. 2307.—Whereas Messrs. Poona Industrial Hotel Limited, 11, Koregaon Road, Pune-411001 (MH/8864) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable

to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1974 dated the 19-5-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 16-6-1987 upto and inclusive of the 15-6-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 1968 dated the 19.5.1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 16.6.1987 upto and inclusive of the 15.6.1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of death, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S 35014/3284-FPG(SS.II)]

का. आ. 2309.—मैसर्स-गुजरात इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन, तीसरी मंजिल, फादिया चैम्बर्स रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद जं. (जे./11819), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपग्रह अभियोग, 1952 (1952 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप मंडल बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1521 तारीख 21-4-1984 के अनुसरण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 5-5-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 4-5-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय केन्द्रों का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रसारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मंदा वाता अतः, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम उचित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को मन्वत करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन कर्मचारियों को उपलब्ध पाँच वरग जति हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की दि की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशस्त उपलब्ध फायदे को प्राप्त करने में अधिक प्रवृत्त हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वक़्त में मन्वत होती जब वह उक्त स्कीम के

अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नार्मानिश्चितों को प्रविष्टि के रूप में दोनों स्कीमों में प्रवेश के समान रूप का सहाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम में उपस्थितों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत के बिना नहीं किया जायेगा, और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत से इन कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्कीम के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापित होने अपना चयन है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी नति में कम हो जाते हैं, तो वह छूट रहे की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदत्त प्राप्ति के भौतिक प्रमाणों में कमी करने में असमर्थ होता है, और प्राप्ति का व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो छूट रहे जा सकता है।

11. नियोजक द्वारा प्रविष्टि में सम्भाव्य विवाद किन्हीं कारणों की दशा में उन मृत सदस्यों के नार्मानिश्चितों या विधिक वारिसों को जा यदि वह छूट रहे की गई हो तो उस स्कीम में अन्तर्गत आने बीमाफायदों के सम्बन्ध में अनुरोधित नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रीमान्कृत राज के हकदार नार्मानिश्चितों/विधिक वारिसों को उन राशि का सम्बन्ध तत्पश्चात् से प्रौर प्रत्येक वर्ष में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सन्ख्या एस-35014/16/84-पी. एफ.जी/एस एस-4-2)]

ए. के. अट्टाराली, अवर सचिव

S.O. 2309—Whereas Messrs Gujarat Industrial Development Corporation, 3rd Floor, Vadia Chambers Road, Nargang Pura, Ahmedabad (GJ/11819) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1521 dated the 21-4-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 5-5-1987 upto and inclusive of the 4-5-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[N.S. 35014/16/84-PF (SS.II)]

A K BHATTARAI, Under Secy

(आय विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का. आ. 2310—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार वसुन्धरा बास-जारा कोलियरी मैनेजर्स भारत कॉलेज कोल लि., डाक बासजोरा (घन-बाज) के प्रबन्धन में सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच,

प्रत्यक्ष में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में कन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रकाशित करती है, जो कन्द्रीय सरकार का 1-8-1987 को प्राप्त हुआ था।

AND

Their workmen

The dispute between the parties to the above reference most respectfully sheweth—

(1) That the above dispute has been amicably settled on the following terms—

Terms of the settlement

- That the concerned lady Smt. Sonapati Kamin will be enrolled as 'Badli' Sweepress and she will be provided job accordingly
- That the concerned lady should report for her duties within 15 days from the date of signing of this settlement
- That she will not claim any wages or benefit for the period of idleness

(2) That in view of the above settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the terms of the settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen

I I of
Smt. Sonapati Kamin

For the Employer
Sd—

नई दिल्ली 18 अगस्त 1987

का प्र. 2311—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अन्तर्गत में कन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रकाशित करती है, जो कन्द्रीय सरकार का 1-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi the 18th August 1987

S.O. 2311—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 6 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act 1947

PARTIES

Employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen

APPEARANCES

On behalf of the workmen Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary Janta Mazdoor Sangh

On behalf of the employers Shri R. S. Murthy, Advocate
STATE Bihar INDUSTRY Coal.

Dhanbad the 27th July, 1987

AWARD

The Govt. of India Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the

(Department of Labour)

New Delhi the 12th August 1987

S.O. 2310—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sendra Bansi Colliery of M/s. BCC Ltd. P.O. Bansi Distt. Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 31st August 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 126 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act 1947

PARTIES

Employers in relation to the management of Sendra Bansi Colliery of M/s. BCC Ltd. and their workmen

APPEARANCES

On behalf of the workman Shri D. Mukherjee Advocate

On behalf of the Employers—Shri B. Tosh Advocate

STATE Bihar INDUSTRY Coal.
Dhanbad the 25th July 1987

AWARD

The Government of India Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. T 24012 (96)185 D IV(B) dated the 22nd February 1986

SCHEDULE

Whether the action of the management of Sendra Bansi Colliery of M/s. BCC Ltd. P.O. Bansi Distt. Dhanbad in terminating the services of Smt. Sonapati Kamin wife of Shri Manoj Dom Substute Sweepress from August, 1984 is justified? If not to what relief the workman is entitled?

In this reference both the parties appeared and filed their respective W.S. etc. The case proceeded along with its course. Ultimately on 15-7-87 both the parties appeared before me and filed a memorandum of settlement. I have gone through the said settlement and I find that the terms contained therein are fair proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the settlement which forms part of the Award as annexure

28.7.87

I. N. SINHA Presiding Officer
(N.T. 24012/96-85-D IV(B))

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 126 of 86

Employers in relation to the management of Sendra Bansi Colliery.

I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(44) 84-DIV(B), dated, the 18th January, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bagdigi Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad in dismissing Shri Shibu Bouri from service while under treatment, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workman is that the concerned workman Shri Shibu Bouri was working as permanent Prop. Mazdoor for a long time in Bagdigi Colliery of M/s. B.C.C.L. During his services he suffered from T. B. On 19-9-80 the Medical Officer of Bagdigi Colliery declared him to a patient of T.B. The management forwarded him to Coal Mine Welfare Organisation's Central Hospital at Jagjiwan Nagar, Dhanbad for his treatment where he continued to receive treatment in the hospital for T. B. In the initial stages he was receiving treatment as an Outdoor Patient and had not been kept on sick roll but was allowed to perform his duties. When the condition of his health deteriorated considerably he was lying ill in a precarious condition and was confined to bed. The attending physician advised him complete bed rest from 9-12-82 as he was not in a position to perform his duties while suffering from a serious disease of T.B. The management of Bagdigi Colliery by a Memo dt. 24-11-83 issued an order of his dismissal from service with effect from 25-11-83 while he was still under treatment under the Central Hospital, Dhanbad. The management had ordered for the dismissal of the concerned workman on the alleged ground of continuous absence without permission and without satisfactory cause for more than 10 days under clause 27(16) of the Standing Orders after holding an ex parte domestic enquiry. The management held an ex parte domestic enquiry in violation of the principles of natural justice and disciplinary authority did not apply his mind to the extenuating circumstances of the case. When mutual effort for settlement relating to the demand of reinstatement of service of the concerned workman ended in failure the matter in dispute was referred to the ALC(C), Dhanbad. During the course of discussion in the conciliation proceeding it was established by the medical certificate that the concerned workman was suffering from T.B. and was under the treatment under the Central Hospital, Dhanbad and was not in position to join his duties without declaration of fitness by the T. B. specialist Medical Officer (T.B.) Central Hospital, Dhanbad. Thus the action of the management by way of dismissal of the concerned workman from service was wrongful and unjustified and the management of M/s. BCCL acted arbitrarily and whimsically in not reinstating the concerned workman. The above mentioned facts were brought to the notice of the management prior to and after the dismissal of the concerned workman from service but even then the concerned workman was not reinstated in service and his dismissal was arbitrary, illegal, malafide, an act of victimisation and an instance of unfair labour practice on the part of the management of BCCL as the reality of the circumstances were deliberately ignored. It was further proved that it is held that the action of the management was wholly unjustified and the management may be directed to reinstate the concerned workman with full back wages and other benefit which may be available to him.

The case of the management is that the concerned workman who was employed in Bagdigi Colliery as Prop Mazdoor absented from duty with effect from 9-12-82 without any intimation or permission from the management and without any satisfactory cause. Such absence of the concerned workman from duty was authorised and was a misconduct under the Standing Orders 27(16) of the Certified standing orders of the colliery. The concerned workman was issued with a chargesheet by the Agent, Bagdigi colliery who is also the Supt. of Mines of the colliery on 10-7-83. The concerned workman received the chargesheet and submitted his explanation which was duly considered by the Agent of Bagdigi Colliery but the explanation was found to be unsatisfactory. The Agent of Bagdigi colliery decided for detailed enquiry into the chargesheet issued to the concerned workman and issued a letter dt. 1-9-83 appointing Shri R. N. Ghosh,

St. P.O. Bagdigi colliery as the enquiry Officer. In the same letter it was mentioned that the enquiry would be held on 4-9-83 at 10.00 A.M. in the office of the Manager, Bagdigi colliery. When the said letter was offered to the concerned workman he refused to accept it. Thereafter the enquiry officer issued further letter dt. 5-9-83 to the concerned workman directing him to attend the enquiry on 9-9-83 at 10.00 A.M. but the concerned workman refused to receive this letter also. Considering the above position the enquiry officer decided to hold the enquiry ex parte. The enquiry officer accordingly held the enquiry ex parte on 9-9-83. The management's witnesses were examined whose depositions were recorded by the Enquiry Officer. The attendance register and Bonus registers were also produced during the enquiry proceeding to establish the absence of the concerned workman without any intimation to or permission of the management. The enquiry officer came to the conclusion on the materials placed before him that the charge framed against the concerned workman was fully established and he submitted his report accordingly. The report of the enquiry officer was considered by the Agent of Bagdigi colliery and he agreed with the findings of the enquiry officer and recommended for the dismissal of the concerned workman from service. The General Manager/Chief Mining Engineer of Lodna Area in which Bagdigi colliery falls approved the dismissal of the concerned workman and thereafter the concerned workman was dismissed from service by the Agent/Suptd. Mines Bagdigi colliery by Order dt. 24-11-83. It was submitted behalf of the management that the ex parte enquiry held by them and subsequently the action taken is perfectly justified under the facts and circumstances of the case. The concerned workman had not at any time taken the plea that he was under the treatment for T. B. as such his dismissal from service was justified and he is not entitled to any relief.

The management in its W.S. stated that as the concerned workman was dismissed from service after holding domestic enquiry into the charges framed against him, it first be decided as a preliminary issue whether the domestic enquiry was fair and valid and in accordance with the principles of natural justice. The management pressed the said issue and accordingly the Tribunal decided the preliminary issue regarding the fact whether the domestic enquiry held into the charges against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principles of natural justice. The management had produced all the papers regarding the enquiry proceeding and they were marked Ext. M-1 to M-11. The management had examined two witnesses for the decision of the said preliminary issue. By the order dt. 14-8-85 this Tribunal held that the enquiry proceeding held against the concerned workman was not fair and proper and accordingly the management were given liberty to adduce evidence afresh in support of their case and the concerned workman was also given opportunity to adduce his evidence in defence.

The point now for determination is whether the dismissal of the concerned workman was justified. In this connection it has to be seen whether the workman have been able to establish that the concerned workman had satisfactory cause for his absence.

The management examined two witnesses namely MW-3 and M-4 on the merit of the case. The workman examined one witness in order to establish their case and produced documents which are marked Ext. W-1 to W-7. The management also exhibited one document which is marked as Ext. M-12.

Ext. M-1 is the chargesheet dt. 10-7-83 which is as follows:-
"You have been absented from your duty/service w.e.f. 9-12-82 without any intimation or permission from the authority concerned."

and as such it was an act of misconduct under clause 27 of the Standing Orders as he was in continuous absence without permission and without satisfactory cause for more than 10 days. The fact that the concerned workman had absented from duty with effect from 9-12-82 for more than 10 days is admitted. The Attendance Registers are Ext. M-11 to M-112. Ext. M-11 is for the period from 19-9-82 to 18-12-82. It shows that the concerned workman Shibu Bauri was present during that period till 5-12-82. Ext. M-11 and

M-11/2 are the attendance registers for the period 13-2-83 to 14-5-83 and 15-5-83 to 13-8-83 respectively. These registers show that the concerned workman was totally absent during that period. The management has produced the attendance Bonus Register Ext. M-10 and M-10/1 in order to prove the absence of the concerned workman with effect from 9-12-82. Bonus Register Ext. M-10 at page 70 and Bonus Register Ext. M-10/1 at page 74 is also leading to the same effect that the concerned workman was absent from 9-12-82 and had absented in the year 1982. M-13 Mid Kamruddin Leave Clerk of Bagdigi colliery has proved the attendance Bonus Registers Ext. M-10 and M-10/1 and has stated that the concerned workman was absent from 9-12-82 and that the concerned workman had not applied for leave or permission prior to his absence. He has further stated that all the leave applications of the workmen are received by him and as such it is expected that if the concerned workman had applied for leave it would have passed through his hands. He has further stated that the concerned workman had not informed that he was being treated of TB in the Central Hospital. He further stated that even if an employee is admitted or is receiving treatment in the hospital, he has to apply for leave and has to produce a certificate for his leave but the concerned workman had not given any such certificate. He was unable to say if the concerned workman had been sent to Bagdigi Hospital or to Central Hospital for his treatment. He has denied that the concerned workman had been wrongly marked absent when he was being treated in the hospital for TB. MW-4 is working as Time keeper in Bagdigi colliery and has proved the Attendance Registers Ext. M-11 and M-11/2 in connection with the concerned workman with reference to the attendance register he has stated that the concerned workman was absent from 9-12-82. The evidence of MW-3 and MW-4 are in consonance with the attendance register and the attendance Bonus registers and there is absolutely no reason to disbelieve the fact that the concerned workman was absenting from 9-12-82. The workman also admitted that the concerned workman was absenting from 9-12-82 and that no application for leave or any information regarding the leave was given by the concerned workman to the management either before or during the course of his absence. Ext. W-6 which is equivalent to Ext. M-12 dt. 4-7-84 shows that the concerned workman Shibu Bouri was attending TB Wing from 19-9-80 and that he was declared fit to do his original duty after 4-7-84 and that he was advised to continue medicine and to attend for check up. Ext. W-5 dt. 6/13/84 is a letter from Shri A.K. Jha, Secretary of Janata Mazdoor Sangh to the Agent, Bagdigi colliery which also shows that the concerned workman was sick from 19-9-80 to 1-7-84 and was under the treatment at Central Hospital Dhanbad. Ext. W-7 is the treatment card which is provided to the patients being treated in the Central Hospital WW-1 Shri O.P. Khanna working as Medical Social Worker has provided the certificate Ext. W-6 and the treatment card Ext. W-7. He has stated that the hospital record of the patient maintained in the hospital gave the details of admission, treatment, discharge etc. and the entry to that effect is made in the treatment card. He has stated with reference to the treatment card Ext. W-7 that the concerned workman became fit for duty on 8-1-81 and thereafter there was no entry in Ext. W-7 from 10-8-81. He has also stated that the concerned workman was advised rest on 10-8-81 for the first time by the doctor but the period of rest was not indicated in Ext. W-7. As stated by WW-1 it appears that after 10-8-81 there was no entry in 1981. Subsequently there was entry in Ext. W-7 and the last entry was dt. 29-6-84 in which there is a note that the concerned workman was fit for duty.

From all the above evidence it is clear that the concerned workman was absenting from 9-12-82 and was continuing absence since then. It holds therefore that the concerned workman had been absenting from duty with effect from 9-12-82 without any information or permission from the authority concerned.

The only point to be considered is whether the concerned workman has been able to satisfactorily establish the cause of his absence. According to the workman the concerned workman was declared as a patient of TB on 19-9-80 and that he had been under the treatment of TB at Central Hospital Dhanbad.

A patient by the M.O. Bagdigi colliery is not specifically treated by the management. The management used produced Ext. M-12 which is the certificate granted by the I.B. specialist (I.B. Wing) of Central Hospital Dhanbad dt. 4-7-84 to support his contention that the concerned workman Shibu Bouri was a quiescent case of TB and that he may be allowed to attend his original duty and that he has to continue medicine and to attend for check up as advised. It is also stated in the certificate that the concerned workman was attending TB Wing from 19th September, 1980. Ext. W-4 dated 1st November, 1984 by the Superintendent Mines Bagdigi colliery to Shri A.K. Jha, Secretary, Janata Mazdoor Sangh is a reply to Shri A.K. Jha's letter Ext. W-5 dated 1/11/84. The Superintendent stated in the letter that as the matter relating to the concerned workman is pending before the ALC(C), Dhanbad for conciliation the management cannot do anything in the matter. Ext. W-5 is the certificate of conciliation report of the ALC(C), Dhanbad to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour. Ext. W-2 is the comment of the workman before the ALC(C), Dhanbad. Ext. W-1 dated 27th March, 1984 is the letter by which the industrial dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad. The union has two documents of importance annexed on behalf of the workman are Ext. W-6 equivalent to Ext. M-12 and the treatment card Ext. W-7. It appears from Ext. W-7 that the concerned workman had not been admitted in the hospital but he was attending the hospital for his treatment and he was being treated as advised from time to time. It will also appear that after 10th August, 1981 the concerned workman was not attending the hospital for sometime and the Attendance Registers and the Bonus Registers show that the concerned workman had attended his duties in 1982 and he had also attended his duties for one day in December, 1982. It appears that as he had improved so he was attending his duties. But subsequently he again suffered from TB and as such he again started attending the hospital for his treatment. Ext. W-6 clearly shows that the concerned workman was attending TB Wing from 19th September, 1980 and that he was declared fit to do his duties with effect from 5th July, 1984. The certificate Ext. W-6 is an admitted document as the management has also filed a photo copy of the same which is Ext. M-12 on the record. The treatment card Ext. W-7 also shows that the concerned workman was suffering from TB and was attending the Central Hospital at Dhanbad for his treatment on advice and it is clear that the concerned workman was suffering from TB and was attending the Central Hospital, Dhanbad for the treatment of his TB. It may be said that the concerned workman has not been able to show his treatment in the Central Hospital since he admitted but overall picture given by Ext. W-6 and W-7 clearly shows that the concerned workman was suffering from TB and was under the treatment of TB at Central Hospital Dhanbad. The fact that the concerned workman was suffering from TB, he has not been denied by the management. On the contrary the management who has produced the certificate of fitness Ext. M-12 shows that the concerned workman was provided a certificate by the I.B. specialist of the I.B. Wing of Central Hospital at Dhanbad.

Admittedly, the concerned workman had not applied for any leave nor had informed the management that he was under the treatment of TB. It appears that the concerned workman was under the misapprehension that as he had been forwarded to the I.B. specialist in the Central Hospital, Dhanbad by the Medical Officer of Bagdigi colliery there was no necessity that he should intimate about his illness to the management. The concerned workman being in the state of illness could not understand the implication of his absence without leave. But the fact remains that in fact the concerned workman was suffering from TB and was absenting from his duties from 9th December, 1982 till he was advised fit to join his duties from 5th July, 1984 and thus the workman have explained satisfactorily about the absence of the concerned workman for reasonable grounds and as such his claim does not appear to be justified. The concerned workman had been marked absent from 20th December, 1982 and he was declared fit to work with effect from 5th July, 1984 and during this period the concerned workman had not worked. Even if the concerned workman had been allowed to join his duties from 5th July, 1984 he would not have been given his wages for the period of his long absence as there is no evidence that the concerned workman could be allowed leave with pay for such a long period and secondly, it is not the custom that the concerned workman will

not be entitled for any wages for the period from 9th December, 1982 to 4th July, 1984.

In the result, I hold that the action of the management of Bagdigi colliery of M/s. B.C.C.L. in dismissing the concerned workman Shri Shibu Bauri from service while under treatment is not justified. The concerned workman is therefore reinstated in his service from the date of his dismissal i.e. with effect from 25th November, 1983. The management is further directed to reinstate the concerned workman within one month from the date of this Award with all the benefits except that he will not get arrears of his pay and allowances from 9th December, 1982 to 4th July, 1984. The concerned workman, however, will be entitled to his wages with effect from 5th September, 1984 the date from which he was declared fit to work by the doctor.

* This is my Award.
Dated, 27th July, 1987

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. I-24012/44/84-D. IV(B)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

का. अ. 2312 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बासुरिया कोलियरी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधकों के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या-2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th August, 1987

S.O. 2312.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Basuria Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 35 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES:

Employers in relation to the management of Basuria Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen—Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary, Janta Mazdoor Sangh.

On behalf of the employers—Shri M. R. Haque, Sr. Personnel Officer.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 28th July, 1987

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. I-20012 (224)/83-D.III(A), dated the 13th January, 1986.

SCHEDULE

"Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh that the 16 workmen mentioned in the Annexure below should be reinstated as Tyndels in the service of Basuria Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. together with back wages and other dues on the alleged ground that their services were wrongfully terminated from 7-12-1980, is justified? If so to, what relief are the workmen concerned entitled?"

ANNEXURE

/Shri

1. Kanhai Rai
2. Md. Zahir
3. Saral Saw
4. Ashok Podda
5. Tribhuvan Singh Kushwaha
6. Ram Das Singh
7. Yamuna Rajbhar
8. Suresh Mallah
9. Moti Ch. Rajbhar
10. Ram Lochan Singh
11. Rama Yadav
12. Sikram Ram
13. Gouri Shankar Saw
14. Mahendra Singh
15. Binod Das
16. Ram Prasad Singh

Both the parties had filed their W.S. and their document. When the case was fixed for hearing the management represented by Shri M. R. Haque and the workmen represented by Shri B. N. Sharma filed settlement in respect of 14 concerned workmen. It appears that the terms of settlement in respect of the 14 concerned workmen are just and proper and beneficial to both the parties and accordingly I accept the said settlement and pass an Award in terms of the said settlement in respect of the 14 concerned workmen which forms part of the Award.

A petition was filed by Shri B. N. Sharma, appearing on behalf of the union stating that Rama Yadav at Sl. No. 11 of the annexure to the order of reference has been employed elsewhere and as such he is not interested in the reference relating to Shri Ram Yadav and that his case be disposed off. After hearing the parties it appears that the union is not interested in respect of Ram Yadav and as such a "No Dispute" Award is passed in respect of Sl. No. 11 Rama Yadav.

The concerned workman Md. Jahir at Sl. No. 2 of the annexure has not entered into any settlement with the management and as such his case will proceed.

28-7-87.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. I-20012/224/83-D.III(A)]

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2.

DHANBAD

Ref. No. 35/86

Employers in relation to the management of Basuria Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their workmen—represented by Janta Mazdoor Sangh.

The humble joint petition of compromise on behalf of the parties most respectfully sheweth :—

1. That the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi, by a notification No. L-20012(224)/83-D-III(A) dated 13th January, 1986, have referred the industrial dispute for an adjudication u/s. 10(1)(i)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, to this Hon'ble Tribunal as per schedule noted below :—

SCHEDULE

"Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh that the 16 workmen mentioned in the Annexure below should be reinstated as Tyndals in the service of Busseng Colliery of M/s. Bhatot Coking Coal Ltd., together with Back wages and other dues, on the alleged ground that their services were wrongfully terminated from 7-12-1980, is justified? If so, to what relief are the workmen concerned entitled?"

ANNEXURE

S/Shri

1. Kanhai Rai
2. Md. Zahir
3. Saral Saw
4. Ashok Poddar
5. Tribhuwan Singh Kushwaha
6. Ram Das Rajbhar
7. Yamuna Rajbhar
8. Suresh Mallah
9. Moti Ch. Rajbhar
10. Ram Lochan Singh
11. Ram Yadav
12. Sikram Ram
13. Gouri Shankar Saw
14. Mahendra Singh
15. Binod Das
16. Ram Prasad Singh

2. That, the parties discussed the matter amicably between themselves and have settled the case on the following terms and conditions :—

- (i) That the workmen concerned shall be employed as Badli Miner/Loader subject to the condition that they are found medically fit by the Company's Medical Officer and also according to requirements.
- (ii) They shall be posted in any other colliery of M/s. B.C.C.L. and not in any collieries of Kusunda Area.
- (iii) The workmen concerned shall not be entitled to back wages and/or any other benefit.
- (iv) That each of the workmen concerned shall submit eight copies of their respective photographs duly certified by the Mukhiya of the respective Gram Panchayat of his own village of residence, the Block Development, the Contractor under whom they worked and also by the representative of the union who has raised and sponsored the dispute on their behalf, within fifteen days of the filing of the settlement and after proper verification etc. they shall be allowed to join their duties.

(iva) That the photographs and other particulars of the persons concerned shall be displayed on the notice board of the colliery for soliciting objection within 15 days, if any, to determine the genuineness of the persons concerned and if any such valid objection is received with regard to any of the above persons such or the persons shall not be eligible for employment, so that the employers may not be dragged into further litigation with regard to impersonation and/or incorrect identification of the persons concerned.

(ivb) That in view of the fact that the name of one of the persons concerned in the schedule of the reference has been mentioned as Md. Zahir but there is no such person named Md. Zahir in any of the attendance registers of the colliery and, therefore, the employer did not agree for his employment.

(v) That each of the workmen concerned shall also swear an affidavit disclosing his identity and particulars with regard to father's name, village of residence, Post Office, Police Station, District, State nearest Railway Station, date of birth, Educational Qualification etc. enclosing therewith the supporting documents in support thereof for proper record and produce the said affidavit before that date i.e. before they are allowed to resume/joint duties.

(vi) That this finally settles all the disputes between the parties and the workmen concerned shall have no other claim whatsoever.

(vii) That, the terms and conditions are fair and proper.

(viii) That, it was also resolved that the Hon'ble Tribunal be requested to pass an award of the compromise petition.

It is, therefore, prayed that your honour may be graciously pleased to accept the settlement and pass an award in terms of the settlement, and for this act of kindness the parties, shall ever pray.

Representing Workmen

Sd/-

B. N. SHARMA,
General Secretary, JMS.

Representing Employer

Sd/-

S. D. Singh,

Personnel Manager, Kusunda Area,

Sd/-

U. Mishra

S. P. Singh,

Senior Law Officer

Koyla Bhawan

Sd/- Illegible

Workmen concerned :

1. Kanhai Rai
2. Saral Saw
3. Ashok Poddar
4. Tribhuwan Singh Kushwaha
5. Ram Das Singh
6. Yamuna Rajbhar
7. Suresh Mallah
8. Moti Ch. Rajbhar
9. Ram Lochan Singh
10. Ram Yadav
11. Sikram Ram
12. Gouri Shankar Saw
13. Mahendra Singh
14. Binod Das
15. Ram Prasad Singh

I. N. SINHA, Presiding Officer

का. आ. 2313 :—औद्योगिक विवाद प्रणितियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार, के सहराव कोल्यरी, मैगर्स चारन कोकिंग ब्लॉक निमिटेड के प्रबन्धन के सम्बद्ध निरीक्षकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुषंग में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक शान्तिकरण संस्था-1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

SO 2313 -In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Keshergah Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 30th July 1982

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947

Reference No. 24 of 1983

PARTIES

Employers in relation to the management of Keshergah Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited

AND

Their Workmen

PRESENT

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer

APPEARANCES

For the Employers—Shri B. Tohu, Advocate

For the Workmen—None

STATI—Bharat

INDUSTRY—Coal

Dhanbad the 22nd July 1982

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour has by Order No. 1-20012(397) 82 D III(A) dated the 2nd April 1983, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for its adjudication—

“Whether the demand of the workmen of Keshergah Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited in Barora Area No. 1, Post Office Nawagah, District Dhanbad for promotion to Technical and Supervisory Grade A in respect of Shri Mohd. Naim Ansari is justified? If so to what extent is the said workman entitled and from what date?”

2. The case of the concerned workman Mohd. Naim Ansari is that he was a permanent employee of Keshergah Colliery as a Mechanical Foreman from 11.2.1956. The management of Keshergah Colliery was taken over by the Central Government with effect from 31.1.1973 and on this date he was drawing time scale salary in Technical and Supervisory Grade B. The said colliery along with other collieries were administered with effect from 1.5.73 under the ownership, management and control thereof were vested in M/S BCC Ltd. a Central Government Company. M/s Bharat Coking Coal Ltd. introduced promotion rules for its employees effective from 1962 in terms of the said promotion rules employees have been regularly promoted to higher grades. In view of the position of the workman held by him, he should have been promoted to the next higher grade i.e. Technical and Supervisory Grade A in 1976 or soon thereafter. But this was denied to him by the management. He has known to the management. He has been a member of the Trade Union in which he belongs to made up of representatives to the management at various levels but a union which has failed to give justice in the hands of the management. The management of the workman raised the industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad who took up the matter but reported failure of conciliation proceedings to the Central Government. In the circumstances the present reference has been made before this Tribunal for adjudication. It has been proved that the concerned workman that the Tribunal has pleased to hold that he should be promoted to Technical and Supervisory Grade A with effect from 1976 when the promotion rule of M/S BCC Ltd. was introduced.

3. In opposition the management has set up the plea that the action taken by it with regard to the promotion of the concerned workman is justified. The management has filed 787 G/87-10

Further that fitters are placed in Grade IV, V and VI under Wage Board Recommendations and with National Coal Agreement I and II. The Assistant Head Fitters are placed in Grade C and the Head Fitters in Grade B. Thus the scope for promotion of fitters is up to Grade C and there is no scope for their further promotion to Grade A. Mechanical Foreman is also placed in Grade B. When he is promoted to the post of Foreman in Grade A (Mechanical) he is given Grade A which is the highest post of the engineering department below the engineer. Therefore he should possess to him knowledge of all the machineries of the mine besides possessing skill of management control and operation of his department. A mechanical foreman is also not suitable for promotion to the post of Foreman in Charge (Mechanical) that a Head Fitter the promotion of a Head Fitter to the Foreman in Charge in Grade A in preference to a mechanical foreman is entirely at the option of the management and in exceptional cases these promotions are given. But the Foreman in Charge for promotion is he suitable in all respects. The concerned workman has been working as Head Fitter of Keshergah Colliery under the present management from the date of take over of the management of the colliery. He was placed in Grade B. Considering his seniority and experience, he has been promoted as Foreman in Charge in Grade A with effect from November 1982. Thus the demand of the concerned workman has been fulfilled. In the circumstances the management has proved that the concerned workman is not entitled to any relief in this reference.

4. The non senior examinee MWJ Jaideh Kumhar clerk to Personnel Officer in Block II Area of M/S BCC Ltd. introduced in evidence the Office Order relating to the promotion of the concerned workman in Grade A which has been marked as Ext. M1.

5. The concerned workman has claimed that since 11.2.1956 he was working as permanent employee of Keshergah Colliery in the capacity of Mechanical Foreman. This has been disputed by the management and accordingly the management the concerned workman was working as Head Fitter of Keshergah Colliery under the present management from the date of take over of the management of the colliery and that he was placed in Grade B. The concerned workman has not led in evidence in support of the fact that he was working as Mechanical Foreman at Keshergah Colliery since 11.2.1956. The management has filed Office Order Ext. M1 from which it appears that the concerned workman was Head Fitter and was placed in Grade B. Whether or may be the promotion of the concerned workman as Foreman or Head Fitter is entitled to Grade B initially at the time of take over of the management of the Central Government. That was one in his case. But as stated by the management that even though the promotion of a Head Fitter to his post of Foreman in Grade A is a promotion. Mechanical Foreman is entitled to the option of the management to be promoted as Foreman in Charge in Grade A with effect from November 1982. This is also supported by the evidence of MWJ Jaideh Kumhar who has stated that the concerned workman was promoted to Grade A from Grade B with effect from 13.11.1982. This is also evidence by the Office Order Ext. M1 dated 1982 (Ext. M1) which establishes the fact that the concerned workman was promoted to Grade A with effect from 13.11.1982. Thus it is seen that there is no vested evidence on record to show that the concerned workman was entitled initially to Grade A. On the other hand the evidence on record is that he was placed in Grade B and that he was promoted to Grade A at the time of take over of the management of the colliery by the Central Government. It is stated by the management that in consideration of his seniority and experience the concerned workman has been placed in Grade A with effect from 13.11.1982. Thus it is seen that the concerned workman has no case for relief in the matter of promotion to Grade A.

MWJ Jaideh Kumhar has stated that during the pendency of the present industrial dispute the concerned workman was promoted to Grade A. But subsequent to that the present reference has arisen.

6. Any-way from my discussion it is obvious that the concerned workman has no longer any cause for grievance and the demand of the concerned workman for promotion to Grade 'A' is justified and that the said demand has been met by the management. Hence an award is passed in favour of the concerned workman and the present reference is answered accordingly. In the circumstances of the case parties to bear their own costs.

S. K. MISRA, Presiding Officer
[No. I-20012/392/82-D.III(A)]
P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

का. प्र. 2314--औद्योगिक विवाद अधिनियम. (1917 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, चुरी राखेट, सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबन्धन के सम्बद्ध निरीक्षकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुवच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम, सन् 1947, धनबाद के पत्राट को प्रभावित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 3-8-1987 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th August, 1987

S.O. 2314.--In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Churi Project of Central Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 76 of 1982

AND

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coalfields Limited's Churi Project, P.O. Ray, District Ranchi

Their workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mura, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers--Shri R. S. Murty, Advocate

For the Workmen--None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 21st July 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. I-20012 (203)/82-D.III(A) dated the 30th November, 1982 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the action of the management of Central Coalfields Limited's Churi Project, Post Office Ray, District Ranchi in not regularising the services of Sarvashri Lorik Chauhan, Ram Rup Chauhan, Bhikari Chauhan, Dhanu Lal Oraon and Mukhlal Choudhary, Casual Wagon Loaders with effect from the 1st January, 1981, or from a later date, is justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair

and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Minister as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. I-20012/393/82-D.III(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of Reference No. 76 of 82

PARTIES :

Employers in relation to the management of Churi Colliery of CCL, P.O. Ray, District Ranchi.

AND

Their workmen.

JOINT COMPROMISE PETITION OF EMPLOYERS AND WORKMEN

The above mentioned employers as well as the workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh most respectfully beg to submit jointly as follows :-

- (1) That the matter covered by aforesaid reference was mutually negotiated between the representative of the management and the Union.
- (2) That as a result of the aforesaid negotiations, both the parties have arrived at a mutually acceptable and amicable settlement on an overall basis on the following terms and conditions :-

- (a) It is agreed that since the management has already issued office order no DY/CME/CH/P/Office Order Regulation 87-88/1556-1694 dt. 21/23-6-87 regularising S/Shri Lorik Chouhan, Ram Rup Chouhan, Mukhlal Choudhary, Ram Keshwai Chouhan and Dhanulal Oraon, Casual Wagon Loader as permanent Wagon Loaders with immediate effect, the dispute referred to the Honble Tribunal and as covered by the above reference stands fully settled.
- (b) That it is agreed that in view of the above the workmen concerned and sponsoring union RCMS have no more claim as against the Management in regard to this matter.
- (c) It is agreed that this is an overall agreement in respect of all the issues covered by aforesaid reference.

3. That the employers and workmen consider that the aforesaid agreement is just, fair and reasonable to both the parties.

In view of the above both the parties jointly pray that the Honble Tribunal may be pleased to accept this joint compromise petition and dispose of the reference accordingly by giving an Award in terms thereof.

Sd/- Illegible
Secretary RCMS
Churi Branch
Sd/- Illegible
for and on behalf of the workmen

Sd/- Illegible
Project Officer/Agent
Churi Colliery,
C. C. Ltd., Churi
Dy. Chief Mining Engineers,
For and on behalf of employers.

Sd/- R. S. Murthy,
Advocate for Employers

WITNESSES :

1. Sd/- Illegible
2. Sd/- Suraj Nath Ojha, (U.D.C.)
Churi Colliery, 12th day of July, 1987.
Part of the Award
Sd/- Illegible

41-3-86 के अन्त तक दाख I और दाख II शामिल होना
9 मार्च 1986 गान्धी की मर्णा नी गेट् आ 10000 मकाय

का निर्माण कार्य पूरा किया गया। रिपोर्टीशन अवधि के दौरान इन योजनाओं के अधीन कुल 311 मकानों की मजदूरी दी गई तथा 954 369/- रु की राशि खर्च की गई।

(3) जन प्रदाय —वाईतराजी घाटी समर्पित जल प्रदाय परि- योजना, जोदा की अनुमानित लागत 2 09 करोड़ रुपए थी परन्तु अनुमानित लागत को संशोधित करके 2 86 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कल्याण संगठन का भाग 1 13 करोड़ रुपए था जिसे कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा, जन प्रदाय की छह नई योजनाएँ मंजूर की गई हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, इनमें से 2 योजनाओं को पूरा किया गया।

(4) शैक्षणिक और आमोद-प्रमोद सुविधाएँ —लोह/मँगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खनिकों और उनके परिवारों के लिए ये सुविधाएँ भी दी जाती हैं जिनका खर्च निधि में किया जाता है। इस योजना के अधीन, 37 बहुउद्देशीय स्थान, 5 कल्याण केन्द्र, 2 महिला-बाल कल्याण केन्द्र, 11 चलचित्र एकक, 155 रेडियो केन्द्र तथा चार स्कूल बसे हैं। खान के मालिकों को खेल-कूद, खेल, टूर्नामेंट आदि के आयोजन के लिए सहायता अनुदान मंजूर किए गए थे। अनुमोदिन योजना के अनुसार, लोह/मँगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिकों के उन बच्चों को छात्रवृत्ति देने की सुविधा जारी रखी गई जो स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे। 1985-86 के दौरान, 2740 विद्यार्थियों के लिए 7,29,342/- रु की राशि मंजूर की गई। स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने संबंधी योजना को बहाल पर जारी रखा गया जहां वह 1982-83 में विद्यमान थी। मध्याह्न भोजन योजना की दर 75 पैसे प्रति बालक प्रतिदिन है। इसी वर्ष में पुस्तकें, स्लेटें, पाठ्य पुस्तक सप्लाई करने के लिए एक नई योजना भी अपनाई गई है और रसीन टेन्वीविजन सेट के लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है।

(ग) घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना

आलोच्य वर्ष के दौरान दुर्घटना के शिकार हुए श्रमिकों की विधवाओं और बच्चों को वित्तीय सुविधाएँ देने की योजना भी जारी रखी गई। इस वर्ष के दौरान 6 श्रमिकों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

भाग-II

पहली अप्रैल, 1985 को अतिशेष	241,69,942.00 रु.
वर्ष 1985-86 के दौरान प्राप्ति	205 32,536.00 रु.
वर्ष 1985-86 के दौरान किया गया व्यय	224,11,392.00 रु.
31 मार्च, 1986 को अतिशेष	222,61,086.00 रु.

[नं. जेड.-12015/3/86-उप-11]

एम. एम. भल्ला, अवसर सचिव

New Delhi the 13th August, 1987

S.O. 2315—In pursuance of Section 10 of the Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act 1976 (61 of 1976) the Central Government hereby publishes the following report of the activities financed under the Act during the year ending 31st March, 1986, together with a Statement of Accounts for that year.

PART I

(A) General:

The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961, was enacted to provide for levy and collection of cess on Iron Ore for financing activities to promote the welfare of miners

by the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Amendment Act, 1970 (41 of 1970) which was brought into force from 1st October, 1974 and again by the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976 (55 of 1976) which came into effect from 1st September, 1978 and workers employed in Manganese Ore were also covered.

The last amendment was made as under:—

- (i) Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 1982 (45 of 1982);
- (ii) Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Act, 1982 (44 of 1982).

By the amendment of 1982, Cess has been levied and collected on Chrome Ore with effect from 1st July, 1983, in the same manner as is done for the cess on iron ore and manganese ore and workers employed in chrome ore mine have been covered. The Act provides for the levy of cess at a rate not exceeding one rupee per tonne of iron ore, rupees six per tonne on manganese ore and rupees three per tonne on chrome ore exported or internally consumed. The rate of levy of cess on iron ore was increased from 25 paise per tonne to 50 paise per tonne with effect from 1st July, 1981. The present rate of levy on manganese ore is rupee one per tonne and rupees three per tonne on chrome ore. The proceeds of the cess are utilised mainly for improvement of public health and sanitation, prevention of diseases, provision and improvement of educational facilities, etc. The Welfare facilities cover workers employed directly or through contractors.

2. The cess is levied as a duty of customs on the iron ore, manganese ore and chrome ore exported and as a duty of excise on the ores consumed internally, the Welfare Commissioners have also been declared Cess Commissioners and their jurisdictions have been notified for the purpose of collection of cess on internal consumption. The collection of welfare cess on duty of customs is made by the Department of Customs who are paid half per cent towards collection charges.

(B) Welfare Activities:

The Welfare activities under different heads financed during the year from the welfare funds are indicated below:—

(1) Medical facilities.—The workers getting a basic pay up to Rs. 1600 and their dependents are being provided medical aid by the Organisation. Facilities are made available to the workers and their dependents in the 3 Central Hospitals (one each in Bihar, Orissa and Goa) and 19 Mobile/Static Dispensaries established under the Fund Organisation. In addition to the existing medical facilities the following new Hospitals/Medical Dispensaries were sanctioned during the year 1985-86:—

- (1) Static-cum-Mobile Dispensary at Garividi (Andhra Pradesh).
- (2) Mobile Medical Unit Dispensary at Rajhara (Madhya Pradesh).
- (3) Central Hospital, Barajamda (Bihar).
- (4) Static Dispensaries at Nuia (Bihar).
- (5) Static Dispensaries at Karampada (Bihar).
- (6) Static-cum-Mobile Dispensary at Palamau (Bihar).
- (7) 50 Bedded Hospital at Balaghat.

Besides, beds continued to be reserved for the exclusive use of iron ore and manganese ore miners and their families in TB sanatoria and other hospitals 1868 workers were benefitted during 1985-86.

Arrangements have also been made for indoor treatment of iron ore mine workers of Bihar and Orissa suffering from mental diseases in the mental Hospital Kankar, Ranchi. A scheme introduced in this regard during 1977 provides for payment of subsistence allowance for a period not exceeding 9 months to dependents of miners under going treatment where miner patients happens to be the only earning member of the family and he has no other source of income. Arrangements have also been made for treatment of leprosy patients in the Mission Hospital, Purulia for Bihar region and for

The owners of the non ore mines, manganese ore mines and chrome mines who maintain the dispensaries and hospitals upto the prescribed standard are being paid an annual grants-in-aid

(ii) Housing facilities.—Provision of housing accommodation for miners is one of the main activities of the Fund. At present, there are three schemes in vogue, namely—

- (1) Type I Housing Scheme
- (2) Type II Housing Scheme
- (3) Build Your Own House Scheme.

(1) Under Type I Housing Scheme, subsidy is payable at the rate of 75 per cent of the Standard estimated cost or Rs. 7500 whichever is less. In addition the development charges are also payable at the rate of 50 per cent of Rs. 2,000 for ordinary area and 75 per cent of Rs. 2000 for black cotton or swelly soil areas or the actual cost whichever is less

(2) Under Type II Housing Scheme, the rate of subsidy payable is Rs. 15,000 or 75 per cent of the cost of construction whichever is less. In addition development charges are also payable at the rate of Rs. 1500 per house in ordinary areas and Rs. 2250 per house in respect of black cotton or swelly soil area or the actual cost of development whichever is less.

(3) Under Build Your Own House Scheme, financial assistance of Rs. 1000 as subsidy is given to an eligible worker besides an interest free loan of Rs. 4000, refundable in monthly instalments spread over a period of not exceeding 9 years.

Under Type I and II Housing Schemes, 11482 houses were sanctioned during the 1985-86. Out of total 11482 houses 10865 were completed during that year. A total sum of Rs. 9,54,369 were spent during the year under report.

(iii) Water Supply.—The integrated Vaitarani Vellay Water Supply Scheme, Joda was estimated to cost Rs. 208 crores, but the estimates have been revised to Rs. 228 crores. The share of the Welfare Organisation is Rs. 1.04 crores have been sanctioned by the Welfare Commissioner, Bhubaneswar upto October, 1985. In addition of this 13 new schemes for water supply were sanctioned. Out of 13 schemes 12 were completed in the reported year.

(iv) Education and Recreational Facilities.—The facilities provided to the non/manganese and chrome ore mines workers and their families which were financed out of the fund. Under the Scheme there are 39 multipurpose Institutes, 2 welfare centres, 5 women-cum-children welfare centres, 13 cinema units, 155 radio centres and 3 school bus. Grants-in-aid was sanctioned to mine owners for organising sports, games tournaments etc. Seven more projects were sanctioned during 1985-86. Scholarships continued to be given to the children of iron/manganese and chrome ore mines workers studying in schools, colleges and technical institutions in accordance with the approved scheme. The total amount of Rs. 4,49,137 were sanctioned to 2017 students during the year 1985-86. The mid-day meal scheme for the school children continued wherever it was in existence in 1982-83. The rate of supply of mid-day meal is 75 paise per child per day.

(C) Fatal and Serious Accident Benefit Scheme

The Scheme for financial benefits to widows and children of victims of accident was also continued during the year. Under report 6 workers were sanctioned financial assistance during the year.

PART II

Opening Balance as on 1st April 1985	Rs. 241,69,942.00
Receipt during the year 1985-86	Rs. 205,32,536.09
Expenditure during 1985-86	Rs. 224,41,392.00
Closing balance as on 31-3-86	Rs. 222,61,085.00

[No. Z-12015/3/86-W II]
S. S. BHATIA, Under Secy

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1987

ब.ग.प्र. 2316—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार

बृजमोहन को 17 अगस्त से 21 अगस्त, 1987 की अवधि तक उत्प्रवास, संरक्षी, चंडीगढ़ के समस्त कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22012/1/86-उत्प्रवास-II]

New Delhi, the 13th August, 1987

SO 2316—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Bray Mahan, Assistant, Ministry of Labour to perform all functions of Protector of Emigrants, Chandigarh, in the office of the Protector of Emigrants, Chandigarh during the period from 17th August to 21st August, 1987.

[No. A-22012(1) 86-Emig. II]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

ब.ग.प्र. 2317—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय कालीन में सहायक प्रो. वी. के. धामन को 1 सितम्बर, 1987 से 11 सितम्बर, 1987 तक उत्प्रवास संरक्षी, कालीन के समस्त कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22012/1/86-उत्प्रवास-II]

इंदर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1987

SO. 2317—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri K. K. Thomas, Assistant, in the office of Protector of Emigrants, Cochin, to perform all functions of Protector of Emigrants, Cochin, from 1st September to 11th September, 1987.

[No. A-22012/1/86 Emigration II]
INDER SINGH, Under Secy

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1987

ब.ग.प्र. 2318—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, बैंक आफ बरोडा के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजन और उनके कर्मचारियों के बीच में अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पचाह को प्रकाशन करती है, जो केंद्रीय सरकार को 3-9-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th August, 1987

SO 2318—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their Workmen which was received by the Central Government on the 3-8-1987.

BEFORE SHRI N. A. CHAUHAN, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
AHMEDABAD

Ref. (IIC) No. 6 of 87

ADJUDICATION

Bank of Baroda, Nadiad

First Party

AND

The workmen employed under it

Second Party

STAFF : Gujarat

INDUSTRY :

In the matter of termination of services of Shri K. S. Parmar Sweeper with 31.8.87.

PRESIDENT.

PARILLS

Employers in relation to Syndicate Bank, Manipal

AND

Their Workmen

APPEARANCES

For the Management, M. K. Rangaswamy, Dy. General
Manager of the Bank at Manipal

For the Workman Mr. S N Rao, General Secretary,
of the Syndicate Bank Staff Union

INDUSTRY Banking STATE Karnataka.

Camp Bangalore

Bangalore, the 7th day of July, 1987

AWARD

The reference under S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act arises out of the termination of the services of the workman, Miss. Shakuntala S Nayak, who was employed as a clerk on probation at Panjim Branch of the Syndicate Bank, on the terms and conditions incorporated in the Annexure to the appointment letter Exhibit M-1, dated May 24, 1971.

2. In pursuance to the above referred order, the workman joined duty at Panaji Branch before office hours on 31st May, 1971 vide the joining report Exhibit M-2. As her work was found to be not satisfactory for confirmation, the initial period of six months probation was extended by three months on the basis of the report Exhibit M-3 dated 20.10.1971 of the Manager of the Panaji Branch. Thereafter on 4th January, 1972, the Manager of the Panaji Branch submitted his confidential report Exhibit M-5 to the Custodian, Staff Department in the Head Office of the Bank, proposing to terminate the services of the workman. The letter reads as follows:—

“Re Kumari Shakuntala S Nayak

In compliance with your appointment letter No. 19261/761/APT dated 24-5-1971 the above mentioned employee joined the service of this institution on 31st May, 1971 vide our letter No. 1184/801-001/SIF of the same date.

Not having been found suitable for confirmation in our service within the initial period of 6 months, an extension was granted to her for further 3 months with effect from 1st December, 1971 by your letter No. 54017 dated 1st November, 1971.

In spite of what has been said in your referred letter a watch over her work has convinced us that she does not possess capacity for much improvement.

We have not observed from article 20 that of the Bipartite Settlement that she will be bound to be confirmed if she is allowed to work for a continuous period aggregating 240 days which will end on 30th of the current month in case the extension period of probation now granted is adhered to. Any action therefore that we may propose to take to terminate her service we propose, all have to be taken before that date.

3 On the basis of this report the General Manager of the Bank terminated the services of the workman by order Exhibit M 6 dated February 9 1972. The workman was informed by this letter that in terms of that order the workman would be relieved from the services of the bank at the close of the office hours on 29-2-1972. A pay-slip for Rs. 219.30 in lieu of a month's notice was also enclosed.

This reference under section 100A (1) (d) of the ID Act, 1947, has been referred on behalf of the Central Government by the Under Secretary, Ministry of Labour, vide its Order bearing No 1-12012 204/86-D, IIA dt. 20th March, 1987 for determination of the industrial disputes mentioned therein between the parties. The dispute referred is

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in relation to its station Road Branch, Nadiad interminating the service of Shri K. S. Parmar, Sweeper w.e.f. 3-1-1986 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2 The order of reference show that the order of referring the dispute to this Tribunal was communicated by the Under Secretary, Ministry of Labour, Govt of India to the parties and the second party was informed to file the statement of claim with relevant documents within 15 days from the receipt of order of reference and also to forward the copy thereof to the opposite party. In spite of that the second party at whose instance the reference was made by the Government did not bother to file any statement of claim, but even then this Tribunal called upon the second party to file the statement of claim on or before 28th April, 1987 and to inform the first party about the same. The second party in spite of service of the aforesaid notice did not remain present. The first party had remained present and given implication at Ex 2 that unless a statement of claim is given by the second party, nothing can be done by them. In the interest of justice the matter was adjourned and the second party was served with another notice dt 7-5-87 (Ex 5) by Regd AD to appear before this Tribunal on 19-6-87. In spite of the service of aforesaid notice (Ex 5) vide Regd AD Slip at Ex 3 the second party did not bother to file the statement of claim. Still however, in order to give one more chance the matter was adjourned to 26-6-87. Even on that date the second party did not appear and file any statement of claim. The first party also did not appear before this Tribunal.

Thus it appears that the second party at whose instance this reference is made is not interested to prosecute the demand made and therefore the demand made in this reference requires to be disposed of as not pressed. Accordingly, I pass the following order:

ORDER

This reference is rejected for want of prosecution by second party at whose instance this reference was made. Considering the facts, there shall be no order as to the cost of this reference.

Ahmedabad 3rd July 1987

N A CILAUHAN, Presiding Officer

Secretary

[No L 12012 204]86-D H(11)

का प्रा २३१५--औद्योगिक विकास अधिनियम १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १७ में अनुसूचना में, ऐसी ही सरकार, निरीक्षक है। प्रबंधन से सम्बद्ध निगोत्रों और उनके समकार के बीच में अनुसूच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में संस्थीय सरकार औद्योगिक अधिकरण में । अन्यथा संतोष का प्राप्त करने के लिए । सरकार का । १९८६ की भांति । १९८६ में ।

S.O. 2319.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen, which was referred by the Central Government on the 4th August 1947.

with that letter. On the basis of this order, the Manager of the Panaji Branch issued the relieving order Exhibit W-1, relieving the workman from the services of the Bank after office hours on 29th February, 1972.

4. The workman raised the dispute before the AICCO Vasco-da-Gama in the year 1984 and on failure of the conciliation proceedings, the dispute was referred to this Tribunal by the Central Government vide order dated 16th December, 1985.

5. It is the case of the workman that she had become a confirmed employee of the Bank on 29-2-1972 as the period of probation in her case was completed on 28th February 1972, itself, and her services could not have been terminated without giving three months notice or three months' wages in lieu of notice. It is also the case of the workman that she had put in 275 days of service from 31-5-1971 to 29-2-72 and thus completed one year of continuous service within the meaning of S. 25B(2)(a) of the Industrial Disputes Act, and therefore her services could not have been terminated without following the procedure prescribed in S. 25-F of the Industrial Disputes Act. It is also the case of the workman that apart from the action of the management being illegal, it was also totally unjustified as there was no reason or basis for the termination.

6. The Bank contended that the reference is unduly delayed and hence not maintainable under the law as the workman had approached this forum after a period of 14 years and had failed to give any convincing or justifiable reason for explaining the delay in seeking relief under the Industrial Disputes Act. According to the Bank, the officers under whom Miss. Shakuntala Nayak was working during the period were periodically sending the performance reports to the Manager of the Branch and on the basis of these reports which revealed that the workman had not attained sufficient proficiency in her work, the Manager submitted the performance appraisal report to the head office and after perusing the case meticulously, the competent authority in the head office took a conscious decision on 29-10-1971 to extend the probation period of the workman for a period of three months, since Miss Naik had not shown satisfactory progress in picking up work and had not come upto the satisfaction of her superiors. The probation period was extended for giving opportunity to the workman to overcome her short-comings in terms of service conditions. But in spite of this, she had not taken any steps or care to improve her short-coming about which she was duly informed in writing and hence it was finally decided by the Bank to dispense with her services in terms of clause 8 of the order of her appointment. According to the bank, the competent authority took a decision on 29-10-1971 itself to extend the probation period of Miss Naik for a further period of three months and this decision had been communicated to her well in advance vide letter dated 1-11-1971, but while indicating the said decision, the management had inadvertently due to a typographical error mentioned that her probation period was extended with effect from 1-11-1971 instead of 30-11-1971. According to the Bank, Miss Naik was on probation initially from 31-5-1971 to 30-11-1971 for a period of six months, and thereafter for a further period of three months from 30-11-1971 to 29-2-1972. Therefore her probation had not exceeded nine months. The Bank maintained that the management had only dispensed with the probationary period of Miss. Naik on the basis of unsatisfactory performance on completion of nine months purely in consonance with the provisions of the Sastri Award for bona fide reasons borne out from records of the Bank, and the Bank had not flouted any provisions of the Sastri Award in any manner. According to the Bank the concept that any kind of termination would amount to retrenchment was formulated by the High Courts and Supreme Court subsequent to the impugned action of the Bank and hence that concept cannot be made applicable to the instant case. It is also the case of the Bank that the termination of a probationer for unsatisfactory performance and in accordance with the terms and conditions of service falls within the exception provided under S. 2(a)(bb) of the Industrial Disputes Act and hence it does not amount to retrenchment.

7. It is an admitted position that the workman joined the services of the Bank on 31-5-1971 and the original period of probation which was for six months was completed on

30th November, 1971. That period of probation was extended by an order dated 1-11-1971. Though the order mentioned that the period was extended by three months from 1-11-71, it is an admitted position that the date 1-11-1971 was an inadvertent error and that the date was and ought to be 30-11-1971. The extended period of probation, thus commenced on 30-11-1971. It was for three months, which came to an end at the end of 28th February, 1972 and not 29-2-1972 as contended by the Bank. No doubt, the order terminating the service was passed and communicated to the workman long before that date. It was made effective as mentioned in the termination order (Exhibit M-6) as well as the relieving memo Exhibit W-1, after office hours on 29-2-72. It is thus clear that the termination was effected a day after the probationary period of 9 months came to an end. It is also an admitted position that the workman was paid wages for 9 months and one day. She was paid wages for 31-5-1971 and also for full 9 months from June, 1971 to February, 1972.

8. As the services of the workman were not dispensed with on or before the expiry of the probation, she will be deemed to have been confirmed at the end of 28th February, 1972, as provided in para 495 of the Sastri Award. The relevant provision of Sastri Award reads as follows:—

"The Sen Award fixed the period of probation at 6 months, which in certain cases would be extended by 3 months. We respectfully agree with the said direction agree with the said direction and direct that ordinarily the period of probation should not exceed 6 months. However, in case of persons whose work is not found to be quite satisfactory during the said period but who are likely to improve and give satisfaction if a further opportunity is given to them, the period may be extended by three months provided due notice in writing is given to them and their consent in writing is obtained before the extension of their period of probation. In all other cases probationers after the expiry of the period of six months should be deemed to have been confirmed, unless their services are dispensed with on or before the expiry of the period of probation."

9. Admittedly, this provision is not modified by any of the subsequent by-partite agreements between the banks and their workmen. Paragraphs 522 of the Sastri Award contains the directions given by the Sastri Tribunal on the subject of termination of employment. The first direction which is relevant reads as follows:—

(i) "In cases not involving disciplinary action for misconduct and subject to clause (6) below, the employment of a permanent employee may be terminated by three months' notice or on payment of three months' pay and allowances in lieu of notice. The services of a probationer may be terminated by one month's notice or on payment of a month's pay and allowances in lieu of notice."

10. As the workman in this case had ceased to be probationer at the end of 28-2-1972 and deemed to have been confirmed when her services were terminated at the end of 29-2-1972, three months notice or payment of three months' pay and allowances in lieu of notice, was necessary. Admittedly, the workman was paid only one month's pay and allowances in lieu of notice. Therefore her termination was illegal.

11. The termination of the workman was bad for other reason also. It is now well settled that every termination otherwise than as a punishment indicated by way of disciplinary action and other than those coming within the purview of the exceptions mentioned in the definition of the term 'retrenchment' given in S. 2(oo) of the Industrial Disputes Act, amounts to retrenchment within the meaning of the said provision. Admittedly, during the period from 31-5-1971 to 29-2-1972 (both days inclusive) the workman had worked for 275 days and had thus completed one year of continuous service within the meaning of clause 1 of S. 25 B) of the said Act and the workman, therefore, could not have been retrenched without observing the conditions precedent to

retrenchment mentioned in S. 25-F of the Industrial Disputes Act.

12. It was sought to be urged on behalf of the management that the above-mentioned concept about retrenchment was developed by the High Courts and Supreme Court after the impugned action was taken by the management, while the view prevailing at that time was that only discharge of surplus labour amounts to retrenchment and hence the concept subsequently developed should not be applied to the instant case. This submission deserves to be rejected outright.

13. It was sought to be urged that the impugned action of the management in this case falls within clause (bb) of S.2(oo) of the Industrial Disputes Act and hence it does not amount to retrenchment. By virtue of this clause, retrenchment does not include termination of the service of a workman as a result of non-renewal of the contract of employment between the employers and the workman concerned on its expiry or such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein. It is difficult to accept this submission for two reasons. Firstly, clause (bb) was inserted by S.2 of Act No. 49 of 1984, which came into effect from 18-8-1984. This amendment has no retrospective effect and hence this clause cannot be involved for supporting the submission that the action of the management in terminating the services of the workman in this case under the terms of employment cannot be considered as retrenchment. Moreover, term 8 of the terms and conditions of the workman's appointment enabled the bank to terminate her services without assigning any reason at any time during probation giving one month's notice or salary in lieu of notice. This term did not permit the Bank to terminate the workman's services after the probationary period was over. As mentioned above, the probation period was over on 28-2-1972 and the order was made effective after the probation period was completed, i.e. after the office hours on 29-1-1972. As the services of the workman were not terminated before the end of 28-2-1972, when she completed the probationary period of 9 months, it must be held that the contract of employment was renewed. The case, therefore, does not fall under clause (bb) of S. 2(oo) of the Industries Disputes Act.

14. Admittedly, no retrenchment compensation was paid to the workman at the time of retrenchment as contemplated by clause (b) of S. 25F. Retrenchment was therefore, void ab initio and the termination of the services of the workman was illegal on that ground also.

15. In view of the above finding, it is not necessary to consider the question whether there was any valid reason for terminating the services of the workman. Moreover, in the absence of malafides on the part of the management, the decision of the management in not confirming a probationer cannot be questioned. There were no malafides on the part of the management in terminating the services of the workman and none are alleged.

16. It was tried to be contended on behalf of the Bank that the reference is not maintainable in view of the inordinate delay committed by the workman in raising the dispute. There is no substance in this contention, obviously because no period of limitation is prescribed for the appropriate Government to make a reference when the Government comes to the conclusion that an industrial dispute exists. No doubt, the workman raised the dispute for the first time in 1984 nearly 12-1/2 years after her services were terminated. But that does not affect the validity of the reference nor can it be said that in view of the delay, the Government could not have referred the dispute to this Tribunal for adjudication. The result therefore, is that it must be declared that the action of the Syndicate Bank in terminating the services of Miss Shakuntala S. Nayak was illegal and unjustified and the workman must be reinstated in service.

17. Ordinarily, in case where termination is found to be illegal a workman is directed to be reinstated in service, the workman must be paid full back-wages from the date of termination till the date of actual reinstatement. In the present case, however, to award full back-wages would be unjustified in view of the fact that the workman slept over the matter and raised the dispute for the first time nearly 12-1/2

years after her services were terminated. She accepted the order terminating her services and did not move in the matter till 1984 when she raised the dispute. To award full back wages under these circumstances would amount to paying premium on unjustified and unexplained laches on the part of the workman. It is also an admitted position that since July, 1981 the workman is employed as an Assistant Mistress in Model Higher Primary School, Bhatkal and has drawn salary at that post as shown in the annexure to the reply filed by the workman on 5th June, 1987 to the application of management for reopening the case for proving that the workman was gainfully employed. In view of this, it would be just and proper to direct the management of the Bank to pay 50 per cent of the wages payable to the workman during the period from 1st March, 1972 to 30th June, 1981, 50 per cent of the difference between the wages payable to the workman and the salary drawn by her as the Assistant Mistress in the Model Higher Primary School at Bhatkal during the period from 1st July, 1981 till 30th August, 1984 and full difference between wages payable to the workman and the salary drawn by her as the Assistant Teacher from 1st September, 1984 till the date of actual reinstatement.

18. I, therefore, direct that the workman must be reinstated in service with immediate effect and paid back wages as stated above within two months from the publication of the award.

19. Award accordingly.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer
[No. L-12012/12/85-D.I(A)]

का. अ. 2320.—श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1917 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कर्नाटक बैंकिंग, ने प्रबंधन से सम्बद्ध निगोशियों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित श्रीयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार श्रीयोगिक अधिकरण बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-87 को प्राप्त हुआ था।

[कार्डन संख्या पत्र. 12012/19/82 टी 115]

S.O. 2320.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Karnataka Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AND
LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated this the 25th day of July, 1987

Present :

Shri B. N. Jalge, B.A. (Hons.) JI B. ... Presiding Officer
Misc. Appn. No. 1 of 1986

Central Ref. No. 1/1983

Petitioner : In Respondent.

Narayan M. Ashrit of Gadag vs. The Chairman, Karnataka Bank Ltd. Mangalore.

Appearances :

For the Petitioner : Sri A. C. Navadur, Advocate
Dharwad.

For the Respondent : Sri V. N. Apte, Advocate and
Sri V. H. Upadhyay

ORDER

This is an application filed under Order 9 Rule 9 of C.P.C. read with Section 11 of the I.D. Act.

2. The petitioner states as follows :

3. He was the first party in C. R. No. 1'83. He had appeared through Sri P. G. Wadikar, trade unionist. His claim statement was filed on 11-4-83. The reference was being heard at Hubli sitting at the request of both the parties. Sri

P. G. Wadikar died on 24-7-85. He did not come to know about further dates of hearing. Neither himself nor his union had received any notice. He learnt that an ex-parte award has been passed rejecting his claim. He received a copy of the award in November 1986. The present petition is within the time. The ex-parte award may be set aside.

4. The respondent Karnataka Bank, has filed its objections and its contentions are as follows :

5. It is denied that the petitioner did not know about the death of Sri P. G. Wadikar. It is denied that he did not come to know about the further dates of hearing. There is no cause shown by him for his non-appearance. His petition may be rejected.

6. The parties have filed their affidavits and documents.

7. The parties have been heard.

8. The points that arises for my consideration are as follows :

9. (1) Whether this Court has the jurisdiction to set aside the ex-parte award under the facts and present circumstances of this case ?

(2) What Order ?

10. My findings are as follows :

(1) Point No. 1 : No.

(2) Point No. 2 : The petition is liable to be dismissed.

REASONS

11. In the affidavit filed by the petitioner dt. 22-6-87 it has been stated that in C. R. 1/83 Sri P. G. Wadikar and himself used to attend the proceedings regularly. In para 3 of the affidavit he further states that on 24-7-85 Sri P. G. Wadikar expired and for a long time he did not know about it because he resides in Gadag. In para 6 he states that he was prevented from attending the Tribunal on relevant dates, because he did not know about the death the passing of the cause he did not know about the death of Mr. Wadikar award only in October 1986. In order to support his case he was produced a true copy of the award issued by the tribunal. On the other hand, the regional manager of the respondent Sri Suryanarayan Somaji has filed his affidavit and he swears that he used to attend to the case at the Hubli sitting and he used to see petitioner along with Sri Wadikar. He further swears that Sri Wadikar died in July 1985 and an obituary had appeared in the Kannada daily newspaper Samyukta Karnataka Hubli of 24-7-86. He has further sworn that since the first party is an educated person and since Sri Wadikar was a well known labour leader and since the said newspaper is widely circulated in the District of Dharwar including Gadag he must have knowledge about it. He has then sworn that if the award has been passed on 4-11-85, the present application is made on 18-11-86 and that the provisions of law shown by the petitioner are not applicable. Copy of the said newspaper has been enclosed to his affidavit. It is dated 24-7-86. The news item reads that on 24-7-86 the first death anniversary was being celebrated at Hubli. The newspaper does not indicate that any such news item had been published in July 1985.

On facts there can be no objection to accept the contention of the petitioner that he did not come to know about the death of Mr. Wadikar till as late as July 1986. The petitioner states that he also used to attend the tribunal at the Hubli sitting and on the basis of this statement, it was submitted by the Respondent that it is not explained as to why he did not attend the Hubli sitting of the tribunal, for a considerable period. The Order sheet in C. R. 1/83 discloses that when the matter was called at Hubli camp on 23-6-84 the first party was absent and an order was made that notice should be issued in the name of the petitioner. The Order sheet of 1-2-85 discloses that Sri Wadikar filed his authorisation and sought for an adjournment. The matter was adjourned to 12-3-85. On 12-3-85 the first party sought further adjournment. The Order sheet dated 29-8-85 indicates that though notice had been issued on the first party the petitioner had not remained present. After that the matter had been adjourned to 29-10-85 and at Hubli camp evidence had been

recorded and the side of the second party has been closed. On 4-11-85 award has been passed.

2. The learned counsel for the Respondent contended that the petitioner had the burden to prove the delay of each day and for not having done so he cannot succeed. It was also argued that in view of Section 11 of the I.D. Act the petition is not maintainable and this Court has no jurisdiction to recall the award. The miscellaneous papers of the case file do not point out any office copy of the notice or any acknowledgement to show that the first party had been served with a notice to appear on 29-8-85 at Hubli sitting. The preponderance of evidence is thus on the side of the petitioner that after the death of Sri Wadikar he was not served with any notice regarding the Hubli-sitting and therefore it shall have to be presumed that he was not aware of the date of hearing of Hubli sitting. On facts I therefore find that the petitioner has shown sufficient reason for his non-appearance when the matter was called at Hubli sitting on 29-8-85.

3. The learned counsel for the Respondent contended that section 11 of the I.D. Act states that subject to any rules made in this behalf the tribunal shall follow such procedure as the tribunal thinks fit. Then he pointed out to Rule 10B of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. The said provision of law states that in case of any default the tribunal may proceed ex-parte. The provisions of Sub-Rule (9) of Rule 10B state that before the submission of the award the Court may revoke its order if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds.

4. The learned counsel for the Respondent contended that Rule 10B has been inserted by amendment of Rules of 1984, which came into effect on 18-8-84. It was further submitted that this tribunal becomes functus officio soon after the award is submitted to the Central Government and thus this tribunal has no jurisdiction to set aside the ex-parte award.

5. The learned counsel for the petitioner referred to the case of Grindlays Bank Ltd., vs. the Central Government Industrial Tribunal and others (AIR, 1981 Supreme Court page 606). The authority states that the tribunal does not become functus officio provided application is filed within 30 days of publication of award. The authority deals with law when there was no Rule 10B in the Rules. I am of the view that the principle laid down in the authority is therefore not applicable. The learned counsel for the petitioner then relied upon the case of Satnam Verma vs. Union of India (AIR 1985 Supreme Court page 294) and contended that even if the award is published, the Court has the jurisdiction to set aside the ex-parte award. The facts of the reported case would show that the petitioner contended that the date given was 26-2-82 and not 23-2-82 but the reference was disposed of ex-parte on 23-2-82 and it is held that even if the award has been published in the Gazette the Labour Court can set aside ex-parte award.

6. Paragraphs 7 and 8 of the authority disclose that the principles have been laid down with reference to Rules 22 and 24(h) when Rule No. 10B was not inserted by a subsequent amendment. Now the provisions of Rule 10B (9) make it very clear that the aggrieved party file an application before the submission of the award and if the tribunal is satisfied that the absence was on justifiable grounds the tribunal may revoke the ex-parte order. Section 11 starts with the phrase subject to any rules that may be made in this behalf ... and now the rules provide that an application for setting aside the ex-parte award can be entertained if it is made before the submission of the award. The authorities that have laid down the aforesaid principle before Rule 10B was inserted in the rules cannot be of any avail to the petitioner.

7. The learned counsel for the Respondent cited the case of Mohammed Yahaya Kola vs. James D'Souza and others (1974 Lab IC) and argued that the tribunal has no power to set aside the ex-parte award. This authority does not hold the filed any longer in view of the two authorities cited for the respondent. Since the facts and circumstances of the case show that the application for setting aside the ex-parte award has been made long after the submission of the award and once Rule 10B squarely applies to the facts of the case I am of the view that the petitioner cannot succeed. In spite

of my finding that he has shown sufficient cause for his non-appearance, it has now been canvassed before me that notwithstanding Rule 10B or Rule 24(b), the provisions of C.P.C. and Section 5 of the Limitation Act can be invoked by the petitioner to his advantage if there is a favourable finding of fact.

8. Looking from any angle I am of the view that the petitioner cannot succeed and the petition is liable to be dismissed.

9. In the result, the petition is hereby dismissed.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

B. N. LALAGE, Presiding Officer
Central Government Industrial Tribunal-
Cum-Labour Court, Bangalore.

[No. L-12012/19/82-D.IV(A)]

का.प्र. 2321--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नेशनल इश्योरेंस कं. लि. के संबंधित से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-7-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2321.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT BANGALORE

Dated this the 7th day of July, 1987

PRESENT :

Shri B. N. Laje, B.A. (Hons.), LL.B.,—Presiding Officer.

CENTRAL REFERENCE NO. 3/77 (New CR No. 4/87)

I Party :

Mrs. B. Kochhar, 90, Pratap Chowk, Opp Shopping Centre, Separated Family Quarters, Delhi Cantt-110010.

Vs.

II Party :

The Divisional Manager, National Insurance Company Ltd., 134/1, Residency Road, Bangalore-560025.

APPEARANCES :

For the I Party : By Sri M. C. Narasimhan, Advocate, Bangalore.

For the II Party : By Sri K. Kasturi, Advocate, Bangalore.

The Government of India by its order No. L-17012/3/75-D-II/A dated: 5-7-1976 has referred the present dispute for adjudication of the following points:

all other relevant matters into consideration, is the management of National Insurance Company limited justified in not providing employment to Mrs. B. Kochhar from the 1st January, 1975? If

“Whether taking the 8 years of continuous service put up by Mrs. B. Kochhar under Shri P. K. Rajagopalan, Inspector, the Royal Insurance Company and now merged with National Insurance Company Ltd, and not, to what relief is the said workman entitled?”

The I party has then filed her Claim Statement and she contends as follows:

2. She joined the Royal Insurance Company on 21-10-1966 as per the letter issued by the then Inspector Shri P. K. Rajagopalan. She was attending to the work of the Royal Insurance Company in a clerical and secretarial capacity. She was paid a salary of Rs. 200 per month. It was revised from time to time and she was getting Rs. 310/- as on 31-12-1974. Her work was subject to the supervision of the manager. It was a foreign Company and it had an office at Bangalore. Since Rajagopalan was attending to field work, the company felt the necessity of giving Secretarial assistance to him. The Bombay Office had asked him to appoint Secretary and then she was appointed. The business of the said Company was nationalised in 1973. The notification regarding taking over of the business was issued on 1-1-1973. By virtue of the said enactment she was entitled to be treated as an employee of National Insurance Company Ltd., Her other colleagues were transferred to the General Insurance Company. The action of the II party in not continuing her in the service and their refusal to take her back is violative of Article 14 & 16 of Constitution of India. The salary was paid to her by Rajagopalan at Bangalore and it was only an arrangement of convenience. It used to be reimbursed every month by the Bombay Office as an item of the imprest amount. When Rajagopalan was hospitalised or used to be on leave, she used to pass cover notes. Her salary was revised from time to time with concurrence from the Bombay office. There was no personnel work of Rajagopalan to be attended to by her. She had put in continuous service from October, 1966 to 1-1-1975. Even after 1-1-1973, she continued to work as before in the office of the II party management at M. G. Road, Bangalore. She used to work under the instruction of Rajagopalan who had become the employee of the II party from 1-1-1973. In early part of 1974 she learnt that the Divisional Manager wanted to terminate her services. She then gave a representation to Rajagopalan. She had written letters to the custodian and Convenor. The Bangalore Unit of Royal Insurance Company came under the control of Custodian on 19-5-1971. Neither the Custodian nor the II party demurred against her work. The II party is estopped from saying that she was not their employee. An award may be passed for reinstatement and continuity of service and consequential benefits.

3. The II Party has filed its counter statement and its contentions in brief are as follows:

She was employed as a Private Secretary to Mr. P. K. Rajagopalan, an employee of the Royal Insurance Company. There was no privity of contract between the I Party and II Party. Royal Insurance Company was nationalised in 1973. Its business vested in the II Party. There was no privity of contract between them. It is not a case falling under the provisions of Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947, and the I Party cannot raise the dispute. There is no espousal of the dispute by a substantial number of workmen. This Court has no jurisdiction to entertain the dispute. She was not on the rolls of the Royal Insurance Company. It may be that she may be attending to the work of Royal Insurance Company, but she used to work in her capacity as a Private employee of Rajagopalan. Her work was not supervised by the Manager. The Bombay office had not requested Rajagopalan to appoint her. Since she was not an employee of the Royal Insurance Company, the question of her becoming employee of the II Party does not arise. The provisions of articles 14 and 16 are not attracted. They understand that the Royal Insurance Company was paying certain allowance to Rajagopalan for getting certain assistance and that Rajagopalan had engaged the services of the I Party. It is denied that her salary was revised under the instructions of Bombay office. Her services have been terminated by Rajagopalan. It is denied that there was no personnel work of Rajagopalan to be attended to by her. It is denied that she continued to work as before even after 1-1-1973 in the office of the II Party. She was working only for Rajagopalan who terminated her service on 1-1-1975. It is denied that her salary was revised by them after 1-1-1973. It is denied that the Divisional Manager asked Rajagopalan to terminate her services. There is no estoppel because there was no privity of contract. The reference may be rejected.

4. In view of the said pleadings the following two additional issues have been raised:

1. Whether the reference is bad for the reasons mentioned in Para II of the II Party statement.

2. Whether the reference by the Central Government of this dispute to this Tribunal is maintainable without the Central Government proceedings to adjudicate the dispute before making a reference as required under the General Insurance Business Act, 1972?
5. The II Party has examined Rajagopalan and has got marked Ext. M-1 to M-8.
6. The I Party has examined herself and has got marked Ext. W-1 to W-7.
7. The parties have been heard.

My findings on the additional issues and point of reference are as follows:

Additional Issue No. 1: The reference is not bad.

Additional Issue No. 2: The reference is maintainable even though the Central Government has not adjudicated the dispute under Section 7(2) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (hereinafter called as the Nationalisation Act).

POINT OF REFERENCE

The II Party was not justified in not continuing the services from 1-1-1975. She is entitled to the relief shown below:

REASONS

Additional Issue No. 1: In para II of the Counter statement two points have been raised. The I Point relates to want of privity of contract. The II Point relates to espousal, on the footing that it is not in industrial dispute. The first point will be discussed while dealing with the point of reference.

8. It was urged before me that Section 2-A has no application since it is not a case of discharge, dismissal or other kind of termination of services. The contention is not available for the II Party. Ext. M-2 dt. 30-12-1974 is a letter by Rajagopalan to the I Party. It shows that the II Party had expressed before Rajagopalan that it was not possible to absorb the I Party and that it was necessary that he should terminate her services, which he had utilised. The letter makes it clear that on the basis of such instructions Rajagopalan terminated her services by sending a sum of Rs. 310 being the salary of one month. Since the letter Ext. W-2 makes it clear that it is a case of termination of services which means the same thing as not continuing her in service from 1-1-1975, I find that the provisions of Section 2-A are attracted and that the reference is not bad.

Additional Issue No. 2: There is no dispute on the point that the Royal Insurance Company was nationalised and by virtue of provisions of Section 7(1) of the Nationalisation Act the employees of erstwhile companies became the employees of the Indian Insurance Company. Section 7(2) of the said Act states that if any question arises as to whether any person was an employee of the General Insurance business of the existing insurer, the same should be referred to the Central Government and that its decisions shall be final. In para 8 of the claim statement she has pleaded that neither the custodian after 18-5-1971 nor the II Party after 1-1-1973 objected against her work. There is nothing in the counter statement to suggest that either the custodian or the II Party raised any objection against her work after 18-5-1971 or 1-1-1973. Prior to her services were terminated in December, 1974 as per Ext. W-21, the Convenor of the II Party had written a letter to Rajagopalan as per Ext. W-3 on 10-9-1974. That the case of his Secretary can be considered when a suitable vacancy arises. Ext. W-5 is a letter by the I Party to the Convenor dt. 10-5-1974 that her services may be regularised. Ext. W-4 dt. 10-9-1974 is a letter by Rajagopalan to the Convenor. Whereby Rajagopalan enclosed her letter Ext. W-5 and requested the Convenor to regularise her services, for she had been working in the Royal Unit since the past 7 years and she had been paid from the imprest amount. Ext. M-7 is the same as Ext. W-5. Ext. W-6 is a letter of 7-3-1974 whereby Rajagopalan requested the Branch Manager to confirm her on the rolls of the Company. The appointment order at Ext. M-1 discloses that she was appointed for

the work of Royal Insurance Company. Ext. M-2 to M-7 indicates that she was paid for the work of the Royal Insurance Company. The oral evidence of MW-1 Rajagopalan makes it evident that he used to be away from the office for field work and as such he had appointed her to attend to the office work and the same was done with the concurrence and approval of Head Office of the Royal Insurance Company. He further admits that her salary was being paid from the imprest amount of the Company kept with him. He further concedes that she used to attend to office correspondence and used to sign for him on Insurance Cover Notes. He admits that he has signed the conciliation proceedings, Ext. W-1. MW-1 Rajagopalan and WW-1 M/s. Blossom, both agree on the point that she was not attending any personnel work of Rajagopalan but used to attend to only the work of Insurance business.

9. The appointed day was 2-1-1973 as per Section 3(b) of Nationalisation Act. There is no dispute on the point that notification of nationalisation was issued on 1-1-1973. In order to raise a dispute either party should have approached the Central Government before 1-1-1975 as required by Section 7(2) of the Nationalisation Act. Ext. W-2 states that her services have been terminated w.e.f. 1-1-1975. The I Party had therefore no opportunity to approach the Central Government before the said date. It was the Custodian and the II Party who were deriving the benefit of her services and were suffering the payment of her salary through Rajagopalan from 18-5-1971 and 1-1-1973 and if they had any grievance against her continuation in Insurance business, they should have approached the Central Government before 1-1-1975. The II Party cannot take advantage of its own default. It is important to note that in sub-section (2) of Section 7 of the Nationalisation Act there is no non-obstante clause whereas there is such a clause in sub-section (3). Thus it is evident that Section 7(2) is no bar as against the I Party for maintaining the reference under the provisions of the Industrial Disputes Act.

10. Point of Dispute: The main dispute is on the point whether Miss. Kochar was only an employee engaged by Rajagopalan to do some part of his work or whether she had become the employee of Royal Insurance Company and subsequently of National Insurance Company. Either by virtue of the contract or by virtue of my provision of law, Ext. M-1, the copy of the order shows that she was appointed on the condition that she will not disclose about the business of the Company to any one either during her service or after termination of her service. Ext. M-2 to M-7 are the salary receipts. They show that she had received the salary from Rajagopalan of National Insurance Company for certain months of the period between January 1973 to December, 1974. Ext. W-1 the conciliation proceedings indicates that Miss. Kochar and Rajagopalan asserted before the Conciliation Officer, that she was employed for the work of the Insurance Company. Ext. W-2 is the letter issued by the Rajagopalan to Miss. Kochar on 30-12-1974. Wherein he has reproduced certain portion of the letter received by him from Divisional Manager of the National Insurance Company. It is obvious from the letter that under the instructions of the Divisional Manager her services were terminated. He has however thanked her for helping him to build up such a business which has created the record in the Bangalore Inspectorate. The documents at Ext. W-3 to W-7 from the correspondence among Miss. Kochar, Rajagopalan and the II Party. Ext. W-6 dated: 7-3-1974 is a letter by Rajagopalan and it specifically states that the Branch Manager had accepted to pay her salary by reimbursing. Ext. M-5 is a letter dated 10-9-74 by Miss. Kochar to the convenor of the Company. Ext. W-4 dt. 10-9-74 is a letter by Rajagopalan to the Convenor and it was enclosed by Ext. W-5. Ext. W-3 dated 23-9-1974 is a letter by the Convenor to Rajagopalan in reply to Ext. W-4. In his letter Ext. W-4 Rajagopalan pointed out that for the last 7 years, Miss. Kochar was looking after the interest of the Company and she was paid from the imprest cash which was reimbursed and that her services were necessary to look after the organisation of the Company. Ext. W-3 states that her case may be considered when a suitable vacancy arises. The documentary evidence thus shows that though she was employed by Rajagopalan and paid by him her services were utilised for the organisation of the Company, exclusively and she was paid from out of the funds of the II Party with its consent.

11. Turning to the oral evidence, it is to be noted that Rajagopalan MW-1 has admitted in his evidence at para 5 that he was in need of a secretary for the work of the Company and he has therefore appointed her to attend to the office work and it was with the concurrence of Head Office of Royal Insurance Company. He further swears that the appointment letter Ext. M-1 was approved by the Head Office before it was issued. On going through the letter Ext. M-1 it can be very well made out that there is all the truth in the evidence of MW-1 because the letter of appointment secures a promise from the employee that she shall keep the business matter of the Company as a confidential matter of the company, even after she ceases to be their employee. The evidence of Rajagopalan further discloses that her salary was increased from time to time and that it was paid from his imprest amount. He adds that she used to attend to office correspondence and at times used to sign the cover notes also on his behalf. It is further admitted by him that he used to send the salary vouchers to Head Office at Bombay. The vouchers at Ext. M-2 to M-7 have been produced by the II Party from its own custody and thus I find that there is absolutely nothing to believe the evidence of MW-1, Rajagopalan. He was made a clear statement that Mrs. Kochar was not appointed to do any of his personnel work. No attempt has been made by the II Party to disclaim the evidence given by MW-1, Rajagopalan, despite these admissions. The evidence, produced by II Party itself shows that Mrs. Kochar was appointed for the work of the Company and paid by them. The evidence produced by the I Party consists of the oral testimony of Mrs. Kochar and documents marked as 'W' series. They are a bunch of correspondence and the said correspondence is an admitted fact. WW-1, Mrs. Kochar has sworn that she was appointed as the Secretary to MW-1, Rajagopalan in the Royal Insurance Company and after the nationalisation in 1973, she continued to work in the same. Since it had become the part of the National Insurance Company she has enumerated the items of her work as writing of letters, signing Insurance cover notes in the absence of MW-1 and answering phone calls. She adds that Rajagopalan was supervising her work and she was paid from the imprest amount that used to be with him. She had pointedly stated that she was not doing personnel work of Rajagopalan. The cross-examination of WW-1, Mrs. Kochar indicates that there was no appointment order issued by Royal Insurance Company or the II Party after 1973, in my view in the absence of any appointment letter is no criteria.

12. The learned counsel for the II Party referred to the case of Punjab National Bank Gulam Dastagir [1978 (1) LLI Page 312] and submitted that in the absence of an appointment order by the employer it cannot be said that, there exists employer-employee relationship. The authority states that unless it is shown that control and direction of the work vested in the employer it cannot be said that the workmen employed by an Officer becomes the employee of the employer. The facts of the reported case show that there was no nexus between the Driver and the Bank and there was nothing on record to indicate that the Control and direction vested in the Bank.

13. While discussing the facts of the present case finding has been arrived at to the effect that she was working under the control and direction of Rajagopalan who in turn had such control and direction from the Royal Insurance Company, prior to 2-1-1973 and of the II Party after the said date. Since the facts are different, I am of the opinion that the authority is of no help to the II Party.

14. The learned counsel for the II Party then cited the case of Thungabhadra Sugar Works Ltd., vs. Labour Court, Bangalore (1983-1 LLI Page 465). The authority is on the point that before a workman can succeed, there should be material on record to show that there was employer and employee relationship between them. The analysis of evidence as discussed above shows that there was employer and employee relationship between the parties. The evidence discloses that supervision and control vested in the II Party. There is not even a suggestion made to Mrs. Kochar that she was not signing the cover notes which are important documents of business. On page 489 to 491 of the Law of Industrial Disputes by Shri O. P. Malhotra (Volume 1, 4th

Edition) there are number of cases to show as to how the Court should appreciate the facts in arriving at a conclusion, whether the employer and employee relationship exists or not. The II Party had a case that Mrs. Kochar was in the personal employment of Rajagopalan and nothing prevented it from directing Rajagopalan to stop the services, immediately after 2-1-1973. Instead the II Party has implidely accepted the representation made by the Rajagopalan that her services were necessary for the business of organisation of the Company and the II Party has accepted the salary voucher showing payment of her salary from the funds of the Company. The evidence of Rajagopalan shows that the supervision and control of the service rendered by her vested in the II Party. The fact that he issued the order of termination on the direction of the II Party fortifies the said finding. Taking into account all these factors I find that the I Party has proved that she was the employee of the Royal Insurance Company and subsequently of the II Party.

14. The evidence on record shows that the termination of her services is not in accordance with law. It is neither a case of discharge simpliciter supported by any provision of law, nor of dismissal for misconduct nor of retrenchment within the ambit of Section 25F of the Industrial Disputes Act, It cannot be upheld.

15. The next question for consideration would be to what relief the I Party is entitled. The learned counsel for the I party submitted before me that she is ready and prepared to get reinstated in the employment of II Party. The learned counsel for the II Party strongly contend that Ext. M-8 and the admission made by her would show that she is an Income Tax assessee. Well placed in her profession as beautician and dietician and that she is not interested in re-employment and not entitled to back wages. It was submitted by the learned counsel for the I Party that without any pleading to that effect, the said contention of the II Party cannot be maintained. The II Party has proceeded on the footing that there was no employer-employee relationship and in such a context what relief the Court should grant shall have to depend upon the evidence on record. Mrs. Kochar has admitted in her evidence that she had been running a clinic at Delhi since 6 or 7 years and that she is a beautician and dietician. She further admits that she conducts demonstrations are held at Army and Airforce Quarters. She further concedes that she is a very well known beautician in Delhi, commanding good number of clientele. She has evaded to disclose her income, though she admits that she is an Income Tax assessee. Her evidence has been recorded on 11-3-85. If she has been running a clinic, since about 7 years before 11-3-1985, and has established a good lot of clientele it will not be in the interest of either party to dislodge her from the said profession. The evidence thus shows that atleast from 11-3-1978, she cannot claim back wages. Her services have been terminated on 30-12-1974. The period between 30-12-1974 to 11-3-1978 would be about 3 years 2 months and 11 days. The salary she was drawing at the time of termination was of Rs. 300 per month. The amount for the period of 3 years, 2-1/2 months would be Rs. 11,550. Since no order of reinstatement is passed, I am of the view that only a compensation of Rs. 15,000 would meet the ends of justice.

AWARD

In the result an award is hereby passed that the II Party was not justified in not providing employment to her. But however it is held that it is a fit case to award only compensation of Rs. 15,000 without reinstatement.

(Dictated to the Secretary, taken down by him, and corrected by me).

B. N. IATGE, Presiding Officer
[No. L-17012/3/74-D II(A)/D IV(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

तर्हि दल्लो, 19 अगस्त 1987

क. प्र. 2322--केन्द्रीय सरकार ने यह सन्धान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद प्रशिक्षण-1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के उपखंडों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रशिक्षण संस्था का.

आ. 722 दिनांक 24 फरवरी, 1987 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट मिंट दफ्तरों का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 फरवरी, 1987 से छः मास की कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार का राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (V) के उपखंड (ii) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अगस्त, 1987 से छः मास की और कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करता है।

[फा.सं. एम.-11017/3/85-बि-ए]

New Delhi, the 19th August, 1987

S.O. 2322.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 722 dated the 24th February, 1987 the India Government Mint, Bombay to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 24th February, 1987;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th August, 1987.

[No. S-11017/3/85-D.I(A)]

का.आ.-2323 भारत सरकार के पूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की तारीख 5 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या का.आ. 461 के तहत गठित श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, के पोटासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री कंगाराबापाठि के पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का पोटासीन अधिकारी नियुक्त करता है।

[सं. एस.-11020/7/81-बि-1(i)]

नन्द लाल, प्रधान सचिव

S.O. 2323.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Madras constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 461, dated the 5th February, 1963.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shiru R. Kanagasabapathi, as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[N. S-11020/7/81-D.I(A)]
NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1987

का. आ. 2324—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेक्टर कमीशन, सेक्टर 734 फोरकास्टिंग विभाग के प्रबंधन से सम्बद्ध विरोधकों और कर्मचारियों के बीच, अग्रिम में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में

औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th August, 1987

S.O. 2324.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Water Commission, Central Flood Forecasting Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1987.

BEFORE SHRI C. G. RATHOD, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 14 of 1987

Adjudication

BETWEEN

Central Water Commission
1st Floor, Chhikniwala Chambers
Gomtipur, Ahmedabad-380021

—First Party

AND

Shri Nandubhai Prahladbhai Nayak
Room No. 506, Block No. 92, G. H. Ward
Chandkheda, Ahmedabad

—Second Party

In the matter of terminating the services of Shri Nandubhai Prahladbhai Nayak w.e.f. 17-2-84 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled to?

APPEARANCES:

Shri V. M. Joshi appeared for the second party.

STATE: Gujarat.

INDUSTRY: Irrigation
Ahmedabad

AWARD

By an order No. L-42012/43/84-D.II(B) dated 16th February, 1987, the Desk Officer of the Central Government, Ministry of Labour, New Delhi in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), has referred the dispute namely whether the action of the management of Central Water Commission, Central Flood Forecasting Division, Ahmedabad, in terminating the services of Shri Mandubhai Prahladbhai Nayak w.e.f. 17-2-84 was legal and justified and if not, to what relief he was entitled to?

2. The second party, workman has filed his statement of claim at Ex. 3. Briefly it is stated as under: "that the Central Water Commission appointed the workman as Workcharge Driver in July, 1978 and he joined his duties on 20-7-78. He was carrying on his duties honestly and faithfully and there was no complaint in respect of his work. It is further his case that on 17-2-84 without conducting any departmental enquiry, the Central Water Commission terminated his services. The workman, therefore, approached the Labour Commissioner of the Central Office on 7-3-84. Thereafter as there was no settlement in the conciliation proceedings there was a failure report and ultimately the reference is made to this Tribunal. It is the case of the workman that he has been illegally terminated; that the said action of the Commission is illegal, improper and against the principles of natural justice and is also against the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act. He had, therefore, prayed that he be re-instated with continuity of service and be paid full back wages; that the cost of this reference be awarded to him.

3. The Central Water Commission, the first party was duly served with a notice and its acknowledgement is at Ex. 10. In spite of the same, it appears that no one has appeared on the date of filing of the statement of claim or on the date of filing of the written statement or thereafter. Thus the matter was proceeded ex-parte.

4. Mr. V. M. Joshi appeared for the second party-workman and led the evidence of the workman in the present case.

5. It may be stated that in the instant case even the copy of the statement of claim was sent to be Director, Central Water Commission by Regd. post and the acknowledgement is produced at Ex. 9. no one appeared for the Commission.

6. The evidence of Shri Mandukhai Prahladbhai Nayak, Ex. 9 is to the effect that he joined as Workcharge Driver on 20th July, 1978. According to him, there was no complaint as regards the work. In other words, it is his case that he was doing his work satisfactorily. His services were, however, terminated w.e.f. 17th February, 1984. No notice was served upon him before terminating his services, nor any departmental enquiry was held. He, therefore lodged a complaint with the Commissioner of Labour (Central). He prayed that he be re-instated with full back wages.

7. Now it appears from Ex. 7, Office Memorandum issued by the Deputy Director of Admn. II of the Central Public Works Department that the Government has clarified that the Quasi-permanent status may be granted to the eligible temporary workcharged employees with effect from 18-12-75 or w.e.f. the date of completion of three years continuous service, whichever is later. In the instant case, the concerned workman joined as Workcharge Driver on 20-7-78 and, therefore, he was entitled to Quasi-permanent status on completion of three years of his service i.e. from 20-7-81. In spite of the same, he, it appears, was relieved from his service from 17-2-84. His services were terminated as he was no longer required by the office as per Ex. 8. It is clear that when the person was working for about six years with the Commission, the Commission was not entitled to terminate his services without assigning any reason by merely stating that his services were no longer required. Unfortunately, the Commission had not appeared and filed its statement, nor it has led any evidence and, therefore, there are no facts which could be canvassed as the arguments for the first party. When the person has served for about six years with the Central Water Commission, he was entitled to a Quasi-permanent status as per the Office Memorandum as above. In any case, it is clear that his services can not be terminated in the manner as stated above. Again even as per Section 25B of the I.D. Act, the concerned workman must be deemed to be in continuous service for not less than one year, and as such also he could not have been retrenched u/s. 25F without following the procedure as laid down therein. It appears, therefore, to me that the action of the first party in terminating the services of the workman is illegal, improper and ab initio which requires him to be re-instated with full back wages. I therefore, pass the following order.

ORDER

8. The reference is allowed. The concerned workman, Shri Nandubhai Prahladbhai Nayak be re-instated within one month of the publication of this award. He paid full back wages with continuity of service from 18-2-84 till the date of his being re-instated. he difference as above, shall also be paid within one month from the date of publication of this award. The Central Water Commission shall pay Rs. 150 as cost of this reference to the concerned workman.

C. G. RATHOD, Presiding Officer
[No. L-42012/43/84-D. II(B)]

Ahmedabad, 30th June, 1987.

का. अ. 2325.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार, इंडियन इयर-लार्स यमर्स के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कार्यों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-I, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 मार्च 1937 को रजिस्ट्रार था।

S.O. 2325.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay-I, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines, Bombay and their

workmen, which was received by the Central Government on the 4th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-8 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to Indian Airlines, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer—Mr. Verma, Advocate.

For the Workman—Mr. Shetty, Advocate.

STATE : Maharashtra

INDUSTRY : Airlines

Bombay, dated the 1st day of May, 1987

ORDER

The dispute referred to this Tribunal relates to the removal from service of Shri K. T. Kodte, who was employed in the catering department of the Indian Airlines. The workman was charge-sheeted under the standing orders applicable to him for committing breach of para 1 of the Standing Orders and misconducts as set out in paras 16(1), 16(37), 16(11), and 16(13) of the Standing Orders, on the allegation that he entered the cabin of the aircraft operating Flight No. IC-274 remained inside the cabin even when the passengers were boarding the aircraft and in disobedience of the direction given by the Air Hostess, Miss. R. Mohana and the catering Assistant Mr. K. T. Basak to move out of the cabin and misbehaved with the teenaged daughter of one Dr. P. K. Chakravarty who was seated on row No. 18 and disappeared when the girl started crying. It was also alleged that due to this misbehaviour, there was commotion which resulted in one hour delay to the flight and also greatly tarnished the image of the Indian Airlines.

2. The alleged incident took place on 24th July, 1982 when the workman was on duty in connection with flight No. IC-274 from Bombay to Calcutta. Disciplinary action was taken on the basis of the written complaint filed by Dr. P. K. Chakravarty, immediately after the incident. By an order dated 26th July, 1982 (Ex-M-1), the Commercial Manager suspended the workman from service and a charge-sheet was served on him on 30th August, 1982. The workman submitted his explanation to the Commercial Manager on 22-9-1982 (Ex-M-3). As the reply was found to be unsatisfactory, the Commercial Manager appointed Shri A. L. Bhat, Senior Deputy Manager, Personnel Services, as the enquiry officer and communicated this order to the workman vide Exhibit M-4. The Enquiry Officer fixed the date of enquiry as 28th January, 1983 and informed the workman accordingly by letter dated 14th January, 1983. The enquiry officer found the workman guilty of the misconducts complained of and submitted his report to the Commercial Manager vide Exhibit M-6 on 5-5-1983. The Commercial Manager concurred with the findings of the enquiry officer and proposed to remove the workman from the service of the Indian Airlines. He issued a show-cause notice (Ex-M-8) dated 23-5-1983 and called upon the workman to show cause within 8 days from the date of the receipt of the notice as to why the proposed punishment should not be imposed on him. The workman, Shri Kodte submitted his reply on 9th June 1983 (Exhibit-M-9). His reply was found to be unsatisfactory by the Commercial Manager who communicated the order to the workman, removing him from the service by his letter (Ex-M-10) dated 17th June, 1986.

3. The workman challenged the enquiry on various grounds. The management while maintaining that just, fair and proper enquiry was held against the workman and the charges levelled against the workmen were duly established, sought liberty to prove the alleged misconducts in case it is held that the enquiry was not proper. The workman also contended that the punishment awarded to him was not commensurate with the gravity of the misconduct. Issues arising out of these contentions were framed and the one about the legality of the enquiry was treated as the preliminary issue.

4. As mentioned above, the workman challenged the enquiry on various grounds. According to him, the procedure prescribed for holding departmental enquiry was not explained to him and hence he could not be properly represented during the enquiry. No statement of the workman was recorded before the enquiry was completed. The enquiry which was completed on 28th January, 1983 was reopened and held ex-parte without giving an opportunity to him to cross-examine the witness who was examined behind his back. The enquiry officer based his findings in respect of the second charge on hear-say and irrelevant evidence there being no legal evidence to substantiate the said charge. The material witnesses were not examined and there was complete non-application of mind on the part of the enquiry officer. The findings were perverse and vitiated the enquiry.

5. It is an admitted position that the workman was allowed to be represented during the enquiry by one D.T. Kodte, who was working as a Sweeper in the commercial department of the Indian Airlines. The workman appointed Shri D. T. Kodte as his representative in response to the letter dated 14th June, 1983 addressed to the workman by the enquiry officer informing him inter alia that he was free to avail of the assistance of a friend who must be an employee of the Indian Airlines. The grievance of the workman now is that had the procedure been explained to him properly, he would have arranged better representation which was necessary in view of the gravity of the charges levelled against him. There is no substance in this contention because Standing Order No. 32 which is applicable to the concerned workman lays down that the employee may be permitted, if he so desires to have, under his own arrangement, the assistance during the course of the enquiry, of a friend who must be an employee of the Corporation, and no outside representation is permitted under any circumstances. It is this provision which was brought to the notice of the workman by the enquiry officer when he was informed that he was free to have under his own arrangement the assistance of a friend who must be an employee of the Corporation. There is also nothing on record to show that the workman requested the enquiry officer to allow him to be represented by an office bearer of any union or an advocate. The enquiry officer faithfully brought to the notice of the workman the relevant provision in this behalf and the workman himself chose to make his choice of the friend for defending him during the enquiry. He never wanted any better representation and he cannot complain about the choice made by him in this behalf.

6. It is true that after the evidence of management witnesses was recorded, the workman was not examined by the enquiry officer and the enquiry was concluded when the workman stated that he did not want to examine any witness in his defence. This, it is contended was a material irregularity which vitiated the enquiry. There is no substance in this contention because the workman was asked to submit his written statement by 8th February, 1983. The enquiry was commenced and concluded on 28th January, 1983 and at that stage the workman was asked to submit his written statement. Accordingly, the workman did submit his written statement on 4th February, 1983. Much cannot therefore be made out of the fact that after the conclusion of the management's evidence no oral statement of the workman was recorded.

7. Equally unsustainable is the contention that the enquiry was reopened and evidence was recorded behind his back. As mentioned above, the workman submitted his written statement on 4th February 1983. In this statement, the workman made a grievance that Air Hostess Miss Mohana was not produced before the enquiry officer to record her evidence even though she was the main witness as per the charge-sheet. It will be seen from the enquiry papers that after the enquiry officer received this written statement, the workman and the officer representing the management were called by the enquiry officer in his office on 18th February 1983 and the presenting officer representing the management was asked as to what he had to say about the statement made by the workman. At that stage the presenting officer expressed his desire to examine Air Hostess Miss Mohana. The workman agreed to calling Miss Mohana so that he would have an opportunity to cross-examine the Main witness in the case. This is what the enquiry officer has noted on 18th February, 1983.

"Shri K. T. Kodte, Catering Helper as well as Shri R. B. Modak, Reservations Manager—Presenting Officer were called in the office of the undersigned on February 18, 1983. The Presenting Officer was asked whether he has to state on the statement made by Shri Kodte. The Presenting Officer desired to examine Miss Mohana Air Hostess, Shri Kodte, agreed to calling Miss Mohana, Air Hostess, so that he will have an opportunity to cross-examine the main witness in the case."

This noting made by the Enquiry Officer is signed not only by him but also by the workman and the presenting officer. It is thus clear that the enquiry was reopened with the full concurrence of the workman also. Then after Miss Mohana was called as a witness and the enquiry was fixed on 24th April, 1983. The workman was duly informed by letter dated 13th April, 1983 which he acknowledged on the 15th. On that date, the workman chose to remain absent and hence the evidence of Miss Mohana was recorded in his absence. It is pertinent to note that the workman's friend Shri D. T. Kodte was present and informed the Enquiry Officer that the workman had received the letter and that he himself was waiting for the workman to come. It will also be seen from the proceedings on 20th April, 1983 that the enquiry officer waited for the workman till 12.15 hours and then proceeded to record the evidence of the Air Hostess Miss Mohana. The workman's friend D. T. Kodte did not cross-examine the witness perhaps because he chose not to do so in the absence of the workman. The workman never made a grievance that his friend was not allowed to cross-examine Miss Mohana. It is significant to note in its context that Miss Mohana had to come all the way from Delhi for the enquiry. There is, therefore, sufficient scope for drawing the inference that the workman purposely remained absent. There is, therefore, no substance in the contention that the enquiry which was concluded on 28th January, 1983 was unjustifiably reopened and conducted ex-parte without giving opportunity to the workman to cross-examine the witness examined. As a matter of fact, it would not be correct to say that the enquiry was concluded on 28th January, 1983 even though the enquiry officer stated so in the proceedings of that day. As mentioned above, the workman was called upon to give his explanation in writing and the explanation was submitted by the workman on 4th February, 1983.

8. The most important infirmity which according to the workman completely vitiated the findings of the enquiry officer in respect of the second charge is that neither the girl nor her father who gave the written complaint was examined and the enquiry officer based his findings on hear-say evidence of persons who were not present at the time of the alleged incident. It is contended that the said charge is not proved by any legal evidence. It is true that neither the girl nor her father was examined during the enquiry to substantiate the complaint lodged by the latter with the airport authorities. Instead, the management examined Shri K. T. Basak, Catering Assistant and Miss Mohana, the Air Hostess who had directed the workman to leave the Aircraft and Shri Ramesh Malhotra, Security Officer who submitted a report about the misbehaviour of the workman vis-a-vis a girl-passenger. Shri Basak did not speak about the incident which is the basis of the second charge and Miss Mohana had not referred to this incident in her statement recorded after the incident. Admittedly neither Shri Ramesh Malhotra nor Miss Mohana actually witnessed the incident. But the evidence of Ramesh Malhotra cannot be considered as hear-say because even though he had not actually witnessed the incident he himself made enquiries, as directed by the Commander of flight IC-274 with the complainant and it was at his request that Shri P. K. Chakravarty wrote the complaint in his presence. This is what Ramesh Malhotra stated in his evidence:—

"I was on duty at the terminal on 24th July, 1982. The Security Assistant informed me that the Commander of Service IC-274 wishes to see me inside the Aircraft. On meeting the Commander he informed me that one of the passenger has complained to him about the misbehaviour by one of our employees with the passenger's daughter. The Commander sent one Air hostess alongwith me to identify the passenger who made complaint. This passenger was requested to come near the cockpit. After he came

near cockpit and after hearing his complaint I requested him to put the same in writing which he did."

Shri Malhotra proved the complaint lodged by Shri P. K. Chakravathy and also the aforesaid report which he made on the basis of the said complaint and the enquiries personally made by him. It is significant to note in this context that the evidence of Shri Malhotra remained completely unchallenged. The workman had nothing to ask Shri Ramesh Malhotra in cross-examination. In the complaint lodged by him, Shri P. K. Chakravathy, the father of the teen-aged girl stated as follows :—

"When we boarded the plane Indian Airlines (bounded to Calcutta) me and my wife sat on seat 17 and the two Children sat on seat 18, a youngish chap wearing Khaki tried to tickle and pinch my Daughter of 12 years on board. My daughter was extremely upset and crying and she was so shocked that she couldn't scream. When we found her weeping, she told us this incident but meanwhile the chap went away."

Miss Mohana also stated in her evidence, which also remained unchallenged, that :—

"....." On board of the aircraft before commencement of the flight one passenger came and complained to me that his daughter was pinched by a person in Khaki uniform and I conveyed this message to the Commander of the Aircraft."

Hence so far as complaint made by Shri P. K. Chakravathy is concerned, the evidence of both Miss Mohana and Ramesh Malhotra is directed and not hearsay.

9. In the case between Shri D. J. Jain V/s. Management of the State Bank of India (1982-I LLJ-p. 54) the workman was held guilty in the departmental enquiry of fraudulently altering the amount in the Letter of Authority given to him by one Kansal. The departmental proceedings were instituted on the basis of oral complaint made by Shri Kansal to the Ledger Keeper to Shri Wadhwa and the Supervisor Shri R. P. Gupta. Shri Kansal was not examined in the enquiry as management witness and the management advanced the evidence of four witnesses in whose presence the complaint was made by Shri Kansal. It was contended that the finding of the domestic enquiry was based on hearsay evidence. The Central Government Industrial Tribunal at Delhi held that on a perusal of the evidence recorded by the enquiry officer, the appellant could not be held guilty as in the absence of the evidence of Shri Kansal, the evidence recorded was hearsay. Consequently, the Tribunal set aside the dismissal and directed reinstatement of the workman with full back wages. The High Court however, held that the charges against the appellant were established and quashed the award of the Tribunal. The workman moved the Supreme Court contending inter alia that the evidence of the four witnesses was hearsay which could not be the basis of a finding about the guilt of the workman. Rejecting this contention. Their Lordships, relying on an earlier decision of the Supreme Court in State of Haryana and another Vs. Ratan Singh (1982-I LLJ-p. 46), held that the law is well settled that strict rules of evidence are not applicable in a domestic enquiry. They quoted with approval the following dicta laid down by the Supreme Court in Ratan Singh's case (citation supra).

"It is well settled that in a domestic enquiry the strict and sophisticated rules of evidence under the Indian Evidence Act may not apply. All materials which are logically probative for a prudent mind are permissible. There is no allergy to hearsay evidence provided it has reasonable nexus and credibility."

Their Lordships also rejected the contention that the evidence in the domestic enquiry was hearsay, observing thus in para 11 of the Judgment.

"The evidence of Kansal would have been primary and material if the fact in issue were whether Kansal authorised the appellant to make the alter-

rations in the authority letter. But Kansal's complaint was to the contrary. For the purpose of a departmental enquiry complaint, certainly not frivolous, but substantiated by circumstantial evidence, is enough. What the respondent sought to establish in the domestic enquiry was that Kansal had made a verbal complaint with regard to the withdrawal of excess money by the appellant in the presence of the four witnesses, namely Wadhwa Gupta, Ramzan and Sarkar, aforesaid, against his advice. On the complaint of Kansal, the evidence of these witnesses is direct as the complaint is said to have been made by Kansal in their presence and hearing, it is, therefore, not hearsay."

10. As observed by the Privy Council in the case of Subramaniam V. Public Prosecutor (1956 (1) W.L.R. 965), "Evidence of a statement made to the witness who is not himself called as a witness may or not be hearsay. It is hearsay and inadmissible when the object of the evidence is to establish the truth of what is contained in the statement. It is not hearsay and is admissible when it is proposed to establish by the evidence, not the truth of the statement but the fact that it was made."

11. In the case of State of Haryana and another V/s. Ratan Singh, (citation Supra) their Lordships of the Supreme Court considered the effect of the findings of departmental enquiry, of not examining the passengers from whom the workman, a bus conductor had collected excess fares which was the charge levelled against him. This is what the Supreme Court observed about the non-examination of the passengers and sufficiency of the evidence of the conductor.

"However, the Courts below misdirected themselves, perhaps, in insisting that passengers who had come in and gone out should be chased and brought before the Tribunal before the valid finding could be recorded. The "residuum" role to which counsel for the respondent referred, based upon certain passages from the American jurisprudence does not go to that extent nor does the passage from the Halsbury insist on such rigid requirement. The simple point is, was there some evidence or was there no evidence—not in the sense of the technical rules governing regular court proceedings but in a fair commonsense way as men of understanding and worldly wisdom will accept."

It is this clear that neither it was necessary to examine the girl and her father nor can it be said that the evidence of Miss Mohana and Ramesh Malhotra was hearsay on the question that a complaint was lodged by the passenger that the workman misbehaved with his teen-aged daughter.

12. It is also difficult to accept the contention of the workman that the finding are perverse. It was contended that there was no direct evidence to connect the workman with the alleged incident which is the basis of the second charge. It was appointed out that the girl and her father even refused to identify the culprit and stated that if such an identification was insisted upon, the complaint will be withdrawn. This contention had to be rejected because the workman never disputed that he was the cause of what made the girl to weep. His case all along was that at the instance of some lady sitting in a row ahead, he helped the girl to tighten the seat belt and nothing more. In the letter (Exh. M/3, dated 22-9-1982), he stated as follows in reply to the charge-sheet-

"When the Air-Hostess, Miss R. Mohana told me to move from the Cabin i.e. from Galley-II: passengers had already started to board the aircraft in a rush and I did not think it wise to elice through them, which might have created a obstruction to their normal entry. Thus, I finally started moving toward, the Galley-III alongwith the passengers incidently that was the only way I could get to the tail section of the aircraft and get into the hi-lift.

It was precisely then, when I was passing through the aisle. I noticed a girl about 10-11 years old struggling with her seat belt. Immediately a row ahead of the seat the girl was sitting, a lady gestured and requested me to help her tighten

the buckle of the seat, which I certainly thought would be an act of goodwill. It is precisely at this moment that I reduced the length of the belt and same instance realised my standing there might hinder other passenger to move along the aisle, so I left it and it must have dropped in the girl's lap and I moved to G. III. When I got down from the aircraft I heard something like "passengers complaining about misbehaviour by a staff" and my Duty Officer, Shri A. Rapose calling me to aircraft for identification."

13. In view of the evidence of Shri Malhotra and Miss Mohan and also in view of what the workman categorically admitted in his reply to the charge-sheet, it is difficult to accept the contention that the findings are perverse.

14. Both the charges levelled against the workman have been completely established by legal evidence. I, therefore, hold that the domestic enquiry against the workman was fair, just and proper and answer the preliminary issue in the affirmative.

FURTHER ORDER

Dated 21st July, 1987

In view of my finding on the preliminary issue, the question of the management proving the alleged misconduct before this Tribunal does not arise and hence the issue whether the management proved the alleged misconduct, does not survive for consideration. The only issue that now remains to be considered is whether the punishment awarded to the workman is commensurate with the gravity of the misconduct.

2. Shri Shetty for the workman contended that considering the age and the past clean record of the workman, the punishment inflicted in the workman is grossly disproportionate. There is absolutely no substance in this contention. Even though the charges arising out of his conduct in disobeying the directions given to the workman to leave the aircraft were not grave in nature, the man charge was of very grave nature. As mentioned above, the said charge arose out of the complaint lodged by the father of a girl passenger that his daughter was molested by the workman. As held above, this charge was duly brought home to the workman. The conduct of the workman in behaving indecently with a teen-aged girl showed the perversity of his mind and was injurious to the image of the Corporation. To retain such an employee in employment would certainly affect the credibility of the Corporation vis-a-vis the safety of respectable lady passengers travelling by the Airlines.

3. As rightly contended by the Corporation, the act committed by the workman was grave and serious and involved immodesty and indecency and his behaviour was injurious to the image of the Corporation, which merited harsher punishment of dismissal without retirement benefits. Hence this would have been reluctant to interfere even if the management would have inflicted harsher punishment of dismissal. But the management has not inflicted that punishment which the workman deserved but has taken a comparatively lenient view, perhaps looking to his past good record, and has only removed him from service. Looking to the gravity of the charge levelled against the workman, it is difficult to accept the submission that this punishment is also disproportionate. No doubt, the management has not disputed the claim of the workman that his past record was good, but the relevant question would be his potentiality for future mischief. The fact that the workman is a family man is not a mitigating circumstances, but makes his conduct more reprehensible. Though a married man, he showed the depravity of mind in molesting a 12 year old girl. It would certainly be not in the interest of an Airlines which has constantly to deal with lady passenger, to continue such a person in the employment. There is therefore, absolutely no justification for interfering with the already lenient punishment inflicted on the workman by the management of the Indian Airlines.

4. In the result, therefore, I hold that the action of the management of Indian Airlines in relation to its Catering Department, Old Airport, Santacruz, Bombay in removing

Shri Kodte, Cabin Cleaner, from service was completely justified and that the workman is not entitled to any relief.

5. Award accordingly.

M. S. JAMDAR, Presiding Officer
[No. L-11012/3/85-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1987

सं. अ. 2326.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, राजकुमार स्टोन क्वारी वाडी (जिला सुरत) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवाद में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण प्रहमवादाद के पचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st August, 1987

S.O. 2326.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Employers in relation to the management of Raj Kumar Stone Quarry, Vadi (Distt. Surat) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1987.

BEFORE SHRI N. A. CHAUHAN, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
AHMEDABAD

Ref. (ITC) No. 6 of 87

Adjudication

BETWEEN

Raj Kumar Stone Quarry, Vadi, Dist. Surat

... First Party

AND

The General Secretary Maha Gujarat Khan Udyog Kamdar Sangh, Congress, Bhavan, Soni Falia Distt. Surat

... Second Party

STATE : Gujarat

INDUSTRY : Ahmedabad

In the matter of termination of services of Shri Mohanbhai V. Vasava w.e.f. 1-11-83.

AWARD

This reference under section 10(2A) (i) (d) of the I. L. Act, 1947 has been referred on behalf of the Central Government by the Under Secretary, Ministry of Labour, vide its Order bearing No. L-29012/64/84-D. III (B) dt. 14th January, 1987 for determination of the industrial disputes mentioned therein between the parties. The dispute referred is :

"Whether the action of the management of Raj Kumar Stone Quarry Vadi, Dist. Surat in terminating the service of Shri Mohan Vaidya Vasava w.e.f. 1-11-83 is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled and with what effect ?"

2. The order of reference shows that the order of referring the dispute to this Tribunal was communicated by the Under Secretary to the Ministry of Labour, Government of India to an parties and the Second party was to file the statement of claims with relevant documents, within 15 days from the receipt of order of reference and also to forward the copy thereof to the opposite party. In spite of that the second party at whose instance the reference was made by the Government did not bother to file any statement of claim, but even then this Tribunal called upon the second party to file the statement of claim on or before 13th March 1987 and to inform the first party about the same. The second party in spite of service of the aforesaid notice did not remain present. The first party had remained present and given application at Ex. 2. that unless a statement of claim is given by the second party nothing can be done by them. In the interest

of justice the matter was adjourned and the second party was served with another notice dt. 16th April, 1987 by Regd. A.D. to appear before this Tribunal on 24th April, 1987. In spite of the service of aforesaid notice (Ex. 3) vide Regd. A. D. Slip at Ex. 5, the second party did not bother to file the statement of claim. Still however, in order to give one more chance the matter was adjourned to 23rd June, 1987. Even on that date the second party did not appear and file any statement of claim. The first party also did not appear before this Tribunal.

ORDER

This reference is rejected for want of prosecution by second party at whose instance this reference was made. Considering the facts there shall be no order as to the cost of this reference.

N. A. CHAUHAN, Industrial Tribunal
Ahmedabad, 30th June, 1987.

[No. L-29012/64/84-D. III (B)]

का. अ. 2327--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स बी. न. साहा एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, पोस्ट पाकुर (सन्थाल पारगना) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, प्रमुख, में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद के पंचाट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 4-8-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2327.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. B. N. Saha and Co., Pvt. Ltd., P.O. Pakur (Santhal Parganas) and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th August, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 80 of 1983

PARTIES:

Employers in relation to the management of Messrs B. N. Saha and Company at and P.O. Pakur (Santhal Parganas).

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri K. Mondul, Advocate.

For the Workmen—None.

STATE: Santhal Parganas. INDUSTRY: Stone.
Dhanbad, the 29th July, 1987

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour has, by Order No. L-26011/7/83/D-III(B) dated, the 9th December, 1983, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

“Whether the action of the management of Messrs B. N. Saha and Company (Private) Limited, Mine owners, Pakur (Santhal Parganas) in stopping from work with effect from 5th February, 1982 the following

workers employed in their stone quarries, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?”

S.I No. Name of workman

1. Shri Agijul Seikh, Miner.
2. Shri Siddique Seikh, Miner.
3. Shri Naimuddin Seikh, Miner.
4. Shri Raju Seikh, Miner.
5. Shri Soharab Seikh.
6. Shri Khalil Seikh, Earth-Cutter.
7. Shri Zafol Seikh, Earth-Cutter.
8. Shri Chakku Seikh, Earth-Cutter.
9. Shri Dukhu Seikh, Earth-Cutter.

2. The case of the management of Messrs. B. N. Saha and Company (P) Limited is as follows:

The workmen concerned were never worked as workmen under the company and there was no relationship of employer-employee between the company and the concerned workmen. The workmen concerned did not raise any demand prior to raising the dispute and hence the reference is not legally maintainable. The union styled ‘Santhal Pargana Zila Mines & Quarry Worker’s Union, Pakur (Santhal Pargana) (Bihar) did never function in the mines of the company and the said union is not a registered union also. Accordingly it has been prayed that the present reference be dismissed.

3. The case of the concerned nine workmen, as appearing from the terms of reference, is as follows:

The concerned nine workmen were workmen under the management of Messrs B. N. Saha and Company (P) Ltd., Pakur, in different capacities, some as miners, some as earth cutters and one as an ordinary workman as detailed in the schedule. The management, without any reasonable cause or excuse, stopped them from doing any work in their stone quarry with effect from 5th February, 1982. In the circumstance the concerned workmen pray that they be reinstated in the services with effect from February, 1982.

4. The management has filed written statement in the case, submitted an affidavit affirmed by Shyamal Kumar Saha, Manager of Messrs B. N. Saha & Company (P) Ltd. and examined also Shyamal Kumar Saha at the time of hearing.

5. It is the case of the management that Santhal Pargana Zila Mines & Quarry Worker’s Union, Pakur, did never function in the mine owned by M/s. B. N. Saha and Company (P) Ltd., Pakur and that the union is not a registered union. MW-1, Shyamal Kumar Saha, has stated in his evidence before this Tribunal that the union of Santhal Pargana Zila Mines & Quarry Worker’s does not operate in the company and that no workman of the company is a member of the union. In its affidavit also Shyamal Kumar Saha has vouched for this fact. There is no evidence on record to displace the testimonial value of his deposition. That being so I come to the conclusion that the union styled ‘Santhal Pargana Zila Mines & Quarry Worker’s Union, Pakur, did not function as an union of the workmen of M/s. B. N. Saha & Co. (P) Ltd., Pakur and that the union is not a registered union. It follows therefore that the present dispute raised by the concerned union is not maintainable because the workmen of the company as aforesaid are not members of the said union nor have the workmen, either individually or collectively, authorised the union concerned to raise the present dispute.

6. It has been contended by the management that the nine workmen concerned were not the workmen of the company. On the other hand, the workmen concerned have asserted that they are workmen of the company and engaged, some as miners, some as earth cutters and one as an ordinary workman. But the workmen concerned have laid no evidence in support of their contention that they were workmen of the company. On the other hand, MW-1, Shyamal Kumar Saha Manager of the company has asserted that none of the concerned workmen ever worked in the company either as miners or as earth cutters or an ordinary workman. His affidavit also buttresses this position. That being so I cannot but conclude that the concerned nine workmen were never the workmen of the company engaged in the capacity of either miners or earth cutters or ordinary workman.

7. In the context of the findings of facts that the concerned workmen were never worked in any capacity under the management of M/s. B. N. Saha & Co. (P) Ltd., Pakur, the question of their being stopped from work by the management with effect from 5th February, 1982 does not arise. Hence it must be held that the concerned nine workmen never worked as workmen under the management of M/s. B. N. Saha & Co. (P) Ltd., Pakur (Santhal Pargana) (Bihar) and so the question of their being stopped from work with effect from 5th February, 1982 does not arise. Accordingly an award is passed. In the circumstance of the case parties to bear their own costs

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. L-26011/7/83-D. III(B)]

का. आ. 2328. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947, का. 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजकुमार स्टोन नवारी बाड़ी, (जिला सुरत) ने प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पवाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 3-8-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2328.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajkumar Stone Quarry, Vadi (Distt. Surat) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1987.

BEFORE SHRI N. A. CHAUHAN, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
AHMEDABAD

Ref. (ITC) No. 5 of 87

ADJUDICATION

BETWEEN

Rajkumar Stone Quarry, Vadi, District Surat.

, First party

AND

The General Secretary, Maha Gujarat Khan Udyog Kamdar Singh, Congress Bhavan, Soni, Falia, District Surat

Second party

STATE : Gujarat

INDUSTRY : Ahmedabad.

In the matter of termination of services of Shri Manubhai M. Vasava w.e.f. 1-11-83.

AWARD

This reference under section 10(2A)(1) (d) of the I.D. Act, 1947 has been referred on behalf of the Central Gov-

ernment by the Under Secretary, Ministry of Labour, vide its Order bearing No. L-29012/63/84-D.II(B) dated 12th January, 1987 for determination of the industrial disputes mentioned therein between the parties. The dispute referred is :

"Whether the action of the management of Rajkumar Stone Quarry, Wadi, Dist. Surat, in terminating the services of Shri Manubhai M. Vasava w.e.f. 1-11-1983 is justified? If not, to what relief the workman is entitled and with what effect?"

2. The Order of reference shows that the order of referring the dispute to this Tribunal was communicated by the Under Secretary, Ministry of Labour, Government of India to the parties, and the second party was informed to file the statement of claim with relevant documents, within 15 days from the receipt of order of reference and also to forward the copy thereof to the opposite party. In spite of that the second party at whose instance the reference was made by the Government did not bother to file any statement of claim, but even then this Tribunal called upon the second party to file the statement of claim on or before 13th March, 1987 and to inform the first party about the same. The second party in spite of service of the aforesaid notice did not remain present. The first party had remained present and given application at Ex. 2, that unless a statement of claim is given by the second party nothing can be done by them. In the interest of justice the matter was adjourned and the second party was served with notice dated 16th April, 1987 by Regd. A.D. to appear before this Tribunal on 24th April, 1987. In spite of the service of aforesaid notice (Ex. 3) vide Regd. A.D. slip at Ex. 5, the second party did not bother to file the statement of claim. Still however in order to give one more chance the matter was adjourned to 23rd June, 1987. Even on that date the second party did not appear and file any statement of claim. The first party also did not appear before this Tribunal.

Thus it appears that the second party at whose instance this reference is made is not interested to prosecute the demand made and therefore the demand made in this reference requires to be disposed of as not pressed. Accordingly, I pass the following order.

ORDER

This reference is rejected for want of prosecution by second party at whose instance this reference was made. Considering the facts there shall be no order as to the cost of this reference.

Ahmedabad, 2nd July, 1987

N. A. CHAUHAN, Industrial Tribunal
[No. L-29012/63/84-D.II(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

